पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com
Cell: +91 9425125569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 12 अंक 36 प्रति सोमवार इंदौर, 16 से 22 अप्रैल 2018 पृष्ठ 16 मूल्य 2/- रुपए

रूस और चीन की जुगलबंदी... ब्रिटेन और अमेरिका के विनाश व विश्व पर वर्चस्व का मंसूबा

पुतिन व झी ज़िनपिंग की जोड़ी ने छल, बल, दल व दम से संविधान बदल जालसाजी से सत्ता पर किया कब्जा

दोनों धूर्त ही मिलकर तीसरे विश्व युद्ध का रंगमंच तैयार करेंगे, दोनों की दोस्ती भारत के लिए भी घातक होगी

रूसी पुतिन के जन्म से ही केजीबी का जासूस रहा है, इसलिए वह बहुत धूर्त, मक्कार, चालाक और चतुर है, फिर उन्होंने रूस के पूरे संविधान को बदलकर धोखाधड़ी से रूसी शासन पर कब्जा कर लिया, वह अपने देश में सन 2000 से कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री बन, सत्ता पर अजगर की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है और अपनी धूर्तता से अपने सहयोगियों को मोटा लाभ पहुंचा कर कर जो कि उसी के साथ पूर्व में उसके सहयोगी रहे हैं उनको अपना मोहरा बनाकर सत्ता को हांक रहा है। 76.5% वोटिंग में जालसाजी से जीतकर सत्ता पर पुनः कुंडली मारकर बैठ गया। यथार्थ में वह लोकतांत्रिक मूल्यों की देखरेख नहीं कर रहा है। बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ सिध्द कर वह लोकतांत्रिक पंडित का केवल दिखावा कर रहा है। वह आखिरी चुनाव कैसे जीता, यह दुनिया अच्छी तरह से जानती है। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, सभी में सत्ता हथियाने के लिए खुलकर जालसाजियां, ब्लैक मेलिंग और अपने सहयोगियों को मोटा धन खिलाकर सत्ता हथियाई गई है जनता की इच्छा के विपरीत वे सत्ताधीश बन बैठे हैं छल, बल और धन के दम पर केवल अपनी मौज मस्ती अय्याशी और वर्चस्व के लिए। निसंदेह चीन और रूस में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण 99% सच कभी सामने नहीं आ पाता। जबकि दोनों ही देशों में जनता की आवाज कुचली जा रही है।निसंदेह दोनों ही देशों ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किया है। परंतु जनता की आवाज पूर्णता शासक वर्ग सुनता भी नहीं और करता भी नहीं इसलिए स्वभाविक है कि जनता का दम घुट रहा है और शासक अपनी इच्छाएं शासन तंत्र के माध्यम से जनता पर थोपी जा रही हैं बेशक यही कहानी भारत की भी हो रही है वर्तमान में। यहां भारत में भी पूंजी पतियों की कठपुतली बन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जनता पर भारी आतंक का तांडव मचाते हुए कभी नोटबंदी करता है कभी जीएसटी लादता है,जनता को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने और करने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से उनकी अपनी बचतों, रहन सहन, बातचीत और लेनदेन पर भी निगरानी रखने के लिए आधार कार्ड को उसके मोबाइल से बैंक खातों से लेनदेन से जोड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से अपनी इच्छाएं जनता पर थोपने की विवश करता है। चीन में तो हालात यह है कि वहां पर मजदूरों से 10 से 14 घंटे काम लेकर जिस तरीके से उन्हें मानसिक व शारीरिक तरीके से घोर शोषण कर समय पूर्व मौत की ओर धकेला जा रहा है और सस्ता, स्तरहीन व अविश्वसनीय माल बनाकर पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। (शेष पेज 12 पर)

जहां जहां चरण पड़े दुष्टन के, वहां वहां बंटाधार... गुजराती डकैत पूंजीपतियों के रखैल मोदी का बजट 18-19

पूंजीपतियों के लिए लूट की पूरी छूट और आमजन के लिए शोषणकारी बजट

वर्तमान में मोदी और उसके धूर्त वकील अरूण चीटली ने जो बजट पेश किया है उसमें केवल अपने खास मित्रों अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, आईटीसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के लिए सरकार ने ही सारा कार्य उनके मोटे लाभ के लिए किया गया है आम आदमी के लिए राहत की उसने कोई व्यवस्था नहीं की। इसके चलते उसने आम गरीब मजदूर वर्ग के शोषण और उसकी गाढ़ी कमाई को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लुटवाने की व्यवस्था अवश्य कर दी गई। मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की कि आंकड़ों की बाजीगरी कर बजट को आकर्षक बनाने की नाकाम कोशिश की। करों में छूट पूंजीगत लाभ का फायदा भी केवल कारपोरेट सेक्टर को ही दिया गया जिससे आम गरीब से लूटा गया धन बड़ी पूंजी पतियों की जेब में ही पहुंचेगा आम मध्यम वर्गीय को न तो आयकर में छूट दी गई नहीं भवन निर्माण, बच्चों की शिक्षा हेतु फीस, स्वास्थ्य खर्च आदि में कोई छूट का प्रावधान नहीं दिया गया। (शेष पेज 12 पर)

मध्य प्रदेश सरकार का बजट 18-19: फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी और भ्रष्टाचार से लूट व कमाई का बजट

मुख्यमंत्री शिवराज का अंतिम बजट किसानों को छलावा और जनता से लूट की तैयारी

82% करों से लूटा धन 4 लाख कर्मचारियों के वेतन भत्तों पेंशन और कर्ज के ब्याज भुगतान में चला जाएगा

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले 12 सालों में केवल मीठे झूठे वायदे कर बिजली, पानी, सड़कों पर लूट के साथ पेट्रोल डीजल व रसोई गैस में भारी भरकम टैक्स लादकर चारों तरफ से दोनों हाथों से लूट रही है। वैसे भी मध्यप्रदेश में भारत व दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली और डीजल पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा महंगे बेचकर लूट और भ्रष्टाचार का तांडव मचा रही है। झूठे दिखावे और प्रसार माध्यमों में जन धन से अपनी वाह वाही व उनकी प्रशंसा करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश सरकार की भाजपा में जब तक राघव जी वित्त मंत्री थे तब तक मध्यप्रदेश सरकार का बजट और वित्तीय स्थिति काफी संतुलित थी (शेष पेज 13 पर)

दुनिया का सबसे बड़ा ठग Google

जालसाज, समय की बर्बादी का कारण

खोज करने को ढूंढने वालों के डाटा पर न केवल निगरानी वरण डाटा की बिक्री से भी अरबों रु की आय

वर्तमान में भारत में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विभिन्न विषयों खोज के लिए उपयोग किए जाने वाला व चलने वाला सर्चइंजन है। गूगल जिसनेबहुत कम समय में बहुत बड़ा और लंबा दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार इंटरनेट पर फैला दिया। साथ ही उसके अंदर उसने इंटरनेट की दुनिया के लगभग 400 करोड़ व्यक्तियों के डाटा पर कब्जा कर लिया। जिसमें उसके मोबाइल नंबर, से की गई बातचीत, उसके द्वारा साइट को चलाने पर, किसी भी तथ्य की खोज करने, किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जानकारी एकत्रित करने और व्हाटसअप चलाने पर संदेश भेजने, प्राप्त करने, किसी भी भुगतान या बैंक खाते को चलाने, मोबाइल के माध्यम से खरीदी बिक्री करने आदि के सारे डाटा यह व्यक्तिगत स्तर पर तो एकत्रित करने के साथ उन्हें विभिन्न दुनिया की राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने साझा करने का काम भी करता है और उससे अरबों रुपए की मोटी कमाई करता है शायद यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इसके माध्यम से गूगल दुनिया के अधिकांश उपभोक्ताओं की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखकर यह डाटा न केवल सरकारों विभिन्न विभागों, पुलिस केंद्रीय जांच ब्यूरो, विशेष जांच दल, को, गुप्तचर एजेंसियो, ऋण बांटने वाली एजेंसिओं, बैंकों, बीमा, कंपनियों से लेकर, व्यावसायिक संस्थानों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कंप्यूटर पर काम करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनीयों, यूटयुब के साथ ही सीधे ही डाटा को उपलब्ध करवा कर उन्हें व्यवसायिक स्तर पर यथार्थ में जासूसी का अवसर प्रदान करता है जो की अत्यधिक घातक होने के साथ दुनिया के अधिकांश उपभोक्ताओं की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहां है। जिस पर सरकारी मूल रूप से भारत सरकार का कोई नियंत्रण न होने के साथ,विशेष दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती जबकि यह भारतीय सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कानूनी दंडनीय अपराध है। (शेष पेज 14 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

डर दुनिया के संचालन की कुंजी

प्रकृति का बनाया हुआ डर प्रकृति के स्वसंचालन के लिए आवश्यक था परंतु सत्तधीशों के लिए अपनी मौज मस्ती का हथियार बन गया। प्रकृति ने स्वयं हीं अपने स्वचालित संचालन के लिए डर की अनुभूति का निर्माण किया। यह अनुभूति न केवल मानव सभ्यता के विकास के साथ बढ़ती गई वर्णन यह अनुभूति प्रकृति ने सभी जीव धारियों को भी दी। ताकि प्रकृति का संचालन अपने आप ही सुचारु रुप से चलता रहे। जैसे कि चूहे को नियंत्रण में रखने के लिए बिल्ली बनाई, बिल्ली को नियंत्रण में रखने के लिए कुत्ता और कुत्ते को नियंत्रण में रखने के लिए शेर बना दिया और शेर को नियंत्रण में रखने के लिए मानव बना दिया परंतु यहां उसने अवसर का प्रयोग किया कि जिसको जैसा अवसर मिले वह उसका वैसा सदुपयोग कर ले जैसे कि शेर को मौका मिले और मानव सचेत व संपन्न न हो तो शेर मानव का शिकार कर ले मौका मिले तो वह शेर को पिंजरे में बंद कर ले उसका शिकार कर ले या उसको बस में कर अपनी तरह से उसका सर्कस करवा दे।

मानव सभ्यता में भी डर का भारी महत्वपूर्ण प्रभाव है। मानव को शैशव कॉल से ही डर की अनुभूति ने हीं जिसमें मौसम व जंगली जानवरों के डर से उसने पहले गुफाओं में, फिर अपनी समझ और क्षमताओं का विकास कर घास फूस की झोपड़ियों में, फिर मिट्टी के, फिर विकास के साथ ईट के घरों में रहना शुरू किया। धीरे-धीरे समझ के साथ डर की भी अनुभूति बढ़ती गई। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही उसमें डर के कारण समूह में रहने की प्रवृत्ति बढ़ी जिससे समाज का निर्माण हुआ। और समाज में रहने के लिए और उस को सुचारु रुप से चलाने के लिए राजाओं व लोक प्रशासन का विकास हुआ। यही प्रशासन व समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून का विकास हुआ। ये नियम व कानून समाज को सुचारु रुप से चलाने के लिए बनाए गए थे। न की जनता को लूटने के लिए और धमकाने का हथियार के रूप में उपयोग क्यों जाने लगे । पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यथार्थ में ये लूटने के, जनता को डराने धमकाने, व्यवसाय चलाने और अपने तरीके से लूटने व सत्ता चलाने के हथियार बन गए। निःसंदेह अनादि काल से जिसकी लाठी भैंस वही चराएगा कि अवधारणा आज वर्तमान में भी उतनी ही सफल और सक्षम है। जितनी अनादि काल से थी अब लोकतंत्र में सक्षम पूंजीपति सत्ता को बनाते हैं । फिर सत्ताधीशों को नचाते हुए, अपने मनचाहे तरीके से कानून बनवाते हैं। ताकि जनता को आसानी से अपनी तरह नचाते हुए अपना माल अपनी मनचाही कीमतों पर अपनी तरह से बेच कर जनता को लूटा जा सके। विश्व स्तर पर यूरोप के विश्व व्यापारिक संगठन या घाघ पूंजीपतियों के विश्व व्यापार बिगाड़ो और सत्ताधीशों को पहले विकास के नाम मोटा कर्ज देकर उन्हें भ्रष्ट बनाया जाता है, फिर खरीदकर अपने तरीके से कानून बनवाकर लादे जाते हैं। अपना कानून बन जाने के बाद अपना माल बेचने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र जिसमें पहले बीमारी फैलाओ, फिर मोटे कमीशन पर अपनी दवाई बेंचों, इसी प्रकार अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकवाद को पाल कर आतंकवादी गतिविधियां चलवाई और पूरे दक्षिण एशिया में अपने सारे समय बाधित हथियारों जिसमें हथ्वलित छोटे हथियारों यथा बंदूकें, रिवाल्वर,से लेकर टैंक तोप, मिसाइलें लड़ाकू विमान पनडुब्बियां और जहाज तक बेचे इससे अपनी अर्थव्यवस्था चलाई यह सब के पीछे डर ही था। अर्थात पहले सत्ताधीशों को छल, बल, धन से खरीदो, फिर कानून बनवाओ, फिर कानून का, डर पैदा करो फिर व्यवसायिक लूटपाट करो। जैसा कि भारत में 1965 के बाद हर कानून विदेशी पूंजीपतियों और सत्ताधीशों के इशारों पर भारत में सत्ताधीशों को खरीदकर लागू किया गया जिसमें बीज अधिनियम 1967, कीटनाशक अधिनियम 1968, से लेकर भारत में 2000 तैयारी की गई, और जब कांग्रेस को लाखों करोड़ का धन मिल गया तो तैयार किया गया और लगाया गया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, जिसके अंतर्गत यह तैयारी थी कि कानून के बल पर, पहले किसानों की फसलों को खेतों से सीधे ही 10:00 20% लागत पर खरीदने के लिए विवश किया जाए, किसानों के कर्ज में डूबने पर, किसानों से उनकी पूरी जमीन छीन कर सारी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस पर अपनी तरह से ही खेती कर देश की सवा सौ करोड़ जनता को अपने तरीके से निचोड़कर, दाने दाने के लिए मोहताज बना कर, गुलाम बनाएं और भिखारी बनाकर सड़कों पर छोड़ दें, जिसकी व्याख्या समय माया ने हीं, सर्वप्रथम कर, उस कानून को लगने से सन 2011 तक रोके रखा, और भारी बदलाव के बाद ही लागू किया जा सका, इसी प्रकार भुखेरे जन पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही, अपनी साख जमाने, चीन से डर के चलते, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से ही पुराने हथियारों का कबाड़ा भी 10 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा हैं।

लगभग 10000 करोड़ अरब देसी विदेशी कंपनियों से लेकर उनके लाभ के लिए 2017 में लगाया गया माल एवं सेवा कर या मसक दे जनता को, और भर दे पूंजी पतियों को, लगाया गया उसके पीछे भयंकर दहशत या डर देकर छोटे व्यापारियों, उद्योगों को खत्म करने और सारा व्यवसाय बड़े पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी कर दी गई ताकि वे देश के अंदर एकाधिकारी व्यवसाय कर, पहले छोटे व्यवसाइयों और उद्योगपतियों को नष्ट करें फिर अपने तरीके से आमजन को लूट कर सत्ताधीशों को लाखों-करोड़ों का का मासिक टुकड़ा डालते रहें। यह सब डर का ही परिणाम था कि लालची नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है। बिना धन चुनाव नहीं लड़ा जा सकता पूंजीपति उसे धन टुकड़े डालकर, चुनाव लड़ने में मदद करता है चुनाव जीतने पर फिर उसे जनता को लूटने के षड्यंत्रों अंतर्गत कानून बनवा कर डर दहशत के दम पर लागू करवाता है और अपनी लूट के ईच्छा को पूरा करवाता है जनता बीच में पिसती रहती है।

वर्तमान में भी जो जितना ज्यादा समझदार और शिक्षित होता है, वह उतना डरपोक भी होता है। वह कानूनों को समझता है। और सत्ता धीशों की कठपुतली बन नाचता रहता है। जैसे देसी मोदी जो अशिक्षित होने के कारण, आसानी से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों के लाभ के लिए, उनके इशारे पर देश की 130 करोड़ जनता को नोटबंदी कर चौराहे पर भूखा मरने के लिए खड़ा कर देता है। सैकड़ों लोग लाइन में खड़े खड़े मर जाते हैं 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं पर उन भूखो को सत्ता के मद में सब कुछ अच्छा लगता है जनता के विरोध करने पर उस पर अत्याचार करने, डर पैदा करने पुलिस के डंडे बरसाए जाते हैं। गिरफ्तारियां की जाती है। शायद डर का यह विवरण अत्यधिक लघु रूप में है। इस प्रकार डर न केवल प्रकृति का वरन पूंजीपतियों को, सत्ताधीशों को, जनता को, हाँकने, लूटने का हथियार है।

बैंक अधिकारियों ने सुरा सुंदरी भोग, मोटा कमीशन हजम कर बांटे लोन, अब भेजो जेल

जन धन हजम करने कानून की अपेक्षा जब्त करो, पूंजीपतियों की संपत्तियां जब्त कर, करो सलाखों के पीछे

पूंजी पतियों की रखैल मोदी, बैंकों में जमा गरीबों का धन हजम कर रक्तपान मत करो। पूंजी पतियों से देश की संपत्ति जप्त कर वसूली करो। बैंकों का स्टाफ घोर मक्कार घमंडी और बत्तमीज होता है। ग्राहकों को जानवरों की तरह हांकत्ते हैं। यह सच हर शासकीय और निजी हर वित्तीय संस्थान का है

भारत में आजादी से पूर्व अधिकांश वित्तीय संस्थानों बैंक निजी पूंजी पतियों के थे जिसमें बैंक ऑफ इंडिया बिरला का यूनियन बैंक टाटा का था इसी प्रकार दूसरे पूंजीपतियों के भी अपने अपने बैंक थे इस में जनता का पैसा लेकर वे अपने उद्योग में उसका उपयोग किया करते थे। जिसके कारण स्व. इंदिरा गांधी ने 14 जुलाई 1969 को अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी। राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों में जमा पूंजी का उपयोग देश के अधिकांश उद्योगों में किया गया। जिससे उत्पादकता बढी, देश में छोटे उद्योग का विकास हुआ। साथ ही बैंकों में जनता का विश्वास भी बड़ा और इसके कारण बैंकों में आम नागरिकों नहीं पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया था।इसे बैंकों में जमापूंजी की बाढ़ आ गई। स्वभाविक था बैंक में बैठे अधिकारियों कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बदतमीजीया और घमंड भी बढ़ा।

भारत में 2014 के चुनाव में जिस तरह से मोदी ने सत्ता हथियाने के लिए प्रसार माध्यमों, जिसमें TV चैनलों, हर दिन एक से 2 घंटे के विज्ञापन स्लोट दिए जाने, दैनिक समाचार पत्रों को 4 से 6पेज के, हर दिन रुपए 10 से 20 हजार करोड़ के विज्ञापन, पत्रिकाओं को, 2-4 पेज के के साथ फेसबुक, ट्विटर को हजारों करोड़ रुपए देकर, चौबीसों घंटे लगातार अपने भुगतान किये कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी तारीफों के संदेश देश के 20 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को पहुंचाने ईमेल, वाट्सएप, मोबाइलों पर लगातार संदेश भेजने के लिए भी हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा, मोदी के द्वारा ली गई 800 से ज्यादा चुनावी सभाओं पर भी कम से कम रुपए एक लाख करोड का खर्चा आखिर कहां से आया था, जिसमें 1-1 सभा में मैं रुपए 100 से 200 करोड़ खर्च किए जाते थे, आधुनिक मंच सज्जा, लाखों लोगों की भीड़ को लाने के लिए, परिवहन और प्रति व्यक्ति रुपए एक से 10000 तक का भुगतान, आदि के उपयोग के लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंदे के रुप में वसूले थे उससे यह स्पष्ट था की यह धन कहीं ना कहीं बैंकों में जमा जनता का ही धन है। स्वाभिवक था जिन धूर्त पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से यह धन लिया गया है। उसके बदले में मोदी कहीं ना कहीं जनता को लूटवा कर उन सबका मोटा फायदा करवाएगा और उसने नोटबंदी, माल व सेवा कर, लाद कर उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचाया। साथ ही उसने विदेशियों को देश में सौ परसेंट विदेशी निवेश की छूट देकर जनता को लुटवाने की और देसी उद्योग-धंधों बर्बाद करने, करोड़ों को बेरोजगार करने की पूरी तैयारी उसी चंदे के लिए की ।इसी के साथ यह भी स्पष्ट था कि जिन पूंजीपतियों ने बैंकों से जिसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इंडियन टोबेको कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, जेपी एसोसिएट्स, के साथ हजारों बड़े व्यवसाई होने का पाखंड करने वाले और बैंकों के धन से बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने व्यवसाय करने का कार्य करते हैं ने हीं मोदी के चुनाव प्रचार की सत्ता हथियाने के लिए यह वित्तपोषण किया था।

बैंकों के हजारों करोड़ लेकर विदेश भाग जाने वालों ने बकायदा बैंकों से बैंकों के नियमों के अंतर्गतजाली दस्तावेजों से जालसाजी पूर्वक बैंक के अधिकारियों से मिलकर ही लोन लिया था। उन्होंने पीछे से डकैती नहीं डाली सामने से इज्जत के साथ लोन लिया। इसे बैंकों ने अपने साधनों के माध्यम से वित्त पोषित किया। आखिर इतनी बड़ी घटना घटी और बैंक में बैठे अधिकारियों को जो कि बहुत ही फूंक फूंक कर ऋण बांटते हैं शासन की योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगारों को लोन देने के नाम पर 2-5 हजार से लेकर 2-5 लाखों रुपए के ऋण के लिए वहां के अधिकारी और कर्मचारी आवेदक से ऋण के नाम पर उसकी सारी संपत्तियां, उसके रिश्तेदारों, माता पिता, दोस्तों आदि तक से जमानत लेते हैं। तब कहीं जाकर उसको चार 6 महीने में ऋण की पहली किस्त हाथ में आ पाती है। बेशक इस बीच आवेदक से कमीशन सुरा सुंदरी आदि तक के भोग की व्यवस्था करवा लेते हैं। जब इतने छोटे से कर्ज के लिए बैंक के अधिकारी इतने सारे प्रपंच करते हैं तो हजारों करोड़ के ऋण के लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं किया होगा। बेशक छोटे खर्चों के मामले में बैंक अधिकारी आवेदकों को ज्यादा परेशान करते हैं जबकि बड़े लोगों के मामले में, बड़े अधिकारी जानते हैं की गिरवी रखी गई संपत्तियां जिनका मूल्यांकन कागजों पर दिखाया गया है। उनकी उतनी बाजार की कीमत होती नहीं है। परंतु वे तो अपने कमीशन, सुरा सुंदरी के भोग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, शासकीय मूल्यांकन कर्ता की जांच रिपोर्ट पर आंख मीच कर विश्वास कर ऋण स्वीकृत करते रहते हैं।यह कहानी पिछले 40 वर्षों से हर बैंक, वित्तीय संस्थान जिसमें न केवल देशी वरन विदेशी बैंक के के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक का भी यही हाल है क्योंकि वहां पर भी सभी मनुष्य ही होते हैं और सभी अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सुरा सुंदरी और कमीशन के लिए आंख मीच कर अपनी नियोक्ता संस्थाओं का धन अपने कानूनों की आड़ में औपचारिकता पूरी करवा कर बांटते रहते हैं।

वैसे सन 1970 के बाद जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों के, अध्यक्षों, प्रबंध संचालकों, मंडल सदस्यों से लेकर महाप्रबंधकों शाखा प्रबंधकों तक की नियुक्ति पर, प्रधानमंत्री,उनके सचिव, वित्त मंत्रालय के मंत्री से लेकर प्रधान सचिव, सचिव व अन्य संबंधित अधिकारियों हस्तक्षेप लगातार बढ़ता रहा। ये सारी नियुक्तियां भी पूर्ण रूप से छल, बल, धन और दम के साथ सूरा सुंदरियों के सेवन के दम पर होने लगी। स्वाभाविक था कि जो भी बैंकों और बीमा कंपनियों के शीर्ष पदों के अध्यक्ष और प्रबंध संचालकों से लेकर अधिकारी तक भ्रष्टाचार के शिकंजे में जकड़ कर ही पद प्राप्त कर पाते थे। ऐसा नहीं था, की भूखेरा जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद बीमा और बैंक कंपनियों के कि सभी बड़े पदों पर अध्यक्ष एवं संचालक से लेकर नीचे अधिकारियों तक क्रीम वाली पदस्थापना ऊपर मुफ्त में नियुक्ति की जाने लगी वरन मोदी सरकार के आने के बाद इन कार्यों में और इजाफा हो गया यहां तक की रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति भी रिलायंस के अंबानी बंधुओं के रिश्तेदार उर्जित पटेल की नियुक्ति जो कि कीनिया का नागरिक है, भी इसी के अंतर्गत की गई है। संपूर्ण भारत में रिजर्व बैंक के गवर्नर के लिए कोई सक्षम नागरिक ही नहीं था। इसलिए किन्याई नागरिक को भारत में लाकर गवर्नर बनाना पड़ा रिजर्व बैंक का, तो बाकी अन्य वित्तीय संस्थानों, बैंकों बीमा कंपनियों में भी हर बड़े पद पर मोटा कमीशन लेकर ही नियुक्ति की जाती है जब यह कान्ड वित्त मंत्रालय से ही चल रहा है, तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बैंकों में बैठे अधिकारी सभी नियम-कानूनों का बारीकी से पालन करते हुए ईमानदारी से कार्य करेंगे आखिर उन्होंने जो मोटा धन पद की प्राप्ति के लिए निवेशित किया है। उसकी वसूली तो कहीं ना कहीं से इसी प्रकार जालसाजी पूर्ण तरीके से कर्ज बांटकर कमीशन बटोरकर ही की जा सकती है। फिर वित्तीय संस्थानों में चपरासी से लेकर बाबू अधिकारी अधिकांश घोर बदतमीज, जालसाज होते हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ तो इन्हीं जालसाजियो से कमाए धन के कारण भारी घमंड में होने के साथ घोर बदतमीज होता है। मैं बैंक में आने वाले हर व्यक्ति व ग्राहक से भारी बदतमीजी से पेश आते हैं और यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जबकि वह व्यक्ति शासकीय योजनाओं के अंतर्गत चालान जमा करने गया, DD बनवाने गया, नोट खुले करवाने, पेंशन लेने व अन्य कार्यों के लिए बैंक में घुसा हो तो वहां का स्टाफ मुख्य रूप से जो कैश काउंटर पर बैठता है बहुत ही बदतमीजी के साथ हर ग्राहको, व्यक्ति से पेश आते हैं।

स्वास्थ्य के नाम निजी व सरकारी चिकित्साल्यों में चारों तरफ गिद्धों का बसेरा, लूट की नौटंकी, डॉक्टर नहीं सफेद एप्रिन के गिद्ध

चारों तरफ चिकित्सा के नाम मची है केवल लूट और लूट

निजी नर्सिंग होम अस्पतालों में निजी में भी डॉक्टर्स केवल मरीज को मरीज नहीं मुर्गा समझते हैं जैसे ही कोई प्रवेश करता है उसे सबसे पहले डराया और धमकाया जाता है छोटी छोटी सी बीमारियों के नाम उसे उससे जांचें एक्स-रे सीटी स्कैन खून, मल मूत्र थूक आदि की जांच के नाम सबसे मोटी वसूली की जाती है, निजी चिकित्सालयों में आदमी अपने मरीजों को लेकर जाता है। ताकि वहां सही तरीके से जांच व सही ही इलाज होगा। परंतु वर्तमान में सभी नर्सिंग होम कसाइयों के अड्डे बन चुके हैं। इसके बारे में विधानसभा लोकसभा तक पिछले कई वर्षो से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टरों की लूट पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। सरकार और राज्य सरकारों की लोकसभा और विधानसभा में भी इस तरीके की अनेक प्रश्न उठाई जा चुके हैं कि यह डॉक्टर नहीं गिद्ध बन चुके हैं जो कि मरीज के चिकित्सा के नाम बेइंतिहा जांच के नाम पर वसूली करते हैं । मरीज व उसके परिजनों को कसाइयों की भांति लूटा जाता है।। सरकारी चिकित्सालय में भी मरीजों को जाचो के नाम पर बाहरी एक्स-रे, पैथोलॉजी, ईसीजी, एम आर आई आदि के लिए बाहर भेज कर बाहर की पैथ लैब, एक्स-रे सेंटर, ब्लड बैंक आदि में जम कर वसूली कर 80% तक कमीशन सरकारी डॉक्टर वसूलते हैं। सरकार से प्राप्त दवाइयां इंजेक्शन व अन्य चिकित्सा सामग्री, मरीजों को उपलब्ध करवाने की अपेक्षा उन्हें लिख कर पर्ची पर बाहर से खरीदने के लिए बोला जाता है। यह हाल न केवल मध्य प्रदेश के वरन देश के सभी राज्यों के सभी जिलों के सरकारी चिकित्सालयों का है। हर जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मोटी कमीशन पर औषधियां व अन्य चिकित्सा सामग्री खरीदते हैं। जब उनसे सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी जाती है। तो जानकारी देने की अपेक्षा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से भारी भरकम राशि की मांग कर आवेदक को डराया धमकाया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास इंदौर से जानकारी मांगने पर जिन्होंने पत्रों का जवाब ना दिया बाद में अपील लगाने पर संयुक्त संचालक इंदौर उज्जैन निशुल्क जानकारी देने के आदेश दिए तो देवास इंदौर उज्जैन धार आदि जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी ही नहीं उन्हें इन हरामखोरों को भरी डर था कि जानकारी देने पर इनका सारा सच सामने आ जाएगा अधिकांश जिलों में हर वर्ष करोड़ों रुपए की दवाई औषधियां इंजेक्शन शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले अन्य सामग्री की भारी खरीद विषय 20 से 40 परसेंट तक की कमीशन पर खरीदी जाती है परंतु गांव देहात से लेकर शहरों के मध्य विभिन्न प्रकार की मराठी में बीमारियों के मरीज चिकित्सा हेतु जब सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं तो पहले तो डॉक्टर ही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते क्योंकि वह सरकारी अस्पतालों चिकित्सा महाविद्यालय आदि के आसपास बसी हुई निजी नर्सिंग होम अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने जाते हैं और वहां से मोटा कमीशन और पारिश्रमिक पाते हैं इसलिए कभी कभी भी सभी सरकारी डॉक्टर्स समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते नहीं पहुंचते और समस् और समय से पूर्व सरकारीअस्पतालों से चिकित्सा महाविद्यालय उसे गायब हो जाते हैं ताकि आस पास बसे निजी चिकित्सा केंद्रों में अपनी सेवाएं देकर मोटापा की चमक प्राप्त कर सकें यही कारण है कि ऐसे सभी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम करते समय सरकारी औषधियां सामग्रियां वहां के बीमारों को उपलब्ध नहीं कर पाते और गरीब मरीजों उनके परिजनों हर चीज बाहर से खरीदने के लिए बोलते हैं दूसरी और विश्व कोशिश में भी रहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में पहुंचे हुए मरीजों को जानबूझकर जाटों के नाम पर जिसमें रक्त मल-मूत्र थूक एक्स-रे एम आर आई, ईसीजी सीटी स्कैन आदि के लिए जानबूझकर सरकारी पैथ लैब एक्स रे मशीन एम आर आई सीटी स्कैन मशीनों को खराब कर दिया जाता है। ताकि आसानी से मरीजों को निजी जांच केंद्र को भेजकर मोटा कमीशन वसूल किया जा सके. यही हाल गर्भवती स्त्रियों को सिजेरियन के नाम पर निजी चिकित्सा केंद्र में भेजकर करवाई जाती है और उसका धन शासन के खाते से निजी चिकित्सा केंद्र को दिलवाया जाता है। यह खेल छोटे जिलों में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसमें मोटा कमीशन भेजने वाले डॉक्टर से लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी मिलता है इसके नाम पर हर जिले में करोड़ों रुपए का पिछले 17 वर्षो से भारी धन हजम किया जा रहा है जिसमें मोटा कमीशन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में बैठे कर्मचारियों से लेकर अधिकारी को भी प्राप्त होता है. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह संघ और व्यवसाय स्वयं भ्रष्ट है और पुराना पुलिस अधिकारी रह चुका है वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन का स्वास्थ मंत्री होने के नाते हर जिले में मिठाई गई बैठाई गई हर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पदस्थ करने से पूर्व कि मोटा धन करोड़ों में वसूल कर ही बैठता है बाद में मासिक आशिक त्रिमासिक छमाही या सालाना रॉयल्टी भी बसून की जाती है. स्वाभाविक है कि जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी के पद पर बैठा डॉ डॉक्टर वसूली शासन द्वारा आवंटित धन जो दवाइयों सभी शल्य चिकित्सा सामग्री, व अन्य अस्पताल में उपयोग की जाने वाली सामग्री की खरीद में भवन के रखरखाव मशीनों की रखरखाव आदि के खर्च में खर्च में से झूठी बिल बना कर और फर्जी बिल बनाकर की बस वसूल की जाती है. और यही धन बाद में संयुक्त संचालक जिलाधिकारी संभागायुक्त से लेकर भोपाल में या राजधानी में बैठे संचालक स्वास्थ्य मंत्री वाह मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाती है यथार्थ शासन के लिए चिकित्सा के नाम पर एक मोटी कमाई का साधन बन चुका है जो कि जहां सारी व्यवस्थाएं संभालने वाले मंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सचिव संचालक मुख्यालय में बैठा हुआ हर कर्मचारी अधिकारी भारी भ्रष्ट और हरामखोर होने के कारण वसूली करके ही जिलों तक धन का आवंटन सामग्री की आपूर्ति वाहन स्वीकृति प्रदान करता है इसलिए जिलों में बैठे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों शक नहीं डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक तक सब देहाती व शहरी गरीब मरीजों से येन केन प्रकारेण सुविधाओं के नाम पर भारी वसूली कर अपनी जेब भरते हैं दूसरी निजी नर्सिंग होम व चिकित्सालय में जो कि यथार्थ में कसाइयों का व्यवसाय बन चुके हैं. जानबूझकर छोटी-छोटी बीमारियों को पहले उल्टी-सीधी दवाइयां देकर बिगड़ा जाता है और उसके बाद में साधारण बीमारी में बीमारों को बीमारों को गहन गंभीर बीमारियों में परिवर्तित किया जाता है उसके बाद शुरू होता है कसाइयों और गिद्धों कि बीमार हूं और उनके परिजनों को लूटने का तांडव फिर हरामखोरों का यह खेल बड़ी बड़ी जांच के नाम पर मोटे कमीशन के लिए बीमारों को पैथोलॉजी, एक्स-रे सीटी स्कैन एम आर आई ईसीजी आदि में 50% तक कमीशन वसूल कर दिया जाता है वह फर्जी जांचे डॉक्टरों के लिए मोटी कमाई साधन बन जाती हैं शासन में बैठे हुए।

पहले तो हरामखोर डॉक्टर और उनके बाबू आवेदन पत्रों का जवाब भी नहीं देते हैं। अपीलों के लगाने पर संयुक्त संचालक महीनों तक अपीलों की सुनवाई नहीं करता।और यदि ज्यादा दबाव डाला जाए तो संयुक्त संचालक कार्यालय निशुल्क जानकारी देने का आदेश कर भेजें तो देवास में सालों से पेंडिंग पड़ी अपीलों की आज तक जानकारी नहीं दी गई।

जब से सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए निजी चिकित्सालय की सेवा को सरकारी खाते से धन देने की घोषणा की है। तब से निजी चिकित्सालय की कमाई का एक बड़ा स्त्रोत गरीब लोगों के अनाप-शनाप बिल बना कर और उल्टी सीधी बीमारी दिखाकर बड़े बड़े मोटे बिल सरकार को भेज दिए जाते हैं। जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर का भी मोटा कमीशन होता है क्योंकि अंतिम स्वीकृति और पैसा स्वीकृत करने वाला जिले का कलेक्टर ही होता है। इसमें भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हर महीने करोड़ों में हजम कर जाते हैं। वैसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास सभी आवंटन जिसमें औषधि अस्पताल सामग्री की खरीद में भी 40 परसेंट तक कमीशन होने के साथ जिले के अंदर कार्यरत सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों में मोटा कमीशन मिलता है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी खाद्य एवं औषधि का भी उपसंचालक होने के कारण हर महीने के लाखों रुपए की कमाई खाद्य एवं औषधि कि निरीक्षकों से भी करता है। यहां तक की वह नमूने लेने की पर्ची के बदले में भी हर पर्ची के सबसे अलग से धन मांगता है। इसके साथ सभी प्रकार की जार्चों के लिए बनाई गई मल मूत्र रक्त एक्स रे आदि की सभी निजी प्रयोगशालाओं से भी मोटा कमीशन मिलता है। सभी निजी चिकित्सक भी उसे और उसके संबंधित कर्मचारियों को महीना बांटते हैं। अर्थात किसी जिले का मुख्य चिकित्सक बनने के लिए पहले करोड़ों रुपए स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव को भेंट करने पड़ते हैं। और फिर आसानी से करोड़ों रुपए की कमाई के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। इसीलिए हर डॉक्टर अपना पैसा छोड़कर शासकीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में अटैच होना पसंद करता है। यथार्थ में सरकारों को चाहिए कि सेना की तरह वह भी हर 3 साल में शासकीय एवं निजी चिकित्सकों की परीक्षा लेकर उनको आगे की चिकित्सा की आज्ञा देनी चाहिए। यदि वे उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाते हो, तो। अन्यथा जो चिकित्सक कभी भी अस्पतालों में बैठकर चिकित्सा ही ना करते हो उन्हें डॉक्टर की उपाधि से हटा दिया जाना चाहिए या जो डॉ इस त्रिवर्षिय परीक्षा में पास ना हो सकें उन्हें भी चिकित्सा परिषद से हटा दिया जाना चाहिए और उनकी प्रेक्टिस बंद कर दी जानी चाहिए। वास्तविकता में भारत में 90% डॉक्टर केवल एक बार पूरा पाठ्यक्रम करने के बाद किसी भी परीक्षा से नहीं गुजरते और वह 5-7 बरसों के बाद जो पुरानी पढ़ाई के आधार पर ही जिंदगी भर जनता को नोचते खसोटते रहते हैं। जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में हर दिन नए बदलाव, नई दवाइयां, नए उपकरण, नई पद्धतियां सामने आती रहती हैं परंतु निजी और शासकीय दोनों क्षेत्र के डॉक्टर बरसों पुराने उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं और जनता को वही एंटीबायोटिक जो कि अब बिल्कुल औचित्य हीन हो चुकी हैं टिकाया करते हैं और अपना धंधा चलता रहता है और तत्काल मरीजों को राहत देकर लंबे समय के लिए बड़ी-बड़ी बीमारियां दे जाते हैं बाद में वह कैंसर, लिवर, किडनी,हृदय रोग, डायबिटीज उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप आदि के गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं जिसमें भी इन्हें मोटी कमाई होती रहती है और जिंदगी भर सामान्य लोग भी इन डॉक्टरों के चक्कर में दवाइयों के ऊपर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

इंदौर महानगर में मेदांता हॉस्पिटल में जिसमें संभागायुक्त संजय दुबे काफी रूचि लेते हैं। पिछले दो 3 सालों से नया खेल चल रहा है यहां का धूर्त डॉक्टर त्रेहान जिसकी नोएडा दिल्ली अहमदाबाद में भी अपनी शाखाएं हैं। किसी भी अधघायल इंसान को पहले उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देना फिर उसके माता पिता पर बैनडेड हो चुका है,दवाब डालकर, तरीके से डरा,धमका, और मानसिक तौर पर इस तरीके से समझा कर कि अब तो यह मर ही चुका है। उस अधघायल इंसान की जिस में भी पूरी जान थी उसके इलाज के विपरीत उसके आंख लीवर दिल किडनी तो करोड़ों में बैचकर मोटा पैसा कमाया जा रहा है। और मीडिया को खरीद कर उसके यथार्थ को छुपा ग्रीन कैरियर बनाने का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल लीवर किडनी आंखें आधी को अहमदाबाद दिल्ली मुंबई आदि में मरीजों को लगाना दिखा कर वाह वाही लूटी जा रही है यथार्थ में यह पूरा षड्यंत्र जिसमें पूरा का पूरा प्रशासन और मीडिया भी शामिल है। जिंदा लोगों को भी ब्रेनडेड बताकर उनके अंगों का व्यापार किया जा रहा है। निसंदेह इसके विरुद्ध सबसे पहले केरल ने हीं कानून बनाया है जिसके अंतर्गत ब्रेनडेड मरीजों को चीरने फाड़ने से पहले या उनके अंगों का अंगदान करने से पहले 4 डॉक्टरों की टीम चेक करेगी जिसेमे ऐक शासकीय डाक्टर होगा। उसके पहले उसके मां-बाप को कोई सलाह मशवरा या दबाव नहीं डाला जा सकता। पर उसके पहले इंदौर में तो 20 से ज्यादा लोगों को इस प्रकार से दुर्घटना में घायल होने पर पूरा ही मार डाला गया। इसके पूर्व में भी चोइथराम हॉस्पिटल में किडनी चोरी कांड और व्यापार कांड सामने आ चुका है। इसकी जांच में उस समय के संयुक्त संचालक डॉक्टर शरद पंडित ने करोड़ों हजम कर लीपापोती कर दी थी। इंदौर शहर अपनी पहचान पूरी दुनिया में ड्रग ट्रायल कांड के बाद जिसे भी दबा दिया गया जिस में भी 2000 लोगों की जाने केवल शासकीय अस्पतालों में ले ली गई थी जबकि निजी में यह आंकड़ा भी पूरे देश में लाखों में था। अध्ययनों को अब जीवित अध घायलों को ब्रेनडेड बताकर उनके अंगों के व्यापार का अड्डा बन चुका है। मैं तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को एक बड़े षड्यंत्र जिसके अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ही अंगदान के इच्छुक लिखवाने का षड्यंत्र उप परिवहन आयुक्त के साथ मिलकर रोक दिया अन्यथा इन हरामखोरो और जालसाजों की तैयारी यह थी यह किसी भी हट्टे-कट्टे का पहले दुर्घटना में घायल किया जाए और उसके बाद उसके कार्ड के लिखे अनुसार उसके मानव अंगों की आसानी से करोड़ों में बैठकर तस्करी की जाए को रोक दिया।

साप्ताहिक समय माया

श्रम मंत्री, प्र.सचिव, सचिव, श्रमायुक्त से निरीक्षक तक पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की रखैल, अवैध वसूली में व्यस्त

कानून की आड़ में श्रमिकों के कल्याण के जिम्मेदार, नियोक्ता से करोड़ों की वसूली व कमाई

सूचना अधिकार में जानकारी न देने पर अपीलीय अधिकारी स्वयं पैरवी करने लगते हैं। जानकारीं न देने के भ्रष्टों को बहानों की कमी नहीं। श्रमिक कल्याण नहीं। घोर भ्रष्ट जालसाज पाठक स्व व वरिष्ठ कल्याण हेतु उपायुक्त, संभाल रहा, 5 पद। डेनिम खरगोन ब्लू डायमंड पीथमपुर जैसी अनेक फैक्ट्रियों के बंद करने में लाखों हजम किए पाठक ने।

मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के मुख्यालय आयुक्त कार्यालय में बैठे आयुक्त लेकर अपर आयुक्त, उपायुक्त,सहायक आयुक्त, व अन्य अधिकारी कर्मचारी जिसको जहां जैसा मिलता है। भ्रष्टाचार का कोई मौका चुकना नहीं चाहता। नोट बंदी, जी एस टी व भुखेरा जन पार्टी की नीति, पूंजी पतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को को खुश करने, अपना मोटा कमीशन वसूलने की नीतियों के चलते अनेकों फैक्ट्रियां और संस्थान जो छोटे, माध्यम स्तर के थे, जहां हजारों मजदूर काम करते थे। घोर मंदी, नगद रोकड़े के अभाव, खरीदी का अभाव के चलते व कानूनी पचड़ों के चलते बंद हुए। जिससे प्रदेश भर में लाखों मजदूर बेरोजगारी का सामना करने को मजबूर हो गए। बेशक बड़े पूंजी पतियों बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व व्यापार शैतान संघ के इशारे पर, भुखेरा जन पार्टी इतने मोटे कमीशन, अपने कमाये काले धन को उपयोग करने पर और ज्यादा लाभ पाने के लिए भी बीसवीं शताब्दी से प्रारंभ हुए श्रमिक आंदोलन और 1920 में स्थापित किये गए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रमिको और उद्योगपतियों के हित मैं लागू किये गये अधिकांश कानूनों का बलात्कार कर या तो समाप्त कर दिया। यह उन कानूनों में परिवर्तन, संशोधन और पूंजीपतियों के हित साधने वाले कानून बना दिए।। ताकि पूंजी और उद्योगपति आसानी से 10 से 14 घंटे काम लेकर भी उसे न्यूनतम मजदूरी भी न दे। आधा काम समाप्त करने, संशोधन और परिवर्तन का अंग्रेजों की रखैल कांग्रेस के कमीशन खोरो ने और बचा खुचा भूखेरे जन पार्टी के गिद्धो ने जनता की कुल आबादी 130 करोड़ अर्थात 60 करोड़ श्रमिको को नोचने और शोषण करने का कर दिया। वैसे तो देश की फैक्ट्रीयों उद्योगों और मिलो के साथ अधिकांश सरकारी विभागों में अब मजदूरों से लेकर कुशल श्रमिकों, वैज्ञानिकों, रसान्यों, इंजीनियरों से डॉक्टरों, शिक्षकों, बाबू, स्टेनो, चपरासी, आदि सब ठेका श्रमिक की तरह ठेके के माध्यम से नियुक्तियां दी जा रही है। इस तरह केंद्र सरकार व सभी राज्यों की सरकारें सारे श्रंम कानुनों को बलाये ताक रख कर न केवल अकुशल, कुशल श्रमिकों के साथ इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षकों, बाबू, लेखाकारों, सिपाहियों, सुरक्षा सैनिकों, कंप्यूटर ऑपरेटर, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, आदि सब की भर्तियां ठेकों के माध्यम से कर उन्हें दैनिक मजदूरी से भी कम वेतन भत्ते देकर कार्य करवाया जा रहा है। सरकारी विभागों में ठेकेदार हर महीने सभी कुशल अकुशल श्रमिकों के वेतन में से 10 से 40% तक वेतन स्वयं हजम कर जाता है। निसंदेह ऐसे सभी ठेकेदार शासकीय कार्यों के ठेके लेने में न्यूनतम मजदूरी के साथ मोटा धन वहां पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को देकर ही वह ठेका प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार न केवल अकुशल श्रमिकों का वरन उच्च शिक्षित कुशल श्रमिकों का भी घोर शोषण किया जा रहा है। इंदौर में ही न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल श्रमिक रु. 280रु./- प्रतिदिन होने के बाद में भी यहां पर कुशल श्रमिकों को भी रुपए 5 से 7000 में काम करना पड़ रहा है, जिसमें 12 से 14 घंटे मजदूरी के बाद, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं। अर्थात यहां तक की सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर पर भी भुगतान नहीं किया जाता। अर्थात श्रम निरीक्षक केवल महीना वसूली कर और अपने वरिष्ठों को खुश कर चुपचाप सब चलने देते हैं। जिस पर श्रम विभाग के क्षेत्रीय श्रम अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अपर आयुक्त से लेकर आयुक्त सचिव और मंत्री तक वसूली कर पहुंचाया जाता है। इसलिए कोई किसी के खिलाफ मुंह नहीं खोलता। इंदौर के पाकीज़ा में ही जिसके शहर में ही 4 बड़े शो रूम है, घोर भेदभाव करते हुए।

क्षेत्र में पंजीकृत न होने, छुट्टी मजदूरी करने के कारण, उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता निसंदेह स्वास्थ विभाग के चिकित्सालय में उन्हें चिकित्सा मिलती है। पर राज्यों व केंद्र के बीमा चिकित्सालय में उनके लिए प्रवेश भी वर्जित है। साथ ही श्रम विभाग में भी ऐसे छुट्टी देनिक मजदूरी करने वालों के लिए कोई योजना नही जैसी बनानी चाहिए। ताकि वह भी बीमारी की हालात में इलाज करवा सकें। ठेले पर फुटपाथ पर सामान बेचने वाले भी स्वरोजगार मजदूर ही है। उन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम वाले खदेड़ते, ठेलें जप्त कर तोड़ देते हैं, पर उन गरीबो जो स्वरोजगारी होकर, जो स्वयं के साथ अपने परिवार और सैकड़ों गरीबों का भी पेट भरते हैं। जो अपने कम पूंजी और साधनों से अपना रोजगार संभालते हुए ईमानदारी से मेहनत और स्वरोजगार करते हैं। जिनकी संख्या अकेले इंदौर में 30 हजार के लगभग प्रदेश में 50लाख के लगभग और देश में 10 करोड़ के लगभग है। पर प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की नजर में जैसे चोर डाकू है। जो सड़कों पर ठेले, गुमटी लगाकर, फुटपाथ पर सब्जी बेचने, व अन्य छोटा-मोटा घरेलू सामान बेचने का काम करते हैं। पूंजीपतियों के अरबों रुपए की लागत के शॉपिंग मॉल्स के लिए बड़ा सिर दर्द हैं और उनकी बिक्री में प्रतियोगी होने के साथ उनके धंधे को चौपट करते हैं इसलिए उन्हें समाप्त करने हतोत्साहित करने, खदेड़ने के लिए लाखों रुपए महीना देकर यह कार्य नगर निगम पुलिस प्रशासन से करवाने के लिए केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा क्षेत्रीय प्रशासन व नगर निगम को निर्देशित किया गया है। जिन्हें दिहाड़ी मजदूरी से थोड़ा उठकर अपनी पूंजी से अपना व्यवसाय अवश्य कर रहे हैं परंतु मजदूरों से ज्यादा मेहनत शारीरिक और मानसिक दोनों ही उन्हें करना पड़ती है। वहां भी खुले आसमान के नीचे पुलिस नगर निगम पालिका के हरामखोर कर्मचारी की वैधानिक और अवैधानिक मांगों को पूरा करते हुए इसके विपरीत वह सब श्रमिक की वैधानिक परिभाषा में नहीं आते। अकेले इंदौर में ऐसे एक लाख से ज्यादा स्वरोजगार मजदूर हैं पूरे मध्यप्रदेश में 50 लाख के लगभग और और पूरे देश में लगभग दो करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार ही और छुट्टी मजदूरी करने वाले मजदूरों के बारे में कोई कानून या वर्तमान में कानूनों में उनकी कोई व्यवस्था या परिभाषा के साथ उनके हितों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवसाय व्यवस्था नहीं है। बेशक रेलवे में कुलियों कृषि उपज मंडियों में हम्माल आदि हैं तो स्वराज्य गारी मजदूर पर उनके लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं दी हैं। परंतु अन्य़ क्षेत्र जो भारत की कुल मजदूर संख्या का 60% जो लगभग 30 करोड़ है!

सरकार ने हाल ही में ऐसे मजदूरों के पंजीयन की व्यवस्था पूंजीपतियों के इशारे पर इस प्रकार की है की 90% ऐसे गरीब दिहाड़ी मजदूर और स्वरोजगारी उनके मानक स्तर में ही नहीं आए और पंजीयन से वंचित हो जाएं। जिसमें ऐसी मजदूर जिनके पास मोबाइल न हो, गाड़ी न हो, ही पंजीकृत किए जाएंगे। जबकि वर्तमान में वयस्क आबादी के के वयस्क 90% लोगों के पास मोबाइल होते ही हैं। चाहे वह दिहाड़ी मजदूर हो या स्वरोजगारी मजदूर। सब मोबाइल रु 200- 500/- का बात करने योग्य रखते ही हैं। परंतु मोबाइल रखने के कारण उन्हें मजदूरों के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार पंजीकृत किया गया। मजदूरों का डाटा एकत्रित कर यह सरकार एक तरफ अपने वोट बैंक, से उन्हें कुछ सुविधाएं देकर अपनी सत्ता की मजबूती का काम करेंगे। दूसरी तरफ पूंजीपति इस डेटा के माध्यम से अन्य व्यवसायिक उपयोग करेंगे पर मजदूरों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलने वाली।

उनके लिए केंद्र व राज्यों के स्तर पर कोई भी भूत वर्तमान और भविष्य के लिए स्वास्थ्य बीमा वृद्धावस्था में पेंशन की तरह कोई सुरक्षा निधि जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी कुछ भी नहीं है। इन सबके पूंजीपतियों के हित साधन हेतु, संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत जिनमें 56 कानूनों का पालन करने की व्यवस्था थी। उसे भी धूर्त पूंजीपतियों के इशारे पर मोटा धन हजम कर भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों जो उद्योग व श्रम विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त के पदों पर केंद्र व राज्यों में बैठे इन हरामखोरों ने धन बांट वहां जमकर अधिकांश श्रम कानूनों की मूल आत्मा श्रमिक कल्याण की हजम कर श्रमिकों के आधे पेट भोजन के साथ जीने व अकाल मृत्यु देने की चीन के श्रमिको की तरह भरी जवानी में सैकड़ों बीमारियों के साथ तड़प कर जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ऐसा नहीं था उद्योगपतियों के हितों के विरुद्ध कानून बनाए थे। यथार्थ में यह संगठन ने श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य का अधिकार देकर यथार्थ में श्रमिकों के सुरक्षा प्रदान कर अधिकतम और अच्छे उत्पादन की व्यवस्था की थी। यदि श्रमिक कुंठित और असुरक्षित होगा तो उद्योगों की सेहत बिगड़ने से कम और घटिया बुधवार उत्पादन होने से टूट-फूट हानि होने से अंत में उद्योगपतियों को ही हानि होने का सामना करना पड़ेगा इन सब नकारते हुए केंद्र व राज्यों ने कानूनों को बदलना वरना इस श्रमिक कल्याण विभाग में भी ऐसे भ्रष्ट शूकरो की फौज मंत्री, आयुक्त, अपर आयुक्त, उपायुक्त से लेकर सब श्रम निरीक्षक तक बैठे हैं। जो श्रमिक कल्याण की अपेक्षा स्वकल्याण मैं ज्यादा विश्वास रखती है। और उसके लिए पूंजी पतियों से उद्योगपतियों से बाकायदा सौदेबाजी कर महीना, वसूल कर श्रमिकों का शोषण होने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि धन, श्रमिक नहीं, उद्योगपति, पूंजीपति देते हैं। इसलिए उनकी सेवा कर नमक हलाली करना आवश्यक है उसमें फिर चाहे श्रम निरीक्षक, श्रम अधिकारी, हो सहायक आयुक्त उपायुक्त अपर आयुक्त, आयुक्त, सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी शामिल हैं।

म. प्र. श्रम विभाग में बैठे जिन गिद्धों ने अपनी कमाई के लिए श्रमिकों का घोर शोषण किया। उसमे वहां पदस्थ लक्ष्मीपति पाठक जो पूर्व से ही कई लोकायुक्त जांचो में उलझा हुआ था। उन्हें प्रधान सचिव अश्विन राय. और मंत्री जो दोनों ही घोर अय्याश होने के साथ ही भ्रष्ट भी है, ने लक्ष्मी त्रिपाठी से मोटा धन लेकर उसे इंदौर उपायुक्त के साथ ही भोपाल का उपायुक्त और 5 पदों पर 5 महत्वपूर्ण जिम्मेदारीयां एक साथ सौप स्थापित कर दिया। जिसमें कल्याण आयुक्त संनिर्माण कर्मकार मंडल, ग्रामीण श्रमिक कल्यााण मंडल, पंजीयक श्रमिक संगठन के साथ इंदौर भोपाल के उपायुक्त के पद पर भी पदस्थ कर दिया हैं। प्रधान सचिव अश्विनी राय और मंत्री न प चौधरी दोनों ही नये मंत्रीमंडल में, नये मंत्री भी सुरा सुंदरी के भारी शौकीन है वही हाल इस उपायुक्त लक्ष्मी पति पाठक का भी है। जिसमें भारी, पाठक अपने दोनों वरिष्ठों को अपनी पूरी तन, मन, धन की क्षमता से सहयोग करते हैं। इसलिए उन्हें एक साथ 6 पदों पर पदस्थ कर दिया गया। 27 जनवरी को 11:35 से 12:30 तक आयुक्त मोहित जैन और पाठक के बीच रिश्वत के पैसे को लेकर भारी तू तू मैं मैं हुई और झगड़ा काफी बढ़ गया। जिसे मजे लेकर सभी आयुक्त कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों अधिकारियों ने देखा। इसमे पाठक ने निमरानी की सेंचुरी डेनिम कंपनी खरगोन से रुपए 25 लाख लेकर 2 हजार कर्मचारियों का 3 करोड रुपए हजम करने में मदद की। इसके रु 5लाख का भुगतान अग्रिकम किया गया। जब तीन माह का वेतन देने की जिम्मेदारी उठी तो 3 करोड रुपए देने की अपेक्षा सेंचुरी डेनिम ने पूरी कंपनी को दूसरे हाथों को बेंच दिया। इससे उसकी पूरी यूनियन को बिना भुगतान दिए श्रमिकों को चलता कर दिया था इसके बाद इस शूकर पाठक ने पंजीयक रहते हुए यूनियन का पंजीयन ही रद्द कर उस को अवैध घोषित करवा दिया यही हाल मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा संगठनों में किया गया और बदले में पाठक ने आयुक्त के नाम पर मोटी वसूली कर हजम किया और आयुक्त को उसका 20% भी नहीं दिया गया जो बाद में तू तू मैं मैं और विवादों का कारण बना।

रु20लाख का भुगतान बाद में किया गया जिसके बदले में पाठक नहीं कंपनी के प्रबंधन को सलाह देकर कंपनी को दूसरे को बेच दिया गया। अग्रिम दिए गए 5 लाख में से पाठक ने जैन साहब को मात्र रु1लाख दिए, रु 2लाख अपनी बेटी के प्रबंधन से कह कर खाते में जमा करवा दिए! अग्रिम भुगतान में पाठक ने मात्र रु 2लाख प्राप्त हुआ दिखलाया जिसका 1 लाख का हिस्सा जैन साहब को दिया गया। जब डेनिम के कर्मचारी कर्मचारियों ने हड़ताल की और मामला उलझा तो प्रबंधन ने आयुक्त महोदय से शिकायत की कि हमने 5लाख अग्रिम इसीलिए दिए थे ताकि मामला आसानी से खत्म हो जाए। बाद में श्रमिक संघ का पंजीयन पाठक निरस्त कर 20 लाख ले लिए उसमें भी पाठक ने मात्र 10लाख रुपए प्राप्त दिखला रु5लाख मोहित जैन को दे दिए गए। इसका भी सच सामने आ गया और विवाद का कारण बना। इसी तरह मध्यप्रदेश में रूचि सोया के छह प्लांट बंद हुए जिसके करीबन 2हजार कर्मचारियों का भी तालाबंदी से पूर्व 3 माह का वेतन हजम करने में भी पाठक ने अपना मोटा कमीशन लेकर भूमिका अदा की इसी तरह पीतमपुर की रोजी ब्लू डायमंड कंपनी जिसमें 800 कर्मचारी थे का भी तीन माह का वेतन न देते हुए पाठक ने वहां पर भी लाखों हजम कर लिए और वह कंपनी भी बिकवा दी। पाठक ने संनिर्माण कर्मकार मंडल का सचिव रहते हुए हाल ही में 10,000 फ्लेक्स ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रुपए 7 करोड़ में बनवाई थी जो मात्र रुपए करोड़ से ज्यादा क्यों नहीं थे। जिन्हें प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में पहुंचाना था अभी तक नहीं पहुंचाई गई। क्योंकि न फ्लेक्स की संख्या थी और न ही उसकी उतनी गुणवत्ता, पूर्व उपायुक्त भोपाल दीक्षित ने उसका भुगतान रोक दिया था परंतु पाठक ने रुपए 3 करोड़ के माल के लिए बारे बारे उसका भुगतान कर दिया। 24 फरवरी 18 को जबलपुर में असंगठित क्षेत्र के 5लाख मजदूरों के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें उन्हें शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जानी थी। यह पैसा संनिर्माण कर्मकार मंडल का था। जिसे किसी भी हाल में किसी अन्य मद पर खर्च नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत पाठक ने रु20करोड इस कार्यक्रम नाम से खर्च कर दिया जिसमें मात्र 30 से 40हजार श्रमिक ही आए थे। स्वाभाविक था की खर्च को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और रु दो करोड़ के काम के रु बीस करोड खर्च दिखाकर हजम कर लिए गए। वर्तमान में संनिर्माण कर्मकार मंडल में लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए का शेष है जिसे केवल संनिर्माण से जुड़े श्रमिकों जिसमें सड़क, पुल, पुलिया निर्माण, भवन निर्माण, तालाब, बांध, नहरे, पाइप लाइन डालने बिछाने मरम्मत करने आदि में जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए यह धन खर्च किया जाना है परंतु इतना सारा धन देखकर पाठक येन-केन-प्रकारेण उस धन को हजम करने के नए नए रास्ते कानून के विपरीत जाकर गैरकानूनी तरीके से खर्च कर अपना मोटा कमीशन हजम कर रहा है। जिस पर तत्काल जांच बैठाई जाकर पुलिस में रिपोर्ट की जाए और पुराने पापों के साथ नए पापों के लिए भी इसे मोटी सजा मिलनी ही चाहिए।

सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी चुनाव कार्य संपन्न करते हैं, तो उनका स्थानांतरण 3 वर्ष बाद क्यों नहीं किया जाता

चुनावी वर्ष में कर्मचारियों-अधिकारियों के फेरबदल से स्थानांतरण करें चुनाव आयोग

सभी अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से जुड़े हुए हैं। सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी व उनके परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं चुनावों को, पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सबका स्थानांतरण होना आवश्यक है। जबकि भाप्रसे आकाश त्रिपाठी, आयुक्त संजय दुबे, निगमायुक्त मनीषसिंह जैसो ने इंदौर में ही 5 वर्ष से ज्यादा पूरे कर लिए।यही हाल पूरे प्रदेश व देश का अधिकरियो कर्मचारिओ को अजगर की तरह लिपटा रखा है। मंत्रियों और वरिष्ठों ने अपनी मोटी कमाई के लिए अधिकारियों को बरसों से एक ही कुर्सी और स्थान पर

चाणक्य ने कहा था सुचारू शासन व्यवस्था के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण नियमित रूप से होते रहना चाहिए प्रशासन और जनता की कल्याणकारी देखरेख बनी रहे निसंदेह यह तथ्य चाणक्य ने ढाई हजार वर्ष पूर्व लिखित है परंतु वर्तमान में भी उतने ही कारगर और आवश्यक है एक भ्रष्टाचार हींन शासन व्यवस्था के लिए जिसने की उस समय थन. वर्तमान में भी शासकीय सेवाओं के लिए शासन की कार्यप्रणाली के दस्तावेजों मै यह उल्लेखित है की हर अधिकारी का हर विभाग में 3 वर्ष में और कर्मचारी, लिपिक वर्गीय से चपरासी तक 5 साल मेंस्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था और हर विभाग का कार्य सुचारू रूप से न्यूनतम जालसाजी और भ्रष्टाचार से संपन्न किया जा सके परंतु वर्तमान में हालात ऐसे हैं प्रदेश के हर विभाग में ना केवल कर्मचारी वर्ण निरीक्षक और अधिकारी भी 10 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर जमा रहकर भारी भ्रष्टाचार और जालसाजी पूर्ण कांडो को करते हुए भारी भ्रष्टाचार से भारी काली कमाई करते हुए जनता को भारी कष्ट पहुंचाते हैं नियमों कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है और स्व लाभ के लिए मनमर्जी से कार्यों को संपन्न किया जाता है।जिससे यथार्थ में वर्तमान और भविष्य की प्रशासनिक कार्य प्रणाली और नियोजन को भारी क्षति पहुंचती है जनता से वसूले गए करो की राशि से यू शासकीय विभाग चलाएं व कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं यथार्थ में उनका पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण विभाग लोक-स्वास्थ्य-यांत्रिकी मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सामाजिक विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, वन विभाग आदि के साथ,सभी नगर निगमों पालिका परिषदों, आदि जन कल्याण से जुड़े विभागों में बैठे कुंडली मारे 20-25 साल तक एक ही स्थान पर जमे कर्मचारी-अधिकारी, शासन के जन धन से वसूली निधियों का जनकल्याणकारी योजनाओं परियोजनाओं में उपयोग करने की आड़ में कार्यों का कागजों पर कार्य संपन्न करने, आधी अधूरी व स्तरहीन सेवाएं देकर, यह सेवा में कटौती कर मोटा धन हड़पने के लिए जालसाजिया और षड्यंत्र रच कर कार्य को लंबित करना, कार्यों के भुगतान में वसूली करना जैसे कांड को अंजाम देते रहते हैं और अपने आकाओं को खुश रखते हुए वसूले हुए धन में से कुछ टुकड़े अपने वरिष्ठों को देकर अपनी जालसाजियों और भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्यों पर वर्षों तक कुंडली मारे बैठे रहते हैं। इस संबंध में अधिकांश पंचायत एवं ग्रामीण विकास में बरसों से एक ही स्थान पर बैठे बाबुओं की फौज अधिकांश कार्यों को कागजों पर ही संपन्न कर अधिकांश धन की बंदर बांट कर हजम कर जाती है जिसके पीछे मूल कारण उन बाबू कर्मचारियों और अधिकारियों का एक ही स्थान पर बरसों से जमे रहना ही सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास में बाधक बनता है जैसे कि स्वच्छता के नाम पर सन 2000 से अभी तक शौचालय, कुटीर आवास योजना, मैं ग्रामीणों के लिए गृह निर्माण, गांव में सड़क निर्माण, नदी-नाले के पाल बंधन, नाली निर्माण में ही जिला पंचायत में बैठे कर्मचारियों की फौज ने हर ग्राम पंचायत की 90 परसेंट परिवारों के यहां कि सत्रह अठारह सालों में 4से 5 शौचालय कोठियों का निर्माण निर्माण फर्जी नामों से करवा कर हजारों करोड़ रुपए का धन हड़प लिया गया, जब की वास्तविक हितग्राही के पास ना तो कुटिया है और ना ही शौचालय फिर भी भुगतान अभी तक नियमित होता रहा ऐसे ही उदाहरण हर विभाग के हैं। तो दूसरी तरफ शासकीय निगरानी व नियंत्रण वाले विभागों में जिसमें पुलिस, न्यायालीन व्यवस्था, कर वसूली व्यवस्था, खनिज, खाद्य एवं औषधि, श्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, आदि निरीक्षण और नियंत्रण रखने वाले विभागों में वर्षों तक निरीक्षक एक ही स्थान पर बैठकर नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को अपनी मासिक वसूली कर सारे कुकृत्य करने के लिए खुली छूट देते रहते हैं। यही कारण है कि पुलिस के भ्रष्टाचारों की रोज नित नई कहानियों से दैनिक साप्ताहिक व मासिक समाचार पत्र-पत्रिकाएं भरे पड़े होने के बावजूद इस विभाग में शर्मा शर्मी भी थोड़ा सा सुधार भी नहीं आता जबकि वहां के थाना निरीक्षक से लेकर कॉन्स्टेबल तक इन अपराधियों को बचाने की आड़ में मोटा धन वसूल कर अधिकांश पुलिसकर्मी भारी धन इकट्ठा करते रहते हैं। उसके पीछे मूल कारण रहता है कि उन्हें समय रहते निश्चित समयावधि में स्थानांतरित नहीं किया गया। जबकि होना यह चाहिए था की शासन के नियमानुसार हर थाना निरीक्षक का 2 वर्ष में, उप निरीक्षक व सहायक निरीक्षक का 3 वर्ष में और सिपाहियों का हर 3 से 5 वर्ष के बाद स्थानांतरण नियमित रूप से होता रहता तो शायद वे अपराधियों से आप ने गहरे निजी संबंध स्थापित नहीं कर पाते परंतु इसके विपरीत लंबे समय तक जमे नें के कारण अधिकांश सिपाहियों से लेकर सहायक उप और थाना निरीक्षक से लेकर नगर निरीक्षक अधीक्षक महा निरीक्षक तक सब के संबंध राजनीतिक नेताओं, पोष अपराधियों, सटोरियों, भूमाफियाओ,, कॉलोनी माफियाओं, अस्पतालों के डॉक्टरों जो मरीजों से झूठे इलाज के नाम लूट कर, जुए सट्टे के अड्डों चकलाघर, सेक्स रैकेट चलाने वालों, नकली चोरी का माल बेंचने वाले अपराधियों इनसे जुड़े राजनीतिक नेताओं जो स्वयं भी अपराधी है या अपराधों के सरंक्षण दाता है, से उनके गहरे संबंध बन ही जाते हैं स्वाभाविक है ऐसे सभी लोग चुनावों के समय किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने संबंधी मित्रों येन केन प्रकारेण सहयोग करते ही हैं तो चुनाव की निष्पक्षता कैसी? यह सवाल केवल पुलिस विभाग का ही नहीं वरुण यह सवाल और संबंध हर शासकीय विभाग में बैठे अधिकारी कर्मचारी निरीक्षक से लेकर बाबू चपरासी तक सबका है जो सभी का चुनाव के समय में चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्र से लेकर मतगणना तक इन्हीं शासकीय बाबू, कर्मचारियों, अधिकारियों, निरीक्षकों, शिक्षकों, व्याख्याताओं, डॉक्टरों इंजीनियरों सब की सेवाओं का उपयोग कहीं ना कहीं किया ही जाता है अर्थात शासकीय नियम के अनुकूल यदि 3 से 5 वर्षों में स्थानांतरण नहीं भी होता है और जिन्होंने एक ही स्थान पर 3-5 तो क्या 10 से 25 वर्ष तक पूरे कर लिए हैं का स्थानांतरण हर हालत में कम से कम 100 से 200किलो मीटर दूर किया ही जाना चाहिए।जिसमें किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए

इसका सबसे बड़ा लाभ यथार्थ में कर्मचारी और अधिकारी, निरीक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, मानचित्रकार, बाबू,चपरासी आदि सभी को मिलेगा ही क्योंकि एक ही स्थान पर बैठकर हर कर्मचारी अधिकारी ना केवल भ्रष्ट, जालसाज, चालबाज होने के साथ निकम्मा कामचोर और मक्कार भी हो जाता है। साथ ही एक जैसे लोगों के बीच में रहकर मान सम्मान भी घटता है, जो न केबल स्वयं के लिए वरन परिवार के लिए घातक होने के साथ साथ ही विभाग सरकार और देश की सत्ता के साथ जनता के लिए भी घातक होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जगह स्थिर जल लंबे समय में खराब हो जाता है और बहता हुआ जल सदैव स्वच्छ व उपयोगी बना रहता है वही हाल कर्मचारियों अधिकारियों का भी होता है स्थानांतरित होते रहने से अधिकारियों, कर्मचारियों कि जलवायु का परिवर्तन होने से ज्ञानवर्धन होने के साथ-साथ उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती और मान सम्मान भी बना रहने के साथ परिवार के सदस्यों को भी नए स्थान पर घूमने समझने का मौका मिलता है इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है की एक ही स्थान पर जमे रहने से हर आदमी का दिल दिमाग और बुद्धि सब जड़ हो जाते हैं। वह एक ही स्थान पर रहकर यथार्थ में जीवन का वह आनंद ही नहीं ले पाता जो अलग-अलग स्थानों पर जाकर वहां की संस्कृति सभ्यता बोली आदि को ग्रहण कर आंतरिक रूप से महसूस करता है। दूसरी ओर यथार्थ में स्थानांतरण न होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ, जालसाजीयां तो बढ़ती ही है वरन अन्य कर्मियों को भी एक जैसे वातावरण और एक ही तरह के लोगों के साथ कार्य करने से उकताहट और बोरियत भी होने लगती है। जिससे सभी को नुकसान पहुंचता है और कुल मिलाकर इससे ही जनता सदा ही सरकारी कार्य पद्धति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती है।

जब शासकीय नियमों में हर कर्मचारी अधिकारी का स्थानांतरण की व्यवस्था निश्चित है तो आखिर स्थानांतरण क्यों नहीं किए जाते और यही भ्रष्टाचार का मूल कारण होता है क्योंकि दीर्घ समय तक एक ही स्थान पर काम करने से कर्मचारी-अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का ज्यादा मौका मिलता है। जैसे पुलिस के अपराधियों से, कार्य विभागों के ठेकेदारों से, आबकारी विभाग के अवैध नस्ल की धंधा करने वालों और शराब माफियाओं से, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में पेट्रोल पंप वालों, गैस डीलरों, राशन दुकानों, खाद्य एवं औषधि के निरीक्षकों के स्तरहीन, नकली, मिलावटी, खाद्य वस्तु, दवा व्यापारियों, उत्पादकों से, नापतोल निरीक्षकों के पेट्रोल पंप वालों, व्यापारियों, नाडोल करके बेचने वालों से मासिक वसूली कर ज्यादा धन कमाते हैं इसलिए एक ही स्थान पर जमे रहने के लिए मोटा धन खर्च कर अपने वरिष्ठों से लेकर मुख्यालय तक मोटा धन पहुंचाकर अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब रहते हैं और इसीलिए वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री सचिव प्रधान सचिव इसी लालच में उनका स्थानांतरण नहीं करते क्योंकि वे मोटा धन भेंट कर रहे होते हैं। और फिर हमारे घोर धूर्त नेताओं, मंत्रियों को जो कि 5 वर्ष के लिए चुन कर आते हैं। वे यथार्थ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ना तो परिचित होते हैं न ही उन्हें सुधारना चाहते हैं। उन्हें केवल चुनाव लड़ने में खर्च धन की वसूली और आगे अधिकतम धन एकत्रित करने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए वे जानबूझकर मोटा धन प्राप्ति के बदले अधिकांश कर्मचारियों-अधिकारियों का स्थानांतरण करने से परहेज करते रहते हैं। इंदौर के ही खाद्य व औषधि विभाग में बैठे खाद्य व औषधि निरीक्षकों ने अपना स्थानांतरण रोकने के लिए रुपए 25 से 50 लाख तक मंत्री को पहुंचा कर 10 10 वर्ष से एक ही स्थान पर टिके रह कर न केवल इंदौर जेसे नगर में मोटी महीना वसूली कर खूब नकली मिलावटी स्तरहीन खाद्य पदार्थों व औषधियों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दें रहे हैं। यही हाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, आबकारी, वाणिज्य कर, महिला बाल विकास, पुलिस, वन, नारकोटिक्स, श्रम, जिला पंचायत, ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी खनिज विभाग, जिलाधीश कार्यालय, न्यायालय विभाग, नगर निगम, पालिका, परिषदों, विकास प्राधिकरणों, सहकारिता, मंडी, उद्योग एवं वाणिज्य, नगरी प्रशासन, नगर एवं ग्राम निवेश, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सड़क डकैती निगम में 5 वर्षों से ज्यादा समय से इंदौर में बैठा संभागीय परियोजना यंत्री बोरासी, जो एक साथ 2 पद संभाल रहा है और 15 जिलों की बी ओ टी सड़कों को देख रहा है। सभी ठेकेदारों से मोटी वसूली कर गड्ढे भरी स्तरहीन सड़कों पर, जनता को लूटवा कर टोल वसूली करवा रहा है। क्योंकि सबको पैसा पहुंच रहा है। इसलिए मंत्री रामपाल सिंह प्रधान सचिव आजमगढ़ीया सुलेमान खान, सड़क डकैती विकास निगम का प्रबंध संचालक ।मनीष रस्तोगी तक मुंह में मोटा भ्रष्टाचार का धन दबा कर सब चुप बैठे हैं। और बदले में जनता सड़कों पर टोल चुकाकर भी स्तरहीन गड्ढे वाली सड़कों पर अपनी जान हथेली पर रखकर यात्रा करने के लिए मजबूर है यही हाल हर विभाग का है। जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है वहां निकम्मा और भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज मोटी वसूली कर अपने ही अधिकारियों की कठपुतली बन उनके इशारों पर नाच रहा है। सरकार दिवालिया हुई जा रही है।कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन बांटने के लिए धन नहीं है ।और वह लोक लुभावन घोषणाए करने में जनता को भ्रमित कर जीवन का घोर आनंद प्राप्त कर रहा है। उसे शासन-प्रशासन और जनता के दुख दर्द से कोई मतलब कभी नहीं रहा। नि;संदेह जनता के बीच खड़े होकर उनके मन की बातें बोलकर उन्हें बहलाकर 12 साल से सत्ता पर काबिज अवश्य है।

चुनाव आयोग में जब यह नियम है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो चुनाव में अपनी सेवाएं देता है 3 वर्ष से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर नौकरी न कर रहा हो। जिससे राजनीतिक स्तर पर वह कर्मचारी अधिकारी किसी भी नेता का समर्थन या विरोध न कर सके और चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। पर इसके विपरीत स्थानीय स्तर पर प्रदेश सरकार में बैठे धूर्त अधिकारी और मंत्री मुख्यमंत्री जानबूझकर कर्मचारियों और अधिकारियों का इसीलिए स्थानातरण नहीं करते हैं।पहला ताकि उन्हें मोटा चुनावी चंदा मिलता रहे, दूसरा वह आसानी से चुनाव के समय मतदान में इच्छा अनुसार गड़बड़ी कर उन्हें जिताने में सहयोग करें। तीसरा उन्हें खुश रख कर ही चुनाव में मतदान से लेकर गिनती तक में आसानी से सहयोग लेकर चुनावी वैतरणी पार की जा सके जैसा कि पिछले तीन लोकसभा विधानसभा वह नगरीय निकायों के चुनाव में होता चला आ रहा है। यह कहना यथार्थ में येन केन प्रकारेण पूर्ण जालसाजी से चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए आवश्यक है, कि पुराने अधिकारियों कर्मचारियों को उन्हीं के नौकरी के स्थान पर जमें रहने दिया जाए।वर्तमान में मध्यप्रदेश में 70% से ज्यादा कर्मचारियों, निरीक्षकों ने एक ही स्थान पर 5 से 15 सालसे ज्यादा पूरे कर लिया है यही हाल 50% प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों इंजीनियरों, डॉक्टरों, सहायक संचालक, सहायक व उपायुक्तों, संयुक्त आयुक्तों आदि के पदों पर बैठे शासकीय अधिकारियों का भी है। नियमित रूप से स्थानांतरण होने की बात तो दूर चुनाव के समय में भी इन अधिकारियों ने 2-2 लोकसभा विधानसभा नगरीय निकायों के चुनाव भी एक ही स्थान पर बैठकर और अपने और राजनीति आकाओं की सेवा करते और दोनों हाथों से वसूली करते हुए गुजार दिए हैं। निःसंदेह उनके एक ही स्थान पर बैठे रहने के बदले भ्रष्टाचार से कमाए मोटे धन से अपने वरिष्ठों से लेकर विभागीय मंत्री सबको यथा योग्य मोटी भैंट का चढ़ावा समर्पित किया है। स्वाभाविक है ऐसी दूध देती गायों को कौन हटाकर दूध मक्खन मलाई घी के सेवन से वंचित होना चाहेगा। फिर चुनाव आयोग के आयुक्त कोई देव पुरुष तो नहीं।जो साधु सन्यासी है और भूखे सोते हैं। फिर केंद्र व राज्य सरकार उन्ही अपने खास भ्रष्ट भारतीय प्रताड़ना सेवा के कार्यरत, या सेवानिवृत्त अधिकारियों को इसीलिए ही बैठाती है।जो आंख मीच कर हर तरह से सरकार को जिताने के लिए सब कुछ कर गुजरने, नियम-कानूनों को बलाये ताक रख कर, विरोधियों व अन्य उम्मीदवारों को कदम कदम पर परेशान करने, हड़काने, डराने, धमकाने, कानूनों में उलझाकर उम्मीदवारों को काम व प्रचार न करने देने, उनके साथियों के और स्वयं उम्मीदवारों के फोन मोबाइल टेप करने,निगरानी करने लगती है। लोगों को चुनाव आयुक्त पद पर बैठाता है। अपने आकाओं के इशारे पर सरकार का यह कहना यह सिद्ध करता है कि केवल प्रशासनिक अधिकारियों का ही जिलों से स्थानांतरण किया जाएगा बाकी अन्य कर्मचारी अधिकारी से लेकर चपरासी तक जो सभी चुनावी कार्यों में मतदान से लेकर गिनती तक अपनी पूर्ण सेवाएं चुनाव कार्य में देते हैं, का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सिद्ध करता है कि इस बार भी सरकार पूर्व के तीन चुनावों की तरह जिसमें चुनाव आयोग में बैठे आयुक्त से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली तक सब को मोटा धन सत्तारूढ़ पार्टियां चुपचाप अरबों में पहुंचा देती हैं। इसलिए राज्य चुनाव आयुक्तों, मुख्य आयुक्त सभी ने मोटा धन हजम कर सरकारों की बातों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। ताकि चुनाव आसानी से जीते जा सकें।

साप्ताहिक समय माया

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल लूट मची है लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट

प्लॉटधारकों से पूरी वसूली करने के बाद मंडल का पुन: निर्माण का तांडव

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल वैसे तो अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक अपनी जालसाजियों व भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यशैली के माध्यम से उच्च, मध्यम व निम्न आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक श्रमिकों के आवास की योजनाओं को बनाने, किसानों से व अन्य लोगों भूमि धारकों से, भूमि अधिग्रहण करने, उसका भुगतान करने में, उसके नक्शे में हेरफेर करने, प्लाटों की बिक्री, आवंटन, कॉलोनी और भवनों के विकास, निर्माण के निविदा जारी करने, ठेकेदारों से घटिया स्तर का काम करवा कर, उसमें कमीशन का मोटा धन हजम करने के साथ ही, फिर बिलों के भुगतान में बसूली, आवंटित भवनों, प्लॉटों की एक मुश्त बिक्री या उसकी किस्त वसूली, रखरखाव, जल आपूर्ति व निकासी, विद्युत आदि में हर कदम जालसाजियों और भ्रष्टाचार से जहां जिसको जैसा धन मिलता है हजम करता ही है, यही कारण है कि भ्रष्टाचार से धन कमाने, जालसाज बाबूओं, उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रीयों, संपदा प्रबंधकों आदि सभी अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार से मोटा धन कमाते हो 15 से 20 वर्ष तक स्थान पर संरक्षित किया जाता है। उनके 3 वर्ष के बाद स्थानांतरण होने चाहिए चाहिए। जो कि 15 से 20 वर्ष बाद भी नहीं होते। इंदौर में उपयंत्री मनोज श्रीवास्तव, मनोज तिवारी शिवाले, आदि जो अभी कार्यपालन यंत्री के प्रभार संभाल रहे हैं । यहीं पर उपयंत्री से पदोन्नत होकर सहायक यंत्री और सहायक यंत्री से प्रभारी कार्यपालन यंत्री हैं। जो बरसों से इंदौर में रहकर भारी भ्रष्टाचार कर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। जिनका भ्रष्टाचार के धन मिलते उपायुक्त वाईएस दौहरे पूर्ण संरक्षण करते हैं। जबकि यह शूकरों की फौज को संपदा प्रबंधक, वहां पर बरसों से कुंडली मारे बैठे बाबू संपदा अधिकारी के साथ दो सुरक्षा सैनिक अफाक व एक अन्य जो जप्त किए ताले लगे भवनों की देखरेख के लिए हैं। स्वयं ही ताले तोड़कर पैसे लेकर कब्जे करवाते रहते हैं। इंदौर नगर में 100 से ज्यादा कॉलोनियों की, मंडल की संपत्तियों की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा इन्हीं दोनों सुरक्षा सैनिकों पर है। इंदौर में ही अभी राजेंद्र नगर, राउ आदि में में ही अनेकों कॉलोनियों का कार्य चल रहा है। अभी सबसे बड़ा टेंडर होप मिल की जमीन पर 16 मंजिला भवन का होने वाला है जिसमें अरबों रुपए का निर्माण कराना है। इसके टेंडर में भी काफी लेनदेन और भ्रष्टाचार की खबरें हैं। इंदौर संभाग के उपायुक्त के पास वर्तमान में सनावद, बड़वाह, खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ, धार, पीथमपुरं आदि में सैकड़ों कॉलोनीयों के निर्माण कार्य, प्लाटों, भवनों के आवंटन, बिक्री आदि में भी भारी जालसाजियां कर सभी मोटी कमाई दोनों हाथों से कर रहे हैं। निसंदेह यह धन उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों, संपदा अधिकारियों, कार्यपालन यंत्रीयों उपायुक्त दोहरे से होता हुआ आयुक्त रविंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष मोघे, प्रधान सचिव विवेक अग्रवाल, मंत्री माया सिंह से मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। इन गिध्दों की इस नोच खसोट से से पेट नहीं भरा तो तो इन्होंने जो पुरानी कालोनियां और भवनों जो कि 30-40 साल बाद वे भवन और कॉलोनियां अब नगरों की आत्यधिक व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच में आ जाने से इन अधिकारियों की लार और नियत उन भवनों पर और कॉलोनी पर लग गई अब उन्हें यह तोड़कर नई बहुमंजिला इमारतें बनाने और बेचने में अरबों रुपए का

भ्रष्टों मंत्री माया सिंह प्रधान सचिव विवेक अग्रवाल, अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे, सचिव एवं आयुक्त रविंद्र सिंह से लेकर मुख्य अभियंता, नीचे सभी कार्यालयों के उपायुक्त, से उपयंत्री और बाबू चपरासी सुरक्षा सेवक, तक सब शामिल है आवासियों और आवास की आस में खड़ी जनता को लूटने के लिए

धन हजम करना चाहते हैं इसलिए इंदौर के ही पुरानी निम्न आय वर्ग की तिमंजिला का कॉलोनियों को जो कि एल आइ जी तिराहे ए बी रोड पर हैं। उन्हें तोड़ कर वहां के रहवासियों को अलग हटाकर अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। जब मंडल ने तिमजिला भवनों में मकानों की रजिस्ट्री कर दी, अधिकांश से पूरा पैसा वसूल लिया, तो फिर तोड़ने का अधिकार बिना मर्जी के कैसा? वैसे ही वे सारे भवन निम्न आय वर्ग के लोगों ने अपनी जीवन की सारी जमा-पूंजी से, किश्ते भर कर बड़ी मुश्किल से अपने नाम करवाए थे और अब यह भ्रष्टों और जालसाजों की फौज उन गरीबों से मकान हथियाकर सड़क पर खड़ा कर देना चाहता है इस चक्कर में एक गरीब विधवा महिला की दहशत में हीं मौत हो गई। जिसकी जिम्मेदारी कोई ने नहीं ली दूसरी तरफ रहवासियों ने इसके विरुद्ध आंदोलन भी किया।

निसंदेह इन भवनों का रखरखाव का पैसा यहां पर बैठे हरामखोर उपयंत्रियों रूपी गिध्दों जो वर्तमान में कार्यपालन यंत्री पद का बोल प्रभार रहे हैं, ने रखरखाव कागजों पर ही दिखा कर कर हजम कर लिया जिससे इन भवनों की हालत गंभीर हो गई है और कहीं छत का कंक्रीट टपक और उखड़ रहा है। तो कहीं दीवानों का प्लास्टर टपक रहा है। अधिकांश भवनों में दीवानों छतों पर दरारें आ चुकी है। जिनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल जिसकी मध्यप्रदेश में लगभग 10000 से ज्यादा कालोनिया, बहुमंजिला इमारतें, व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे ज्यादा कालोनियां, फ्लेट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें कार्यालय आदि का आवंटन व बिक्री सबसे ज्यादा भोपाल में हुई वहां इनके तीन कार्यपालन यंत्री बैठते हैं। इन सभी के विकास और निर्माण में पूरे प्रदेश में बैठे उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रीयों, अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता जो कि इन योजनाओं विकास और निर्माण के सूत्रधार थे, उपायुक्तों से लेकर आयुक्तों, अध्यक्ष प्रधान सचिव व मंत्री सबने भ्रष्टाचार में करोड़ों की कमाई की है। वैसे तो सभी निगमों और मंडलों में शुरु से ही अपनी जालसाजियो और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। इस मंडल में भी जो कि भूमि अधिग्रहण, कॉलोनी की डिजाइन तैयार करने, कॉलोनी के प्लॉट बेचने, प्लॅट काटने, प्लाटों के आवंटन, आदि में ही भारी भ्रष्टाचार होता है गरीब और निम्न आय वर्ग मध्यम वर्ग के लिए स्वयं ही बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट बनाकर किश्तों में बेचता है। फिर किश्तों की वसूली में, विलंब में ब्याज की वसूली, वसूली पूरी हो जाए इसके बाद उनके पंजीयन नामांकन अंतरण आदि में भी वहां बैठा हुआ स्टाफ बाबू से लेकर उपयंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री सहायक आयुक्त उपायुक्त आयुक्त से लेकर मंत्री तक, प्लॉट धारी और मंडल में मकान धारी जनता को परेशान कर दोनों हाथों से, कदम कदम पर वसूली की जाती है। इसके साथ ही उन मकानों का रखरखाव के नाम चौकीदार से लेकर उपयंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री, प्रमुख अभियंता सभी के नियमित कमाई का साधन होते हैं और रखरखाव के नाम पर सारा धन हरामखोरों की फौज रहवासी जनता को गिध्दों की तरह नोचकर भी कभी पूरा नहीं करती। यह कहानी और सच गृह निर्माण मंडल कॉलोनाइजरों का 60 साल पुराना है। वर्तमान में यहां बैठे धूर्तो की फौज ने अब एक नया तरीका निकाला जिसके अंतर्गत, जो कालोनियां बहुमंजिला इमारतें गृह निर्माण मंडल ने बनाई थी। बरसों पुरानी इन कालोनियों और बहुमंजिला इमारतों की समय गुजरने के साथ और बस्ती के सघन विकास के कारण उनकी कीमतों में सौ गुना तक वृद्धि हो गई। जिसे देख कर मंत्री आवास अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे के साथ मुख्य अभियंता और आयुक्त सबके मुंह में मुंह में पानी था कि किस प्रकार से इन बस्तियों के रहवासियों को, डरा धमका कर, लालच देकर, पहले इन बस्तियों को उजाडा जाए, फिर इन जमीनों पर आधुनिक किस्म की चकाचौंध वाली नई इमारतों को खड़ा किया जाए और उनकी कई गुना कीमत ज्यादा वसूल की जाएउसी कहानी को पुनः दोहराया जाए और अपने खास लोगों को ऐसी बेशकीमती जमीन पर बैठा दिया जाए। यह हाल पूरे मध्यप्रदेश की जहां पर उद्योगी करण के कारण भारी विकास हुआ और वहां कार्यरत उद्योगपतियों से लेकर मजदूरों तक को आवास की समस्या आई वहां सभी जगह इस मंडल ने जो कालोनियां और भवनों के 50 वर्ष पूर्व काटीं वह निर्माण किए थे उन सभी पर मंडल के प्रबंधन की नजरें गड़ी हुई है ताकि पहले तोड़ने में, फिर निर्माण कार्य में, आवंटन और बिक्री में सैकड़ों करोड़ में मोटा लाभ हो सके।

इसके संबंध में मंडल ने रहवासियों को चमकाने-धमकाने, और हटाने की मानसिकता तैयार करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पहले भूमिका बांधने उन भवनों की जरजर्ता के बारे में लगातार समाचार छपवाए, फिर लालच दिया गया की जब तक निर्माण कार्य होगा तब तक रहवासियों को मंडल किराया देगा और फिर उन्हें नए बने फ्लेटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जबकि यथार्थ यह है कि एक बार खाली करवाने के बाद मंडल साल 2 साल का किराया देगा जिस में भी भारी भ्रष्टाचार होगा. फिर जानबूझकर दो-तीन साल के बाद किराया देना बंद कर दिया जाएगा, धन ना होने का रोना रोया जाएगा. दूसरी तरफ नये निर्माण के नाम पर जानबूझकर डिजाइन ड्राइंग डीपीआर तैयार करने में समय लगाया जाएगा उसमें भ्रष्टाचार होगा, अरबों रुपए के निर्माण के टेंडर होंगे. डीपीआर दोगुनी से चार गुनी लागत की होगी, उसमें मोटी वसूली होगी, फिर निर्माण कार्य, डीपीआर के अनुसार ना किया जा कर स्तरहीन करवाया जाएगा जिसमें करोड़ों की वसूली होगी, बिलों के भुगतान में नौटंकी की जाएगी, यह करते-करते और भवन निर्माण की परियोजना पूरी होते होते ही पूरे प्रदेश की ऐसी 1000 सेज्यादा कॉलोनीयों 10-20% लोग मर ही जाएंगे जिनके भवनों की आवंटन-बिक्री में भी तात्कालिक यंत्रियों और अधिकारियों की मोटी कमाई हो जाएगी बेशक उसने मंत्रियों सचिवों को भी मोटा लाभ मिलेगा।

कृत्रिम बुद्धिमता भविष्य में घातक हो सकती है पूरी पृथ्वी पर

छोटी सी चूक नष्ट कर देगी पूरी पृथ्वी को, निःसंदेह तानाशाही के लिये आवश्यक

ज्यादा यंत्रों का उपयोग जैसे मानव को निरुपयोगी और आलसी बना रहा है वैसे ही कृत्रिम बुद्धिमता मानव की सभ्यता को खत्म करने का खेल कर सकती है

वर्तमान में अमेरिका चीन फ्रांस रूस ब्रिटेन के साथ भारत में भी कंप्यूटराइज मानव यंत्र रोबोटिक्स और उन्हें संचालित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कृत्रिम बुद्धिमता पर काम करना सिखाया जा रहा है ताकि विस्तृत रूप से अपने कार्यों को संपन्न कर सकें जिसमें मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं, मानव की चिकित्सा हेतु जटिल और सूक्ष्म अंगों की शल्य क्रिया करने की लेसर प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमता से संचालित रोबोट्स संपन्न करेंगे इसी प्रकारअन्य जटिल तकनीकी, सुक्ष्म यांत्रिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, सड़कों पुलों के निर्माण भवनों, बांधो, नहरो जिन के निर्माण से लेकर, अत्यधिक उच्च व निम्न तापमान में, जटिल परिस्थितियों में काम करने के लिए इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त रोबोट्स उन कार्यों को संपन्न करेंगे। यह रोबोट्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता का धनात्मक पहल हुआ जो कि मानव के जटिल कार्यों को संपन्न कर मानव के जीवन को खुशहाल बनाएगा इसके विपरीत भविष्य में या युद्ध के मैदान में बिना मनुष्य के के हथियारों टेन्को, तोपो, को संचालित किए भी मशीन गन, लेसर गन, व अन्य हथियार देकर ऐसे ही कृत्रिम बुद्धि से संचालित रोबोट्स युद्ध के मैदान में चुन-चुन कर बिना किसी मानवीय सहायता और नियंत्रण के दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करते करते स्वयं ही थोड़ी सी चूक होने पर अपने ही मालिक पर हमला करने और उसे नष्ट करने से भी नहीं चूकेंगे। यहां तक तो ठीक था। पर जब इनके नियंत्रण में परमाणु हथियार, रासायनिक हथियारों, को अपनी बुद्धिमता से उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी तब यह सब पृथ्वी को नष्ट करने में भी नहीं चूकेंगे। क्योंकि इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि इनकी चातुर सीमा का उपयोग किस प्रकार से वातावरण, मानव के अतिरिक्त अन्य जीवो, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के साथ वातावरण को भी नष्ट कर देगा।

ठीक है निर्माताओं ने भी इसे काफी सोच समझकर और सभी बातें ध्यान में रखकर निर्मित किया है। ताकि जटिल कार्यो को स्वतंत्र रूप से यूरो कोट्स संपन्न कर सकें और मानव जीवन को आसान बना सके पर इसके विपरीत होगा यह की बड़ी-बड़ी व्यवसायिक कंपनियां अपने मोटे लाभ के लिए और कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन के बोझ से बचने, उनकी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने, मानवीय सीमा से परे काम लेने के लिए रोबोटिक्स का उपयोग अपने उत्पादन करने के लिए, भारी भरकम जटिल कर्म करने के लिए करेंगी। परंतु भविष्य में इससे बेरोजगारी बढ़ने के साथ,

व्यवसायिक कंपनियों, सरकारों में उनके मंत्रियों, अधिकारियों में अपनी श्रेष्ठता, एकाधिकार और वर्चस्व के लिए इस कृत्रिम बुद्धिमता के के माध्यम से आपसी प्रतिद्वंदिता, एकाधिकार की जंग होगी। यही जंग बाद में जब विशाल रूप लेगी। तब ना कुछ जनता को समझ में आएगा और ना ही अन्य अधिकारियों मंत्रियों कर्मचारियों को कुछ समझ आएगा। जिससे तानाशाही और एकाधिकार बढ़ेगा और अंत में जनता का ही सर्वनाश होगा। यथार्थ में कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग संचार माध्यमों में कर जनता के साथ अपने अड़ोस-पड़ोस के अधिकारियों कर्मचारियों मंत्रियों की निगरानी कर उनको स्वचालित रोबोट के माध्यम से ही नष्ट करने और अपना एकाधिकार स्थापित करने में तानाशाह सफल रहेंगे डाटा मोबाइल फोन ईमेल कंप्यूटर पर किए गए कार्य, खरीदी, बिक्री, भुगतान, आदि के हर कार्य से यह कृत्रिम बुद्धिमता हर चीज को हर तथ्य को अपने आप देखकर कुछ ही मिनटों में आकलन कर अपने संचालक को सूचित कर तत्काल कार्यवाही करने में सक्षम होंगे। इसलिए हमारे मोदी अपने आप को अत्यधिक चतुर और चालाक समझ इस कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग करने भारत में जनता का अरबों रुपए खर्च करने को तैयार हैं ताकि विरोधी पार्टियों, जनता की हर गतिविधियों पर आसानी से नजर रख उन्हें तत्काल नियंत्रित किया जा सके और अपना तानाशाहीपूर्ण शासन दीर्घकाल तक चलता रहे। धन संग्रह, धन की प्राप्ति, उपयोग आदि के बारे में तत्काल जानकारी एकत्रित कर आयकर विभाग को जागरुक कर छापेमार कार्रवाई आदि करने में इस कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग कर जनता को नोचा-खसौंटा जा सके और अपने मौज मस्ती, अपने ऐशो-आराम के लिए आसानी से धन एकत्रित कर लुटाया जा सके। इसलिए यह मूढ मोदी अपने अधिकारियों की सलाह पर कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारी धन खर्च कर रहा है निसंदेह इसका फायदा हमारी चीन से लगती हुई 4200 किलोमीटर लंबी, पाकिस्तान से 16 किलोमीटर लंबी और समुद्र की 7600किलोमीटर लंबी सीमा पर शत्रु पर निगरानी, नियंत्रण और संभावित युद्ध के खतरे को कृत्रिम बुद्धिमता युक्त रोबोट से करने में आसानी होगी जिसमें सदा ही मानवीय चूक होती आई है। वर्तमान में कश्मीर के हालातों को देखते हुए वहां पर आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता से ही युक्त रोबोट्स बेहतर कार्य करते हुए तत्काल ही आतंकियों, पत्थर फेंकने वालों, गोलियां चलाने वालों, पुलिस और सेना के साथ मारपीट करने वालों को नियंत्रित करने में बेहतर भूमिका निभाएगा, यह भी सच है।

सभी शासकीय कार्यालय स्मार्ट बनाने के नाम हो रही करोड़ों की बंदरबांट

लोक निर्माण विभाग में चल रहा वसूली का खेल और अधिकारी पी रहे हैं जनधन का तेल

प क्रि इ मैं चुन-चुन कर बैठाये गए भ्रष्ट संभागीय परियोजना यंत्री, सहायक संचालक यंत्री, अतिरिक्त संचालक, संचालक 90% शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, छात्रावासों, स्टेडियम, आदि के निर्माण में कर रहे हैं। मूल डिजाइन बदलकर कर रहे, घोर भ्रष्टाचार, सेतु संभागो में भी किसी भी पुल का निर्माण निर्धारित लागत और समय अवधि में भ्रष्टाचारी कारण कभी नहीं होता। इसलिए हरामखोर जवाब नहीं देते सूचना के अधिकार के पत्रो का

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के किस्से कहानियां हर दिन अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं फिर भी बहुत सारे समाचार सामने नहीं आ पाते। कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने चहेते प्रधान सचिव आजमगढ़िया, धूर्त, अय्याश, सुलेमान खान को पुनः लोक निर्माण विभाग में बैठा दिया है। अर्थात भ्रष्टाचार का पुराना इतिहास पुनः दोहराया जाएगा यह तो स्पष्ट किया है। स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लगभग 27000 किमी सरकारी और 20000 किलोमीटर बीओटी सड़कें दयनीय स्थिति में है। पर सरकार के हरामखोर प्रधान सचिव सुलेमान, मंत्री रामपाल सिंह को ना केवल विभाग से महीना मिल रहा है वरन उसके अनुषांगिक संगठनों रोड डकैत कारपोरेशन के बीओटी के टोल वसूली के ठेकेदारों से भी करोड़ों में महीना मिलने के कारण वह आंखें नीचे बैठे हुए हैं। बी ओ टी की सड़कों पर तो ठेकेदार टोल वसूली भी हर साल बढ़ाकर करता है और रखरखाव के नाम पर दचके, गड्ढे, जानलेवा बनावट और संरचना हर दिन सैकड़ों दुर्घटनाओं और लोगों की मौत का कारण बनती है। फिर प्रदेश के 55 से ज्यादा संभागों में अधिकांश में महीना वसूली के लिए सहायक यंत्री को ही कार्यपालन यंत्री का प्रभार देकर बैठा दिया गया है। स्वाभाविक है कि वह कार्यपालन यंत्री अपने अधीक्षण, मुख्य अभियंता, पदस्थ करने वाले प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल, प्रधान सचिव मंत्री को महीना पहुंचाएगा तो उसे भ्रष्टाचार तो करना ही पड़ेगा आखिर वह धन कहां से लाएगा?

बेशक सुलेमान ने आते ही अपनी धाक जमाने के लिए कुछ प्रमुख अभियंताओं जिसमें इंदौर के मनोज पौराणिक, उज्जैन के एम पी सिंह को फटकार भी लगाई थी कि वह अपने कमीशन के लिए जानबूझकर निविदाओं को रोक के रखते हैं। हाल फिलहाल अधीक्षण यंत्रीयो और प्रमुख अभियंताओ के पदों पर अधिकांश भ्रष्टों को ही प्रभार देकर पदस्थ कर दिया गया है जिसमें सिहस्थ उज्जैन के अधीक्षण यंत्री बागोले को ग्वालियर का प्रमुख अभियंता का पदभार दिया गया है जिन्होंने सिहस्थ के कार्यों में भारी मोटी कमाई कर सबको खुश किया था और बदले में महा धूर्त कार्यपालन यंत्री केलकर जिस पर पूरे मध्यप्रदेश में जितने संभागों में काम किया भ्रष्टाचार के अनेकों प्रकरण लंबित है इनकी जांचें अभी भी फाइलों में धूल खा रही हैं। बंदा मोटा धन हजम कर सेवानिवृत्त हो चुका है। जिसने सिन्हस्थ मे लगभग रुपए12सौ करोड़ के काम में लगभग रु400 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसका हिस्सा अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता प्रधान सचिव मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ तक पहुंचा सभी को हिस्सा डकार कर चुप होने के साथ ही जांच की बात तो दूर विपक्ष की सारी बातों को, सारे आरोपों को नजरअंदाज कर उल्टे ही मुख्यमंत्री ने सब को पुरस्कार बांटे।

वर्तमान में भी पूरे प्रदेश के 60 ज्यादा संभागों में जो कि सभी शासकीय विभागों की 5000 कार्यालयीन, इसमें प्रदेश के 3 उच्च न्यायालय, जिलों और तहसीलों के न्यायालयों, 10 कमिश्नर कार्यालयों, 51 जिलों के जिलाधीश कार्यालयों, उनसे संबंधित 50से ज्यादा अन्य कार्यालयों के भवनों, प्रदेश एक लाख से ज्यादा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों, 5000 से ज्यादा महाविद्यालय आदि के भवनों की देखरेख के साथ उनके आवासों और रखरखाव की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री उपयंत्री से लेकर बड़े बाबू छोटा बाबू के हाथ में ही होती है। जिसका पुताई, रंग रोगन, दरवाजे खिड़कियों, छतों दीवारों प्लास्टर, टूट-फूट आदि का 70% पैसा अपने खास ठेकेदारों के साथ मिलकर हजम कर लिया जाता है। निसंदेह इस पैसे को अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता प्रधान सचिव मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ऑफिस के नाम पर हर कार्यालय को प्रति माह कार्यालय के भवन के अनुसार लाखों रुपए का आवंटन का पैसा कार्यालय प्रमुख को दिया जा रहा है। जिसमें पुताई, फर्नीचर, फर्श पर टाइल्स, शौचालय आदि के 90% फर्जी बिलों के भुगतान को ठेकेदारों के साथ मिलकर कार्यपालन यंत्री लोनिवि हिस्सा बांट में हजम करते हैं यह कहानी, यह सच पूरे मध्य प्रदेश अधिकांश शासकीय विभागों का है। जबकि कार्यपालन यंत्री के पास जिले की 1,000 किलोमीटरसे ज्यादा सड़कें, नए छोटे भवनों का निर्माण कार्य आदि भी होता है। अधिकांश बार सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर यहां के प्रमुख अभियंता जो कि अपने परिक्षेत्र के सारे संभागों के कार्यपालन यंत्री पर नियंत्रण व देखरेख का कार्य करते हैं, जिनसे उन्हें महीना मिलता है अधिकांश उन्हें बचाने का प्रयास भी करते हैं इसलिए ये हरामखोरों की फौज कभी भी पूरी जानकारी नहीं देती यहां तक की कई मुख्य अभियंता कार्यालयों में बैठे वहां के बाबू धारा 6(3) में कार्यालय में न होने पर पत्र को अंतरित तक नहीं करते बेशक पूरे मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग के कार्य विभाग के मैनुअल केअनुसार अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्रीयों के महीने भर की टूर डायरी, निजी टैक्सियों की जिनके टेंडर किराए पर लेने के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय से होते हैं। लॉग बुक देने से साफ मना कर दिया जाता है। यही हाल मुख्य अभियंता को महीने में कम से कम 10 निरीक्षण कार्यों के करना आवश्यक होते हैं उसकी जानकारी भी नहीं दी जाती क्योंकि सबको बचा कर चलना है। ताकि उनसे महीना मिलता रहे। झाबुआ में बैठे कार्यपालन यंत्री जयसवाल सूचना का अधिकार के पत्रो का समय पर जवाब देते हैं। न हीं ये हरामखोर अपील लगाने पर कभी अपील की सुनवाई में उपस्थित होता है। विभाग में इसके हरामखोरी, जालसाजी के और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन न करने के नियमित प्रकरण सामने आते हैं। बेशक भ्रष्टाचार से मोटी कमाई करने के कारण यह पैसा सीधा प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल को पहुंचा कर उनसे छोटे अधिकारियों की परवाह नहीं करता।

वर्तमान में लोनिवि विभाग में सभी शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, खेल प्रशालों, छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य के लिए अलग परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन जो 5 वर्ष पूर्व हुआ था । इसमें वे सारे घोर भ्रष्ट इंजीनियर जो विभाग के लिए काफी सिर दर्द बने हुए थे। उन्हें ही इस इकाई में पदस्थ किया गया। इंदौर में बैठा हुआ खरात जोकि अधीक्षण यंत्री सह सहायक संचालक परियोजना क्रियान्वयन इकाई है लोक सूचना अधिकारी होने के कारण हरामखोर सूचना का अधिकार में हुए पत्रो के जवाब नहीं देता साथ अपनी कार्यपालन यंत्री सह संभागीय परियोजना यंत्रीयों के हर कदम किये हुए भ्रष्टाचारों स्वीकृत डिजाइन से भवन के वास्तविक निर्माण में किए गए बदलावों में उसे भारी भ्रष्टाचार से भारी धन कमाया जा सके। फिर उनकी निर्माण निविदाओं मैं अपना कमीशन वसूलने के साथ, निविदाओं की स्वीकृति देने में ठेकेदार से वसूली के बाद भी निर्माण कार्य में स्तरहीन निर्माण दरवाजे, खिड़कियां, दिवालो के प्लास्टर, छतों की भराई, के साथ फाउंडेशन की खुदाई और भराई के साथ निकले हुए मलवे जिसमें मिट्टी पत्थर के लीड अर्थात उन्हें फेंकने में भी भारी लंबी दूरी का भुगतान करता है जिसमें उसने ठेकेदारों को अपने भ्रष्ट शुकरों की फौज कार्यपालन यंत्री या संभागीय परियोजना यंत्री को भारी लूट का मौका दिया ।

जिसमें उसने स्वीकृत लागत से ज्यादा कि भुगतान स्वीकृति प्रदान कर अपना हिस्सा भी बटोरा। यह हाल इंदौर परिक्षेत्र में आने वाले 12 संभागों का था। इसलिए यह हरामखोर न तो सूचना के अधिकार के आवेदन का जवाब देता था और अपील भी दबा कर चुपचाप बैठ गया क्योंकि इसे मालूम था कि इसने जो भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। बेशक यह सच पूरे मध्यप्रदेश के सभी परियोजना क्रियान्वयन संभागों के हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कानून में ही व्यवस्था है की सूचना का अधिकार की अपील उसका वरिष्ठ अधिकारी ही सुन सकता है। इसके विपरीत परियोजना संचालक को भेजी गई अपील को उसने पुनः अतिरिक्त परियोजना संचालक को भेज दी वह हरामखोर उन अपीलों को को हजम कर कर बैठ गया।

अब जबकि पिछले 6 माह से यहां पर अधीक्षण यंत्री तिवारी को अतिरिक्त परियोजना अधिकारी बनाकर बैठाया गया है। यह भी अपनी मोटी कमाई के लिए लीड फेक्टर मे, स्वीकृत कार्यों जिसमें स्टेडियम, स्कूल, न्यायालय, छात्रावास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, प्रयोगशालाओं आदि के भवनों की, डिजाइन बदलकर कम निर्माण करवाना स्वीकृत राशि से ज्यादा का भुगतान करना, समय विस्तार देना महंगाई का लाभ देना आदि के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई में यदि इसके संभागीय परियोजना अधिकारी द्वारा किए गए सभी कार्यों की बारीकी से जांच की जाए तो 90% कार्यों में भारी भ्रष्टाचार सामने आएगा परंतु सब देखने और जानने के बावजूद यदि अतिरिक्त परियोजना संचालक परियोजना संचालक प्रधान सचिव जो भी कार्य के निरीक्षण के लिए आते हैं अपने हिस्से का धन बटोरकर चुपचाप सब कार्यों को अच्छा बता कर निकल लेते हैं जबकि यहां पर जितने भी अधिकारी ब गए हैं उनके इतिहास में कदम कदम पर मक्कारी, हरामखोरी और भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ था तो उनसे स्वाभाविक रूप से तो उनसे अच्छे कार्यों की उम्मीद करना निरर्थक है। धार संभाग में लंबे समय तक पदस्थ रहे रावत का अपना भ्रष्टाचार का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है।पूर्व में अपनी लड़की के मेडिकल में प्रवेश के कारण व्यापम घोटाले में कई महीनों तक फरारी काट चुके हैं सागर से परियोजना क्रियान्वयन इकाई देवास में पदस्थ कर दिए गए हैं।

यही हाल इस विभाग के सेतु निर्माण का भी है यहां भी कोई भी पुल निर्धारित डिजाइन और डीपीआर मैं किए गए सामग्री उपयोग के विवरण व निर्धारित समय लागत की सीमा मैं कभी पूरा नहीं होता। इसी चक्कर में पूर्व के घोर धूर्त जलसाज और महाभ्रष्ट कार्यपालन यंत्री रा.ना. मिश्रा लोकायुक्त के चंगुल में फंस गए। उसके बाद में भी वहां के इंजीनियर, अधिकारी व कर्मचारी सुधरने और संभालने को तैयार नहीं। यहां पर भी सूचना का अधिकार में दिए जाने वाले आवेदनों का जवाब तो देते ही नहीं यहां तक कि उज्जैन संभाग में बैठे कार्यपालन यंत्री टेंटवाल जिसने कार्यपालन यंत्री केलकर से प्रभार लिया है और उसके पूर्व सुश्री खन्ना ने वहां सिहस्थ मैं लगभग रु 200 करोड़ के पुलों का निर्माण का कार्य किया था। इस में स्तरहीन और डिजाइन के विपरीत भारी भ्रष्टाचार किया गया। इसलिए वहां पर भी जानकारी देने से हर प्रकार से बचा जाता है। इसके विपरीत कार्यपालन यंत्री की अपील मध्य प्रदेश सेतु मंडल भोपाल में करने पर वहां बैठा अधीक्षण यंत्री जो इन सभी कार्यपालन यंत्रीयों से मोटा महीना वसूलता है।सदा ही पूरे मध्यप्रदेश भेजी गई अपीलों को एक मुश्त निरस्त कर देता है। साथ ही सूचना के अधिकार पर अधिनियम को लगे हुए 13 साल से ज्यादा का वक्त पूरा हो चुका है परंतु इस पूरे विभाग ने इस अधिनियम की धारा 4 को अभी तक पूरा नहीं किया जिसके अंतर्गत 17बिंदुओं की जानकारी को स्वमेव ही हर विभाग को अपनी विभाग की साइट पर उपलब्ध करवानी थी। करोड़ों रुपए हजम करने के बाद में भी अभी तक प्रधान सचिव, सचिव प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता से लेकर नीचे तक सभी संभागीय यंत्रियों ने भी कभी पूरी नहीं की जबकि श्री अजमेरा द्वारा लगाई हर अपील में इस बात का उल्लेख करके हर बार कहा गया की धारा 4 के अंतर्गत सारी जानकारियां विभाग क्यों नहीं अपनी विभागीय साइट पर डालता। ताकि सूचना के अधिकार में आवेदन देने की आवश्यकता ही ना पड़े। पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव से लेकर प्रमुख अभियंता तक जानबूझकर न तो इसकी पूछताछ करते हैं, न हीं जानकारी डालते हैं क्योंकि सभी को डर है,कि जानकारी साइट पर डालने से वह सार्वजनिक हो जाएगी जिससे जनता का धन जो निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त हुआ है हजम करने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मध्य प्रदेश की सेतु निर्माण के सभी संभागों का इतिहास रहा है कोई भी पुल पुलिया ना तो कभी डिजाइन व डीपीआर के हिसाब से बनाई है इसके साथ ही चित्र संभाग के सभी कार्य पर नियंत्रण का कार्यपालन यंत्रीयों का यह इतिहास रहा है की कोई भी पुल कभी भी निर्धारित लागत और समय में पूरा नहीं हुआ हर पुल में दुगना समय और दूगुनी लागत का सरकार द्वारा भुगतान और स्वीकृति दी गई जिस में भारी भ्रष्टाचार कर काफी मोटा धन कार्यपालन यंत्री यों से लेकर अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता ने डकारा यह सत्य सभी जानते हैं इसके विपरीत यहां पर अधिकांश पदस्थ किए जाने वाले इंजीनियर वही होते हैं जिनका भ्रष्टाचार का इतिहास होता है।

मप्र सड़क डकैती विकास निगम मैं बैठे 7 वर्ष से ज्यादा समय से संभागीय यंत्री बोरासी जो कि वर्तमान में इंदौर के साथ, उज्जैन और इंदौर के सभी 14 जिलों के महा प्रबंधक के पद को भी प्रभार के रूप में संभाल रहा है। हटाने को कहा था परंतु मोटा धन मिलने के बाद इस तरफ निगाह उठाना भी उचित नहीं समझा जबकि सड़क डकैती विकास निगम मैं बैठा का य बोरासी एक तरफ ठेकेदारों से महीना वसूली कर, कठपुतली बन नाच रहा है। क्योंकि उसे स्वयं अपने कार्य में दक्षता प्राप्त नहीं है। उज्जैन सड़क डकैती निगम का संभागीय प्रबंधक राकेश जैन जिसने भी के कार्यों मैं सड़क निर्माण पुल पुलिया निर्माण बाईपास निर्माण के साथ सड़क पर सेंट्रल लाइटिंग में करोड़ों रुपए का खेल किया यह संदेश सब को शेयर हिस्सा पहुंचाया वह भी पिछले 5 सालों से वहां पर कुंडली मारे बैठा हुआ है। चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों की सिंहस्थ के दौरान भारी मोटी सेवा इनके द्वारा की गई थी इसलिए सभी उज्जैन संभाग की बीओटी टोल सड़कों में यह भी महीना लेकर किसी भी ठेकेदार से सड़कों के पुनर्नवीनीकरण के लिए कभी नहीं कहता और ठेकेदार वाहन चालकों से पूरी मुस्तैदी से वसूली कर स्तरहीन सड़कें उपलब्ध करवाता है यह हाल पूरे मध्यप्रदेश में हर ब्यूटी सड़क का है जहां पर कोई भी टोल सड़क पर टोल की शर्तो के अंतर्गत कार्य नहीं किया जा रहा है और सड़कें बर्बाद व स्तरहीन होने के बावजूद भी उनसे पूरी वसूल की जा रही है। यहां तक की किसी भी टोल नाके पर न एंबुलेंस उपलब्ध होती है न क्रेन न ही वहां के स्नानागार, शौचालय और मूत्रालय स्वच्छ होते हैं। ना ही वाहन चालकों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त होता है। इसके विपरीत यह सारे हरामखोर डकैतों की फौज आंख मीच कर महीना हजम कर चुपचाप रहती है। जबकि निरीक्षण रिपोर्ट में हर तथ्य चुस्त-दुरुस्त दिखाया जाता है। इन दोनों संभागों का इंदौर मंडल का महाप्रबंधक बोरासी भी अपना हिस्सा डकार चुप रहता है। जबकि इन दोनों को तत्काल यहां से स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिन्हें 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं।

बीओटी ठहराव पत्र में यह शर्त की हर सड़क को 33% हिस्सा हर 3 साल में रिन्यू किया जाएगा अर्थात 3 साल में हर सड़क को पूरी तरह से नया बना दिया जाना चाहिए था पर कोई भी बीओटी ठेकेदार केवल टोल के ऊपर बढ़ती हुई रकम तो वसूल रहा है परंतु सड़कों के मेंटेनेंस के नाम पर केवल गड्ढे भरने का अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसमें भी यह पूर्ण सही निरीक्षण रिपोर्ट लगा रहा है यही हाल उसके वरिष्ठ अधिकारी से लेकर प्रबंध संचालक तक कर रहे हैं

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री रामपाल सिंह अभी तो हाल फिलहाल अपनी बहू की आत्महत्या को लेकर उलझे हुए हैं। इसलिए इस पर टिप्पणी करना निरर्थक है। वैसे मंत्री रामपाल सिंह की नियुक्ति के बाद उन्होंने जो इंदौर में सभा की थी उस वक्त काफी कड़े तेवर दिखलाए थे।

साप्ताहिक
समय माया

इंदौर नगर निगम अपनी लूट के लिए उजाड़ रही वैध बस्तियां और कब्जे किए जा रहे नजूल, सरक

अवैध निर्माणों से मोटी कमाई, स्मार्ट सिटी के नाम भ्रष्टाचार से भी मोटी वसूली

पूरे देश और प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर चारों तरफ हर जिले हर नगर में जिस तरह से बसी हुई पुरानी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। वन विभाग की, नदी नालों के बहाव क्षेत्र पर कब्जा कर उसे मलबे से भर कर साथ ही अन्य सरकारी जमीनों पर नगर निगम पालिकाओं के कर्मचारी और अधिकारी किसी भी मद से किसी भी नाम पर जल्दी से सरकारी पैसे से निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। यह शायद न तो जिलाधीश कार्यालय में बैठे तहसील के पटवारी, तहसीलदार, सहायक व उपजिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक को नजर नहीं आ रहा उस की आड़ में बड़े नेता मीडिया के भूमाफिया, जालसाज भूमाफिया, कालोनियां, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल, नर्सिंग होम्स, बड़े-बड़े शॉपिंग सेंटर का निर्माण कर वर्षों से चला रहे हैं. जिस में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ मिलकर अकेले इंदौर में ही नदी नालों से सटे हुए भूभागों पर 5000 से ज्यादा पक्के निर्माण जिसमें बहुमंजिला इमारतों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल नर्सिंग होम चल रहे हैं जो किसी को नहीं दिखते और जहां पर नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों से लेकर पटवारी और तहसीलदार बरसों से वसूली करते हुए एक ही स्थान पर जमे हुए हैं. जिसमें राजकुमार हलदार तहसीलदार को बैठे हुए बरसो हो गए इंदौर में जबकि लगभग नदी नालों की 5000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पूरे शहर के नदी नालों और शासकीय भूमि पर वर्षों से मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं जिसे ना तो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी बरसों बाद भी आंख उठाकर नहीं देखा क्योंकि सबसे मोटा महीना मिल रहा है। यही कारण है कि नगर निगम पालिकाओं परिषदों, पंचायतों में बैठे सचिन पंच सरपंच, पार्षद महापौर से लेकर पटवारी तहसीलदार सहायक जिला अधिकारी जिलाधिकारी और जिला अधिकारी नगर गृह विकास विभाग, विकास प्राधिकरणों मैं बैठे अधिकांश कर्मचारी, नेता इन जमीनों की हेराफेरी करोड व अरबपति बन चुके है। लोकायुक्त आयकर विभाग और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन नेताओं और कर्मचारियों सभी महीना मिलने के कारण कभी छापे मार कर अरबों करोड़ों की संपत्ति जप्त क्यों नहीं करता। पंचायत, परिषद निगम और पालिकाओं, प्राधिकरणों में यही कारण है कि चारों तरफ मची लूट के तांडव में सूचना के अधिकार में कोई जानकारी देना नहीं चाहता यहां तक कि इंदौर के निगम आयुक्त मनीष सिंह वल्द मोती सिंह यह वही मोती सिंह है जिन्होंने भोपाल की यूनियन कार्बाइड कांड में 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को अपनी जीप में बैठाकर भोपाल के हवाई अड्डे पर पहुंचा कर अमेरिका भगा दिया था और बदले में मोटी करोड़ों की धनराशि हजम कर गए थे इन्हीं के बेटे को इंदौर में बैठाकर पिछले कई सालों से तांडव करवाया जा रहा है. हर वर्ष कम से कम 100 से डेढ़ सौ करोड़ रुपए हजम किया जाता है. सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वालों को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता है और उन्हें ब्लैकमेलर बोलता है यह इसकी बदतमीजी का खुला प्रमाण इसके भ्रष्टाचार को सिद्ध करता है की है भ्रष्टाचारी महापौर मालिनी गौड, निगमायुक्त मनीष सिंह और निगम के 85 पार्षदों के साथ मिलकर किस प्रकार से चारों तरफ लूट का तांडव मचाए हुए हैं। वैध बस्तियों को स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ने का तांडव पिछले कई सालों से चल रहा है जिसमें हजारों परिवारों को बेघरवार कर बिना मुआवजा दिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और वहां नए निर्माण के नाम पर 5 से 20 गुना तक ज्यादा कीमतों पर स्तरहीन काम करवा कर मोटा धन महापौर निगम आयुक्त संबंधित पार्षद के साथ निगम इंजीनियर से लेकर बिल पास करने के वाले लेखाधिकारी से बाबू चपरासी तक सब की मुट्ठियां गर्म की जाती है. इसी तरह लूट का यह तांडव पिछले कई सालों से प्रदेश की हर नगर पालिका और निगमों में चलाया जाकर जन धन से लुटे गए धन को चुनाव जीतने के लिए खर्च किया जाता है। संपत्ति कर व अन्य सफाई कर विद्युत कर के नाम से जनता को लूटकर बनी बनाई सीमेंट की सड़कों का डामर की परतें चढ़ाई जाती कर जाकर मोटे बिलों की वसूली की जाती है जबकि इसके विपरीत कई मोहल्लों में बरसों से सड़कें बनी तक नहीं सफाई का तो दूर इंदौर के बाहरी इलाकों में की की कालोनियों में अभी तक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाई गई है जब नगर के अंदर कई मोहल्लों में एक ही खंबे पर 4-4 एल इ डी लाइट लटका दिये गए हैं। शहर के विकास के नाम पर स्तरहीन सड़कों, पुलों का का निर्माण कार्य 4 से 5 गुना कीमतों पर अपने चहेते भाई भतीजे ठेकेदारों को देकर करवाया जा रहा है शहर के अधिकांश सड़कों और पुलों की वर्तमान स्थिति को देखकर यह स्वयं सत्यापित किया जा सकता है वही हाल प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए गरीबों के आवास जोक कई गुना कीमतों पर स्तरहीन तरीके से बनाए गए हैं जिनमें उजाड़े गए हमरे वासियों को आवंटित किया गया है मालूम पड़ता है कि नए बने इन मकानों का पलस्तर से लेकर दरवाजे खिड़कियां, ऊपर की छत नीचे का तल तक सब अस्तव्यस्त और उखड़े हुए पाए गए।

सफाई के नाम पर भी वास्तविकता में जितने कर्मियों का भुगतान किया जा रहा है वास्तविकता में उसके 40% कर्मचारी ही जो की अधिकांश किसी न किसी नेता के चेले यह पट्ठे हैं । आराम से केवल हस्ताक्षर कर सालों से वेतन ले रहे हैं और सफाई के वास्तविक मजदूर जो 15 से 20-30 से ज्यादा वर्षों से सफाई कार्य कर रहे हैं वही वास्तविकता में सफाई कर रहे हैं उन्हें शासन के नियमानुसार ना केवल नियमित ही नहीं किया गया वरन् उन्हें आज भी कलेक्टर मजदूरी भुगतान दरें से कम पर भुगतान किया जा कर उनका घोर शोषण किया जा रहा है। जो कि 275 प्रतिदिन है उन्हें आज भी ठेकेदार मात्र रुपए 5000 से 6,000 ही मासिक मजदूरी का भुगतान करता है बाकी का धन नेता उसके पट्ठे, महापौर, निगमायुक्त, पार्षदों से लेकर लेखापाल और बाबू ही डकार जाते हैं। यह खेल भी नगरों की नगर परिषद से लेकर पालिकाओं और निगमों में पिछले 60 साल से निरंतर चल रहा है इसी से मोटी कमाई निगम में बैठे कर्मचारी अधिकारी पार्षद महापौर सभी करते आ रहे हैं. इसलिए कोई कुछ भी नहीं बोलता इन हरामखोर पालिकाओं परिषदों और निगमों में चुने हुए नेता और कर्मचारी अधिकारी यहीं से करोड़पति अरबपति बने हुए बैठे हैं। सफाई के नाम पर लूटपाट और भ्रष्टाचार का यह खेल अधिकांश पार्षदों महापौरों से लेकर सफाई ठेकेदार वह सुपरवाइजर तक सब के लिए 40 से ज्यादा वर्षों से मोटी कमाई का साधन रहा है।

12 वर्ष पूर्व सन 2006 में प्रोजेक्ट उदय के नाम से लगभग रुपए 800 करोड़ से ज्यादा का लोन एशियन विकास बैंक से लिया गया था जिसमें 600 नर्मदा के तृतीय चरण के लिए और रु 200 करोड़ मैं से लगभग रुपए सवा सौ करोड़ का 70 80 से ज्यादा लोडिंग ट्रक, 5000 साइकिल रिक्शा रु 25000 में प्लास्टिक की 8 बाल्टियों के साथ गली मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करने के लिए, 10 से ज्यादा गाड़ियां सक्सन मशीनों के साथखरीदी गई थी जो बरसों तक मूसाखेड़ी के मैदान में बिना उपयोग के धूल खाती रही बाद में अचानक धीरे धीरे कर सारा सामान गायब हो गया उस खरीदी में भी 10 से 15 परसेंट और किसी सामान में 20% तक मोटा कमीशन खाया गया और लगभग बंदरबांट में 50 करोड रुपए बंटने के के बाद भी वह सारा सामान कहां उपयोग किया गया आज तक कोई अता-पता नहीं और सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर निगम के हर विभाग में घोर बदतमीजी या कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा की जाती हैं। अपीलों की सुनवाई के नाम पर मुसाखेड़ी से अप्पर आयुक्त नगर निगम मैं चक्कर काटती रहती हैं और अंत में 3-4महीने बाद किसी दिन भुला कर बदतमीजी के साथ उल्टे सीधे सवाल कर अपील रद्द कर दी जाती हैं। मोदी के स्वच्छता अभियान के नाम पर पूरे देश और प्रदेश के हर नगर निगम,नगर पालिका परिषद मैं हूं कम से कम अपने प्रिय पूंजीपति मित्र टाटा की लगभग एक लाख से ज्यादा मिनी ट्रक कचरा ढोने के लिए खरीदे गए जिसमें 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे पालिकाओं और पंचायत तक बंदरबांट में हजारों करोड़ में बांटा गया। यथार्थ में यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होती है उन मिनी ट्रकों पर ड्राइवर से कंडक्टर और चार से पांच सफाई कर्मियों की नियुक्ति भी होती है इन नियुक्तियों में भारी भ्रष्टाचार होने के साथ ही सारी नियुक्तियां दैनिक वेतन भोगियों के हिसाब से भुगतान किया जाता है जिसमें अधिकांश कर्मचारी 12 से 15 घंटे काम करते हैं यहां भी प्रतिदिन 8 घंटे कि 275/- के साथ प्रतिदिन 4 घंटे ओवरटाइम की दोगुनी मजदूरी भुगतान किया जाना चाहिए साथ ही शुरुआत में दिन भर में हर 2 घंटे में सुबह 6:00 से रात में 12:00 बजे तक चक्कर लगता था वह घटते -घटते 9 से 5 और 3:00 पर आ गया अर्थात दिन भर के कि हर घड़ी के हर मोहल्ले में 5 गाड़ियों के हिसाब से प्रतिदिन हर गाड़ी पर 20 लिटर डीजल के पैसे मैं से जो 700 गाड़ियों पर 1400 लिटर, यही हाल इन गाड़ियों पर निगरानी रखने के लिए खरीदी गई सौ ज्यादा पीली जीपे इन पर लगभग 1000 लीटर प्रतिदिन, 200 से ज्यादा बड़े ट्रकों पर 30 लीटर प्रतिदिन, निगम की गाड़ियों के नाम पर औसतन 10000 लीटर डीजल की न्यूनतम की बंदरबांट जो कि लगभग 700000 प्रतिदिन डकारने में जाता है इसके साथ ही गाड़ियों के रखरखाव टूट-फूट के नाम पर भी भारी बंदरबांट निगम के वर्क शॉप से लेकर निधि चाहते गरीबों को भी लाखों रुपए का भुगतान किया जाता है जब तक इंदौर में नंबर वन के नाम पर जो निरीक्षण टीम दिल्ली से आनी थी। उसके नाम पर फरवरी के अंतिम सप्ताह में इंदौर में साफ सफाई की व्यवस्था का पाखंड किया गया और उस पर करोड़ों रुपए जनधन के बर्बाद किए गए । उस उस दिल्ली के निरीक्षण टीम के दौरे के बाद 1,2, 3 और 4 मार्च को उंगली ट्रकों का एक भी फेरा कई मोहल्लों में नहीं लगा अर्थात पेट्रोल डीजल का जो इस खर्च का लगभग दोगुना था। पूरा ही नेताओं कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा हजम कर दिया गया। इस स्वच्छता की कहानी का दूसरा रूप देखने में और भी भयावह है। केंद्र सरकार ने इश्क खरीदी के घाटे को पूरा करने के लिए हर सेवा पर 2:00 पर्सेंट सेवा उपकर पेट्रोल डीजल इंडेन गैस के साथ हर सेवा पर जीएसटी की तरह और साथ बिजली बिल टेलीफोन बिल रेलवे टिकट इंश्योरेंस प्रीमियम आदि में भी जोड़कर लाखों करोड़ रुपए की वसूली के रास्ते खोल दिए अब यही खेल स्वच्छता के नाम पर राज्य सरकारों ने खेला और उसने भी वसूली के स्वच्छता के नाम पर मै नए हथकंडे अपनाए इसमें राज्य सरकार ने अपनी वसूली के लिए शासकी शासकीय कार्यों के बिलों के भुगतान में अधिशेष जोड़ने के साथ निगमों पालिका और पंचायतों में भी अपनी वसूली के लिए आमजन पर नए कर दिए कहानी यह खत्म नहीं हुई। क्षेत्रीय सफाई ठेकेदार जो ट्रकों के साथ चलते हैं उन्होंने भी अपनी वसूली प्रति घर 60/-और प्रति दुकान छोटी सी रु 200 प्रतिमाह के साथ होटल, रेस्टोरेंट, बड़े व्यवसायिक संस्थानों संस्थानों स्कूलों-कॉलेजों, नर्सिंग होम हॉस्पिटल वर्कशॉप गैरेज आदि से मनमर्जी से हजारों रुपए प्रतिमाह सफाई के नाम लूट की जा रही है। अर्थात सफाई के नाम देश की जनता की चार तरफ से जेब साफ की जा रही हैं, और सफाई मोटी कमाई का साधन पंचायतों परिषदों निगमों से लेकर मंत्रियों मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए अरबो करोड़ की कमाई का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधन बन चुका है।

यही तरीका जनता को निचोड़ने का स्मार्ट सिटी के नाम पर भी केंद्र व राज्य शासन के लूट की कमाई के पाखंड का हिस्सा है । या इन सभी को लूट और भ्रष्टाचार का नया हथियार मिल गया है जिसमें केंद्र और राज्य का मोटा धन प्राप्त हो रहा है यहां तक की बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से कर्जा भी लिया जा रहा है इंदौर में ही जल निकासी के लिए नालियों और बड़े नालों का निर्माण के नाम पर सन 2000 से 2017 तक लगभग ?3000 करोड़ की बंदरबांट कर ली गई परंतु शहर में आज भी जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है यही हाल इंदौर में बने बीआरटीएस का भी था जिसमें लगभग रुपए 13 सौ करोड़ का भारी भरकम खर्च निगम और विकास प्राधिकरण ने किया जिसमें विवेक अग्रवाल से लेकर वर्तमान तक बैठे सभी जिलाधीशों, संभागायुक्त, निगमायुक्त महापौरों पार्षदों ने मोटी बंदरबांट की और इस तेरह सौ करोड़ में से निर्माणकर्ता कंपनी के साथ मिलकर लगभग 700 करोड़ डकार लिया गया। निसंदेह यह पैसा मीडिया के नगर के बड़े डकैतों को विज्ञापन के नाम बांटा गया इसलिए सब जानकर भी किसी ने कुछ नहीं छापा। जबकि 11 किलोमीटर सड़क पर रुपए 13 सौ करोड़ में सोने की परत बिछाई जा सकती थी. यह इंदौर की भ्रष्टाचार की विकास शैली पूरे देश और प्रदेश के हर जिले और नगर की कहानी का नमूना है। यही कारण है की गांव के पंच सरपंच से लेकर नगरों के पार्षदों और महापौर बनने के लिए व चुनाव जीतने के लिए साधारण सा नेता भी करोड़ों में खर्च करता है आखिर आयकर लोकायुक्त से लेकर सभी अन्य जांच एजेंसियां इन सब की घरों पर छापे मार कर इस अवैध धन को क्यों नहीं पकड़ती क्योंकि सत्ताधीशों को अगले चुनाव में चुनाव खर्च के लिए इन्हीं का सहारा होता है और सरकारी जांच एजेंसियों के कर्मचारी अधिकारी निरीक्षक सबसे महीना पाकर अपने को अहोभाग्य समझते हैं पूरे देश में मोदी सरकार नहीं जनता को लूट कर जो स्मार्ट सिटी की चकाचोंध बिखेरकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा उलझाया है निसंदेह आम गरीब आदमी से लेकर मध्यम वर्गीय और बड़े पूंजीपति तक सब भ्रमित हुए हैं अब मोदी रूपी डकैत की कहीं ना कहीं उसे शक करने से भी नहीं चूकते. जबकि अकेले सफाई और स्वच्छ भारत के नाम पर आम आदमी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर तरह से लूटा जा रहा है जिसमें महापौर निगमायुक्त से लेकर सड़क के सफाई कर्मी कचरा ढोने वाले वाहनों के सफाई कर्मी चरक तक सब हम गरीब आदमी को

...कारी नदी-नालों की जमीनों पर

लूटने और वसूली करने में लगे हैं. अकेले इंदौर में ही हर वर्ष रुपए 300 करोड़ से ज्यादा केवल सड़कों पर नवीनीकरण मरम्मत के नाम पर हजम कर लिया जाता है और बनी बनाई सीमेंट की सड़कों पर अनावश्यक रूप से डामर बिछा गिट्टी की बारीक चूरी की परत बिछाकर सड़कों को बर्बाद करने के साथ मोटे बिलों की वसूली कर ली जाती है. अभी कुछ वर्षो से सड़क सुधारने सीमेंट की सड़के बनाने के नाम पर जनता से भी भारी वसूली की जाती थी पूरे देश और प्रदेश के हर जिले और नगर में पिछले कुछ वर्षों से जल निकासी की नालियां बनाने के लिए उन सीमेंट की सड़कों को वापस खुदा और स्तरहीन पाइप लाइनों का जाल बिछाया जा रहा है जिसमें निगमों और पालिकाओं में बैठे भ्रष्ट, जालसाज, घोर निकम्मे वहां के उपयंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री तक किसी को कार्य को पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से करवाने की तो दूर देखने की भी फुर्सत नहीं जिसको जो मन में आ रहा है वह नेता का पट्ठा ठेकेदार अपनी मनमर्जी से करता चला जा कर आराम से मोटी बिलोकि वसूली कर रहा है जिसमें सबका कमीशन होता है. प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों जिला मुख्यालयों में किए गए सभी प्रकार के सड़क निर्माण भवन निर्माण पुल पुलिया निर्माण सरकारी निगमों के बड़े बहुमंजिला भवनों के निर्माण बाजारों के निर्माण आदि में किस प्रकार से लूट मची है उसको कोई देखने समझ नहीं और उसी गुणवत्ता पर ध्यान देने की मोटे कमीशन के चलते फुर्सत नहीं आखिर क्यों नहीं सभी नगर परिषद पालिकाएं और निगम सूचना के अधिकार की धारा 4 के अंतर्गत हर निर्माण कार्य से संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों से संबंधित, धन प्राप्ति और उसके खर्च और निवेश की जानकारी अपनी विभागीय वेबसाइट पर डालते और आय-व्यय का ठोस व पक्का वार्षिक लेखा जोखा व तलपट व चिट्ठा प्रदर्शित व प्रकाशित करते हैं. क्योंकि सारे गिद्ध हरामखोर पार्षद महापौर निगमायुक्त नगर यंत्री अधिकारी नेता भ्रष्टाचार से मोटी कमाई कर रहे हैं इसलिए इंदौर का मनीष सिंह सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर आवेदक को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता है ब्लैकमेलर कहता है क्योंकि सारे ब्लैक कर्मों से कमाई करने में लगे हुए हैं इसलिए हर जानकारी मांगने वाला इन शूकरों की फौज को ब्लैकमेलर ही दिखता है। निसंदेह सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वाला आवेदक, ऐसे भ्रष्टों की फौज का जानकारी मांग कर रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लेता है इससे ये सब डकैतों का गिरोह भारी हैरान परेशान हो उठता है.

निसंदेह स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे देश में और प्रदेश में बैठे बड़े बड़े मोटे ठेकेदारों जो कि बड़े नेताओं मंत्रियों के रिश्तेदार जो बड़ी ठेकेदारी कंपनियां चला रहे हैं या उनकी सीमेंट फैक्ट्रीयां है. या बड़ी योजनाओं, सड़कों पुलों के निर्माण में अरबों रुपए के ठेके देकर आसानी से 20- 25 परसेंट का मोटा कमीशन लेकर अपनी अगले चुनाव की तैयारी के लिए व अन्य कार्यों के लिए धन इकट्ठा करते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज की की पत्नी साधना सिंह के रिश्तेदार जो कि ठेकेदार भी है, दिलीप सूर्यवंशी जिसने शिवराज के रहते पिछले 12 सालों में ही हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी की, वैसे ही इंदौर के पी डी अग्रवाल व अन्य, कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियों के साथ ही बड़े निर्माण कार्यों में चीनी कंपनियों का भी देश और प्रदेश में बड़े ठेके दिए जा रहे हैं और उनसे मोटा कमीशन वसूला जा रहा है एक तरफ सरकार जनता से चीनी माल उपयोग न करने के लिए कहती है. वहीं दूसरी तरफ बड़े-बड़े अधिकांश ठेके चीनी कंपनियों को दिए जा रहे हैं यहां तक की देश व प्रदेश में लाखों करोड़ की चीनी लाइटों का उपयोग स्वंय निगमों पालिकाओं मे सस्ती और स्तरहीन स्ट्रीट लाइट के रूप में पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से किया जा कर हजारों करोड हजम किया जा रहा है. जबकि बिल सारे स्टैंडर्ड कंपनियों के लगा कर मोटा धन कमीशन के रूप में डकारा जा रहा है इस प्रकार से सरकार की स्मार्ट सिटी योजनाएं मोटी कमाई के साधन और गरीबों के लिए कहर बन कर सभी नेताओं के लिए लूटपाट का और भ्रष्टाचार से कमाई का स्त्रोत बन चुकी है जो कि चुनाव के साथ जनता को करोड़ों रुपए के भंडारे करवाकर कर साड़ी पायलें बांटकर और पुरुषों को चकाचक शराब का नशा करवा कर वोट कबाडने में काम के साथ चुनाव जीतने चुनाव जीतने और सत्ता हथियाने का जरिया बन जाती है. जबकि गिद्धों का यह गिरोह प्रदेश में पिछले 14 वर्षों से और देश में पिछले 4 वर्षों से जो लूटपाट का तांडव मचा रहा है उस पर कोई सरकारी एजेंसी कार्यवाही नहीं करती क्योंकि वह सत्ताधीश गिद्ध है इनका काम केवल जनता को नोचना और अपनी मौज मस्ती में जिंदगी गुजारना है गरीब का जन्म तो रो-रो कर मरने के लिए ही हुआ है यथार्थ में यह लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र है।चाहे वह स्मार्ट सिटी के नाम लूटा जाए, स्वच्छता के नाम, अच्छे दिनों के नाम देश के नाम लूटा जाए उसे दो वक्त का भोजन मिले ना मिले पर सरकार को सरकार में बैठे गिद्ध नेताओं मंत्रियों अधिकारियों कर्मचारियों की जेबों में धन अवश्य बरसते रहना चाहिए. उनके लिए कोई कानून नहीं कानून तो केवल आम आदमी के लिए होता है सत्ताधीशों ने तो स्वयं ही कानून बनाए हैं इसलिए कानून उन पर कैसे लागू हो सकता है.

प्रदेश का हजारों किसान कर्ज सेआत्महत्या कर रहा है दूसरी तरफ सरकार पुरस्कार ले रही है

मंत्री, प्रधान सचिव, संचालक से लेकर सभी कृषि अधिकारी डकैतों का गिरोह

ग्रामीण वोटों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के कृषि के भारी बजट 18-19 का छलावा

कृषि विभागः धूर्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन प्रधान सचिव राजेश राजोरा जो चारों तरफ से किसानों को नाम पर मोटी कमाई कमीशन से वसूल रहा है,

मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ पिछले कई सालों से कृषि कर्मण पुरस्कार या अवार्ड राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों प्राप्त कर रही है, और यह पुरस्कार प्राप्त कर अपने आप में वह फूले नहीं समाती. और प्रदेश के देश के मीडिया में अपनी वाह वाही के झूठे जन धन से अरबों रुपए के विज्ञापन छपवा कर अपने आप को महान समझती है। जबकि इसके विपरीत सच बड़ा- भयावह यह है कि प्रदेश में हजारों किसान हर वर्ष बिजली खाद बीज कीटनाशक दवाई खरीदने में जो कर्ज बैंक और साहूकारों से लेते हैं. उसका समय पर भुगतान न कर पाने के कारण हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ जाती है क्योंकि उसकी फसल का मूल्य अत्यधिक कम या प्राप्त ही नहीं होता है।जिससे उसकी खाद बीज कीटनाशक बिजली पानी जुताई हंकाइ की नगद लागत भी नहीं निकल पाती। उसकी व्यक्तिगत और परिवार की मेहनत-मजदूरी जो कि कलेक्टर रेट से भी जोड़ी जाए तो भी 4 महीने की रुपए एक लाख होती है मिलना तो दूर की कौड़ी है। जिससे वह समय पर बैंकों और साहूकारों का कर्ज न चुका सकने के कारण, घरेलू आवश्यकताओं के भोजन पानी बच्चों की शिक्षा की फीस किताबें कपड़े आदि के खर्च की भारी मानसिक प्रताड़ना को झेलते हुए आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। इस पर हर प्रदेश हजारों और देश में लाखों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। पर केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि मंत्री व अन्य नेतागण उल्टे सीधे बयानऔर भाषणों के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। इसके बीच पीछे का सच यह है केंद्र व राज्य शासन कृषि के नाम से जिन योजनाओं में धन आवंटित करते हैं उन योजनाओं का वह धन और लाभ किसानों तक पहुंचने के पहले बीच में बैठे राज्यों के कृषि मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक सहायक संचालकों से लेकर ग्रामीण स्तर पर बैठे कृषि विस्तार अधिकारी तक बीच में ही बंदर बांट कर 40 से 80% तक हजम कर जाते हैं। निसंदेह इस बंदरबांट में कमी आई है सारा वितरण व अनुदान का धन सीधे ही किसानों के खाते में जाता है परंतु सरकार की हर योजना का कर्मचारियों और अधिकारियों के पास पूरा तोड़ होता है। मनरेगा की तरह यहां भी कई फर्जी और खास लोगों के खातों मैं पैसा उनके खाते में स्थानांतरित कर हजम कर लिया जाता है। यही कारण है, कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर और जानकारी उल्टी-सीधी या न देने पर अपील करने पर संभाग स्तर पर बैठे संयुक्त संचालक जो इस बंदर बांट का सहभागी होता है जानकारी देने के नाम पर कई बार बड़ी मुश्किल से अपील की सुनवाई करता है और अंत में उसे रद्दी कर देता है। जबकि छोटे जिलों में सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उपसंचालक को ही उसका अपीलीय अधिकारी बनाकर सारे भ्रष्टाचार को छुपाने की और बचाने की कानूनन व्यवस्था कर दी। यही कारण है जिलों में बैठे उप संचालक कृषि और उद्यानिकी कभी अपनी जानकारी देने के लिए चिंता ही नहीं पालते। यही हाल धार और देवास में आवेदन देने की बाद के वहां बैठे भ्रष्ट और जालसाज उपसंचालकों सुभाष राजपूत पीएल साहू उन्होने तो आवेदन का न तोजवाब दिया और न ही अपील की सुनवाई की।इस घोर भ्रष्ट सुभाष राजपूत ने बैतूल के आदिवासी क्षेत्र में कृषि विकास के नाम खाद, कीटनाशक, बीज, तालाब, कृषि यंत्रों आदि के अनुदानों में करोड़ों रुपए के घोटाले किए। अपील लगाने पर यह हरामखोर भ्रष्टों की फौज कभी अपील की सुनवाई की दूर, बात भी नहीं करती। जबकि सरकार चाहती तो छोटे जिलों में कृषि उपसंचालक की सुनवाई जिले के जिलाधीश द्वारा करवा कर जिलों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करती। इसके संबंध में समयमाया ने लगातार प्रकाशन किया पर शासन में बैठे धूर्तों ने भ्रष्टाचार में हिस्सा डकारने के चलते,संशोधन की अपेक्षा कभी आंख उठाना भी उचित नहीं समझा। यही कारण है कि छोटे जिलों में वहां के धूर्त जिला उप संचालक कृषि कभी भी सूचना के अधिकार में जानकारी देने के लिए आवेदन पत्र का जवाब तक नहीं देते हैं। और अपील लगाने पर भी उसका जवाब भी नहीं देते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही उसके अनावेदक और अपीलीय अधिकारी होते हैं। इसलिए वह खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं और किसानों को उनके हक से वंचित रख कर उन्हें शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं व अनुदान का लाभ स्वयं या कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से कागजी खानापूर्ति कर अपने खास लोगों की खातों में स्थानांतरित करवा कर हजम कर जाते हैं। यही हाल पूरे मध्यप्रदेश के 51 जिलों के कृषि उपसंचालक को सहायक संचालक से लेकर गांव और ग्राम पंचायतों में बैठे कृषि विस्तार अधिकारी तक कार शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और बदले में किसान आत्महत्या कर रहा है।

पिछले बार के समय माया के समाचार पत्रों में छपा था कि किस प्रकार महाभ्रष्ट और दूध प्रधान सचिव राजेश राजोरा ने रु27/- प्रति किलो का ढेंचा या जैविक खाद रुपए 125/- प्रति किलो में खरीद कर आदिवासी 15 जिलों में आदिवासी किसानों को सरकारी खर्च पर मुफ्त में और अन्य जिलों के किसानों को 50% अनुदान पर बेचा गया था। यही हाल मृदा परीक्षण किट का भी हुआ जो कि बाजार में मात्र रु 5000 की थी उसे सरकार के माध्यम से ही 10000 किट रु1लाख5हजार में खरीद कर शासन को लगभग रुपए 100 करोड़ का चूना लगाकर ग्रामीण कृषि अधिकारियों को आवंटित की गई साथ ही उसमें लगने वाले अन्य रसायनों जो कि मृदा परीक्षण में काम आते हैं, भी खरीदे गए। उसमें भी लगभग रुपए 50 करोड का भ्रष्टाचार किया गया। यही हाल किसानों को खरीफ और रबी की फसलों के लिए बीज के हैदराबाद से क्रय करने में भी किया गया। उसमें भी लगभग रुपए 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करके हजम किया गया। यह सब तथ्य पूरे मध्यप्रदेश को समाचार पत्रों के माध्यम से जो छोटे समाचार पत्र साप्ताहिक रूप से निकलते हैं। उन्होंने ही प्रकाशित किया था। परंतु मुख्यमंत्री को शिकायत किए जाने के बाद में भी मोटा पैसा मिलने के कारण उसकी जांच नहीं की गई। इसी संबंध में जब इंदौर उज्जैन धार देवास जिलों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो स्पष्ट किया गया कि हम लोग कुछ भी खरीदी नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी बिल बाउचर का या आपूर्ति आदेश का सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं दी जा सकती। जबकि सच यह था के आदेश भोपाल से निकलने के बाद जिलों में सीधे ही वह आदेश के माध्यम से रवि और खरीफ का बीज सोयाबीन, गेहूं व अन्य फसलों का स्तरहीन विस्तार था किसानों को मध्य प्रदेश की सभी जिलों में आपूर्ति की गई।और किसानों से सीधे ही उसकी आधी कीमत वसूल कर आधा पैसा उसे खाते में स्थानांतरित कर बीच का 40% कमीशन राजेश राजौरा से लेकर जिलों में बैठे उपसंचालक, सहायक संचालक, जिन्होंने कृषि अनुदान किसानों के बैंक खाते में अंतरित किया कृषि विस्तार अधिकारी आदि के माध्यम से हजम कर लिया गया। इंदौर में मैं बैठे विजय चौरसिया जो पूर्व से ही अपने भ्रष्टाचारों के लिए कुख्यात रहे हैं और कई बार निलंबित हुए। कार्यवाही को रोकने के लिए हर बार राजेश राजौरा को मोटा लाखों रुपए का धन देकर बचते आए हैं। उन्होंने भी देवास की कृषि बीज उत्पादक सहकारी समितियों से वीज न खरीद कर गेहूं की खरीद हरदा से भी की थी जिसमें भी लाखों रुपए का मोटा कमीशन हजम किया गया। इस संदर्भ में इसकी शिकायत किए जाने पर विजय चौरसिया को निलंबित कर भोपाल स्थानांतरित भी कर दिया गया था। परंतु इस घाघ भ्रष्ट अधिकारी ने अपनी लूट की कमाई में से कुछ टुकड़े लाखों रुपए के राजेश राजौरा के सामने फेंक पुनः अपनी नियुक्ति इंदौर में करवा ली।जबकि सूत्रों के अनुसार देवास में बैठे उप संचालक सुभाष राजपूत ने इसके लिए रुपए 30 लाख की बोली लगा दी थी। विजय चौरसिया ने अपने लूट के ऐसे हिस्से में से पुनः बड़ा हिस्सा देने का वादा कर पुनः इंदौर में नियुक्ति प्राप्त कर ली। आखिर इंदौर में इतना मोटा धन खर्च कर जिला उपसंचालक बनने के लिए अधिकारी क्यों इतने बेताब रहते हैं इसके पीछे कारण है कि इंदौर में ही पूरे प्रदेश की सबसे ज्यादा बीज, खाद, कीटनाशक विक्रेता कंपनियों के प्रदेश मुख्यालय हैं जो राजेश राजौरा और कंपनियों के बीच मोटे कमीशन के लिए संपर्क सूत्र कार्य करते हैं। स्वाभाविक है उन्हें भी मोटा कमीशन हाथ लगता है इसलिए प्रदेश के अधिकांश उपसंचालक इंदौर के उपसंचालक बनने का मोटा धन खर्च करके सपना देखते हैं। वैसे भी प्रधान सचिव राजेश राजोरा अपने कर्मचारियों अधिकारियों को पहले भ्रष्टाचार की खुली छूट देता है। उसमें से मोटा हिस्सा डकारता है शिकायत होने की जांच बैठाई जाने पर नोटिस जारी करता है निलंबित करता है और बदले में बहाली के लिए फिर मोटी लाखों में धन राशि हजम कर जाता है। निसंदेह उसकी पहुंच मुख्यमंत्री की रसोई तक है भाभीजी ही सारा लेन देन करती हैं यथार्थ में मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज नहीं वरन भाभी जी ही चलाती हैं। जब इस सच को कुछ कांग्रेसी नेताओं मुख्य रूप से के के मिश्रा ने हीं उजागर किया तो महाधूर्त और भ्रष्ट निकम्मे शिवराज ने हीं उसके ऊपर न्यायालीन प्रकरण लादकर डराने धमकाने की भारी कोशिश की जिसका साथ स्वयं कांग्रेसियों ने भी कभी नहीं दिया। यथार्थ में सरकार द्वारा आवंटित धन का सदुपयोग किसानों की अपेक्षा कृषि विभाग में बैठे हुए मंत्री प्रमुख सचिव से लेकर जिलों में बैठे उपसंचालक और गांव में बैठे कृषि विस्तार अधिकारी तक सही ढंग से कर रहे हैं.मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में वैसे तो हर दिन ही भ्रष्टाचार के नए-नए किस्से कहानियां आते ही रहते हैं दिनांक 3 मार्च 2018 को धार के उपसंचालक पी एन साहू रंगे हाथों रु 25000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए। बेशक बे भी मोटा धन खर्च कर वापस लोकायुक्त के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे क्योंकि उन्होंने धन को बाजू के ड्रावर पर रखवा लिया था वैसे ही साहू जी का सेवानिवृत्ति काल भी निकट आ चुका है पर यह कहानी केवल इंदौर या उज्जैन संभाग की नहीं वरन पूरे मध्यप्रदेश के हर जिले की है, क्योंकि हर जिलों में उपसंचालक के पद पर उन्हीं लोगों को बैठाया जाता है जो भारी भ्रष्ट होते हैं और नियुक्ति के लिए भारी मोटा धन खर्च करते हैं।अब जबकि नियुक्ति में ही हर उपसंचालक को मोटी भैंट प्रधान सचिव को चढ़ानी पड़ती है तो स्वाभाविक है कि वे पहले सहायक संचालक रहते हुए भारी धन कमा चुके हैं तभी उपसंचालक की नियुक्ति के लिए मोटा धन खर्च कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग में निकम्मे और जालसाजों की भरमार

मुख्य अभियंता शर्मा घोर बदतमीज और जालसाज

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर, कदम कदम पर बदतमीजी और जालसाजियां, जानकारी न देने के लिए नए-नए हथकंडे

मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग यूं तो शुरु से ही घोर भ्रष्ट, निकम्मे और जालसाज अधिकारियों व कर्मचारियों का बड़ा अड्डा रहा है। जिसमें प्रधान सचिव से लेकर सचिव, प्रमुख अभियंता मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री सहायक यंत्री व निचले स्तर पर कार्य करने वाले उपयंत्री व बाबू तक घोर भ्रष्ट, निकम्मे, जालसाज, मक्कार, कामचोर होते हैं, बेशक प्रधान सचिव जुलानिया के आने के बाद इस विभाग में काफी कुछ सुधार आया था परंतु उन्हें बीच में स्थानांतरित कर ग्रामीण विकास विभाग में भेज दिया गया जिससे यह विभाग अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया और उसी शैली में पुनः कार्य संपन्न किया जाने लगा। प्रधान सचिव जुलनिया की शक्ति से घबराकर उन्हें जल संसाधन विभाग में डाल दिया गया पर उनके आने के बाद भी वर्तमान में ढर्रा सुधरने का का नाम नहीं ले रहा। बेशक इसके पीछे जो कारण है, कि 90% लिपिकीय स्टाफ अपने स्थान पर पिछले 15 से 20 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठा हुआ है जबकि इन सब का भी स्थानांतरण हर 3 साल में हो जाना चाहिए जैसा कि कानून है परंतु स्टाफ की कमी के कारण और छोटे पद पर होने के कारण शासन ऐसा नहीं कर सकता इसलिए यह बाबुओं की फौज न केवल मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग में वरन शासन के 95% विभागों में अपनी जगह जमें रहकर न केवल भ्रष्टाचार करते हुए निकम्मेपन का प्रदर्शन करती है साथ ही जिन कार्यों को करने में उसे कोई आर्थिक सामाजिक व अन्य प्रकार का लाभ नहीं होता। उस कार्य को करने में सदा ही टाटा टूली करती रहती है। फ़ाइलें, कागज, दबाना, कार्य को लटकाना यह उसके प्रिय शगल होते हैं।इससे यथार्थ में जनता को जो परेशानी होती है । उससे शासन की भी उतनी ही बदनामी होती है। वहां तक तो ठीक था परंतु सबसे ज्यादा परेशानी वहां स्थानांतरित होकर आने वाले इंजीनियरों व अन्य अधिकारियों को होती है। वे बेचारे नई पदस्थापना होने पर नए विभाग में जाकर इन्हीं बाबूओ के आश्रित होता है।यह बाबू, उपयंत्री, सहायक यंत्री, अपनी कमाई न होने और काम के बोझ से बचने के लिए जानबूझकर अपने कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, प्रधान सचिव तक को भारी गुमराह कर केवल अपने मतलब के कामों को पहले सिद्ध करते हैं। जहां उन्हें मोटा धन मिलता हो। वहां सबसे पहले कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और जहां धन नहीं मिलता है या जहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो। वहां पर वह फाइलों को दबा कर रख देते हैं और मजबूरी में अगर करना भी पड़ जाए तो भी फाइलों में शब्दों का हेरफेर कर उल्टी-सीधी टिप्पणी कर देते हैं। ताकि काम अटक जाए और बड़ी-बड़ी परियोजना से लेकर व्यक्तिगत स्तर के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के काम अटका दिए जाते हैं। बेशक बड़ी परियोजनाओं में जानबूझकर काम को लंबित करना धीरे-धीरे कार्य करना करवाना आदि के कारण राज्य व केंद्र सरकार के सभी निर्माण विभागों में हजारों करोड़ों रुपए प्रति वर्ष का घाटा इसी कारण होता है के वहां का स्टाफ, ठेकेदारों से मोटे लाभ के लिए जिसमें मूल्यवर्धित होने से अधिकांश परियोजनाओं की कीमतें सामग्री, मजदूरी की कीमतें बढ़ जाती है और इसका लाभ ठेकेदारों के साथ विभाग के लोग भी दोनों हाथों से कमाकर लूटते हैं। इससे केवल जल संसाधन ही नहीं वरन,प्रदेश के साथ, पुरे देश के सभी सरकारी कार्यालयों का हाल है। उस पर फिर सूचना का अधिकार का आवेदन देखते ही मानो इन सभी कर्मचारियों अधिकारियों को सांप सूंघ जाता है उनका बस नहीं चलता वरना उस आवेदक को कमरे में बंद करके हमेशा के लिए यमलोक पहुंचा दें। यथार्थ में सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वाले देश की सरकार का और जनता का ही बड़ा फायदा करता है। परंतु वह सभी शासकीय विभाग के हर अधिकारी कर्मचारी की आंख का मोटा कांटा होता है जो कि उनकी दुखती रग पर जानकारी मांग कर हाथ रख देता है । मुख्य अभियंता नर्मदा ताप्ती कछार कार्यालय में बैठे उप लोक सूचना अधिकारी और वहां बैठे घोर भ्रष्ट जालसाज बड़े बाबु व्यास जो कि स्थापना कार्य का पूरे इंदौर उज्जैन के15 जिलों के 17 संभागों के कर्मचारियों- अधिकारियों का स्थापना कार्य देखता है। हर कार्य के लिए जिसमें स्थानांतरण नियुक्ति पदस्थापना समय मान, वेतन मान, दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ती व नियमितीकरण आदि हर कार्य में उसे धन की आवश्यकता होती है बिना धन के वह कार्य अटकाता रहता है। जिसका साथ अवैध रूप से सेवानिवृत्ति के बाद बैठाये गये एस के पवार जो कि विभाग का विधि कार्य देखता है साथ ही विभाग के न्यायालयीन संबंधी प्रकरणों, जिनमें क्षतिपूर्ति, ठेकेदारों के विवाद कर्मचारियों के प्रकरण आदि हैं। ,जिसे हिंदी में ढंग से चार लाइन शुद्ध हिंदी नहीं लिखते बनती, भी अपना मोटा कमीशन लेकर पूरा करते हैं । इसलिए सूचना का अधिकार में दिए गए आवेदनों को यह बाबू व्यास धारा 6(3) के अंतर्गत ना केवल अंतरित नहीं करता वरन आधी अधूरी जानकारी देकर आवेदक को भ्रमित करने के साथ ही उसके आवेदनों के जवाब को नोटिस बोर्ड पर टांग देता है जबकि

उसकी सूचना डाक के माध्यम से आवेदकों को की जानी चाहिए। परंतु यह कामचोर आगे आवेदक पैसे जमा करके जानकारी न मांग ले इसलिए उसे डाक से नहीं भेजा जाता। जैसे शासन का धन इनके बाप की जागीर हो और ये बहाना लेकर कि उसमें रु 5/- का टिकट लगा लिफाफा नहीं था।जबकि जो आवेदक उसे लिफाफा देते हैं। वह जानबूझकर जानकारी ना देन पड़े फाड़ कर फेंक देते हैं। उस आवेदन के जवाब को अपने नोटिस बोर्ड पर टांग कर इतिश्री कर लेते हैं।

दूसरी तरफ हर विभागीय कार्यालय के हर इंजीनियर और अधिकारी को शासन के वाहन का उपयोग करने की लॉग बुक, टूर डायरी किस कार्य के लिए कब कहां शासन के वाहन का उपयोग किया। स्वयं भी रखने के साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। जिसका उल्लेख शासकीय कार्य पद्धति में स्पष्ट है और हर शासकीय विभाग में अधिकांश अधिकारी कर्मचारी शासन के वाहन का उपयोग करने पर उसकी लाग बुक टूर डायरी अपने वरिष्ठों को प्रेषित करते हैं। इसकी जानकारी मांगने पर यह विभाग लिखता है, कि हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि यह कार्य आवश्यक रूप से हर विभाग को करना पड़ता है। जो कि कार्य पद्धति के अंग होने के साथ ही यह बताता है की किस दिन कौन सा कार्य किया गया वह उसके लिए वाहन का कितना और कहां पर किया गया।क्योंकि उपयोग किया गया वाहन अपने बाप की व्यक्तिगत जागीर नहीं जिसे आप मनचाहे तरीके से सरकार का जो कि जनता का धन उपयोग करती है। पेट्रोल डीजल फूंकते हुए अपनी मनमर्जी से अपने परिवार, सहेली और मित्रों को लेकर घूमते फिरते रहे। और उसका भुगतान शासन के खाते से होता रहे। वर्तमान में अधिकांश विभागों में, किराए की टैक्सियां लगाई जाती हैं इसमें भी भारी घोटाला और भ्रष्टाचार किया जाता है अधिकांश टैक्सियां विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की ही होती है। जिन्हें वो दूसरे नाम से शासकीय कार्यालय में लगाकर, शासन के नियमों के विपरीत उच्च किराए पर रखवा दी जाती हैं। जिसमें पेट्रोल-डीजल सरकार का ही होता है। साथ ही ड्राइवर भी सरकार का ही होता है। उस प्रकार से टैक्सियों के नाम पर अधिकारी कर्मचारी मोटी कमाई करते रहते हैं। शासकीय कार्यालयों में संलग्न की गई कारे यथार्थ में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होने के साथ ही वाहन चालक को व्यवसायिक वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारी होना चाहिए। जानकारी मांगने पर और न मिलने पर या उल्टा सीधा जवाब देने पर अपील लगाने पर वह धूर्त मुख्य अभियंता वाय सी शर्मा बहुत ही बदतमीजी से कहता है की आवश्यक नहीं कि जानकारी दी जाए आपको। बेशक शर्मा जी वर्तमान में जिसमें मुख्य अभियंता के पद को सुशोभित कर रहे हैं। शायद भूल गए होंगे कि वह लड़ाई सामान्य वर्ग की समय माया नहीं ने ही लड़ी थी।अन्यथा सहायक यंत्री रहते हुए ही सेवानिवृत्त हो जाते। जैसे कि अनेकों सामान्य वर्ग के सहायक यंत्री एक ही पद पर नियुक्ति से सेवानिवृत्त हो गए।फिर शर्मा जी को ऊचे पद पर बदतमीजी कूट-कूट कर भरी होने के साथ-साथ पद का बड़ा घमंड है। परंतु जब सूचना का अधिकार में इनकी लॉग बुक की कॉपी, टूर डायरी, निरीक्षण कंडिका की कॉपी मांगी गई। तो बचने के लिए मात्र मांगी, बचने के लिए मात्र पूर्व मुख्य अभियंता डाबर की निरीक्षण रिपोर्ट की कॉपी के 10 पन्ने रुपए बीस जमा करवाकर दे दिए गए।जिसमें मात्र 2 माह के निरीक्षण रिपोर्ट थी। जबकि आवेदक ने 6 माह के पूर्व अभियंता कि दिसंबर तक की और 2 माह की वर्तमान मुख्य अभियंता शर्मा की निरीक्षण रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी जबकि हर मुख्य अभियंता को महीने में

10 दौरे और निरीक्षण रिपोर्ट देना आवश्यक है। परंतु जालसाज मुख्य अभियंता शर्मा ने अपने निरीक्षण रिपोर्ट व टुर डायरी नहीं दी। वैसे शर्मा जी हर कार्य में अपने अधीनस्थों को नियम कायदे कानून सिखा कर बहुत ही बदतमीजी दिखाते हैं। डांटते डपटते और मोटी वसूली करते हैं। अपील लगाने पर मुख्य अभियंता ने अपने पद की गरिमा के विपरीत बड़े निम्नता से व्यवहार करते हुए आवेदक को उसके आवेदन की मूल वस्तु को ध्यान देने की अपेक्षा अपील को उल्टे सीधे तरीके से देखकर खारिज कर दिया। क्योंकि मुख्य अभियंता का इतिहास वर्तमान का ही नहीं बरन पुराना भी है।की वह बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार करके अपना रोब हर किसी छोटे अधिकारी व कर्मचारी पर कर यथा योग्य वसूली कर लेते हैं। वैसे इस विभाग में किसानों को खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए जिन तालाबों, बांधो, नहरों आदि के निर्माण कार्य किए जाते हैं उसमें कोई भी कार्य कभी समय पर पूरा नहीं होता इसकी आड़ में समय वृद्धि, मूल्य वृद्धि आदि का मोटा खेल होता है जिसमें ठेकेदार के साथ मिलकर उपयंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री से लेकर यदि अधिक राशि का बांध है तो ऊपर तक कमीशन पहुंचता रहता है दूसरी तरफ कोई भी कार्य कभी भी पूर्णत; मैनुअल के हिसाब से नहीं किया जाता। हाल ही में देवास में कन्नौद के पास बनाए दतुनी बांध में भी जो कि रुपए 180 करोड़ का था मुआवजा बांटने से लेकर बांध निर्माण और नहरों के निर्माण में भी भारी अनियमितता की गई और मोटा धन पूर्व कार्यपालन यंत्री हरिनारायण गुप्ता, बाद में मुकेश चतुर्वेदी के साथ सहायक यंत्री येवले उपयंत्रियों, बड़े बाबू पारीक ने मैं भी मोटा धन डकारा ।इसलिए पिछले 4 सालों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हर बार कोई न कोई बहाना लेकर जानकारी अटकाइ जाती रही ।

समय माया के प्रतिनिधि ने जो दतुनी नहर के फोटो लिए जिसमें स्पष्ट दिखता है कि जो नहर बांध से निकलकर कन्नौद तहसील में नेशनल हाई वे 59अ को जहां पर क्रोस करती है। एक तरफ नहर व्ही आकार में काटकर कंक्रीट की गई है, जबकि उसका भी ढाल पर जो गिट्टी डाली गई है उस पर वर्म के नाम परकुछ भी नहीं है इस सीधी गिट्टी और मिट्टी नहर के तल पर बैठेगी। दूसरी तरफ जो नहर काटी गई है उसमें नहर के व्ही के तरीके से काटने की अपेक्षा, सीधा काटकर तल पर कंक्रीट कर दिया गया है अर्थात इसमें भी भारी भ्रष्टाचार किया जा कर पैसा लाखों रुपए हजम किया गया। उज्जैन में शिप्रा की गंदगी को अलग से बहाने के लिए 18 किलोमीटर लंबी जो पाईप लाईन डाली गई वह भी पूर्ण असफल रहा और उसका पानी भी क्षिप्रा में मिल रहा है। खरगोन में बैठा अधीक्षण यंत्री भगोरा जो पिछले 25 सालों से पहले एसडीओ फिर कार्यपालन यंत्री और अब अधीक्षण यंत्री बना मोटे धन के बद्ले ही बैठाया गया है।यदि इस के कार्यकाल की जांच की जाए तो भगोरा ने सहायक यंत्री रह्ते हुए खरगोन में करवाए गए कार्यों में ठेकेदारों से मिलकर न केवल स्तरहीन कार्य करवा कर मोटा धान हजम किया। वरन कार्यपालन यंत्री रहते हुए भी सन 2002 से सन 2010 तक एक ही कार्य के कई बार टेंडर लगाकर बांधों और नहरों के निर्माण कार्यों में काफी भ्रष्टाचार किया जिसकी रिपोर्ट ऑडिट में भी हुई। पर जुलानिया ने अपने लंबे कार्यकाल में भी उसे न केवल कोई आरोप पत्र तक नहीं दिया वरन उसे पदोन्नत कर वहीं पर मोटे धन के बदले पुनः पदस्थ कर दिया। यही कारण है कि यह हरामखोर कभी भी सूचना के अधिकार में जानकारी देने की तो पत्र का जवाब भी नहीं देता। अब जबकि उसके पास खरगोन के साथ बड़वानी खंडवा बुरहानपुर आदि संभाग भी हैं। अंदाज लगाया जा सकता है की प्रधान सचिव जुलानिया के रहते इन चारों संभागों में कार्य को कैसे संपन्न किया जा रहा होगा। फिर क्या मजबूरी है कि एक व्यक्ति एक ही जिले में 25 साल पूरे कर ले और वह भी सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री रहते हुए। इस कार्यशैली से पाठकगण समझ गए होंगे कि आखिर इस जल संसाधन विभाग में सभी किसानों के खेतों की सिंचाई के नाम कैसे अपने बैंक खाते सींचते रहते हैं। यह हाल पूरे मध्यप्रदेश के सभी संभागों अधीक्षण यंत्री कार्यालयों मुख्य अभियंता कार्यालय से लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तक के हैं।

नगर तथा ग्राम निवेश शासकीय भूमाफियाओं जालसाजों और भ्रष्टों का अड्डा

शासकीय अवैधानिकता को शासकीय वैधानिकता देने वाले जालसाजों का गिरोह

2011-12 के बाद से विभाग की 17 बिंदुओं की जानकारी, अपग्रेड नहीं की गई, 11-12का हीं आवंटन ही दिखाया जा रहा है वेसे विभाग की साइट खुलती ही नहीं है। निगमों पालिकाओं के आवंटन से लेकर मकानों दुकानों कालोनियों आदि के निर्माण में हर कदम वसूली मे करोड़ों की कमाई में चपरासी से प्रधान सचिव तक शामिल।

नगर एवं ग्राम निवेश का पूरा विभाग धूर्तो, जालसाजों और डकैतों से भरा हुआ है, इस विभाग में सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर सारे जालसाज जिन्होंने कदम कदम पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर हर नगर महानगर में कदम कदम पर जालसाजी पूर्ण तरीकों से भूमाफियाओं के साथ मिलकर और वैध -अवैध तरीके से कॉलोनियां, मकानों, बड़ी बहुमंजिला इमारतों शॉपिंग मॉल हॉस्पिटल नर्सिंग होम का निर्माण सड़कों की चौड़ाई कम करना, हरित क्षेत्र की भूमि, पार्किंग व अन्य कार्यों की भूमि कम करना, आदि मे ही में भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए की कमाई कर स्वयं की करोड़ों की संपत्तियां बनाई है।जानकारी देने की अपेक्षा स्पष्ट लिख देते हैं, कि ये जानकारी दी जाने योग्य नहीं है। अपील लगाने पर, प्रधान कार्यालय में बैठा हुआ संयुक्त संचालक वीएम त्रिपाठी क्योंकि सबसे वसूली करता है। इसलिए वह हरामखोर एकमुश्त अपीलें रद्द कर देता है। और उसके बदले में भी मोटी राशि अनावेदक से वसूली की जाती है।इसलिए जानकारी मांगने पर कोई जानकारी नहीं दी जाती और इंदौर कार्यालय में तो भ्रष्टाचार और लोकायुक्त के छापे के कारण, वहां बैठे धूर्त मक्कारों बाबू की फौज किसी को भी बिना जान पहचान के अंदर नहीं जाने देती है। यहां बैठा घोर धूर्त और जालसाजी बाबू टेकचंदानी जो वर्षों से इंदौर में जमे रहकर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर चुका है। स्वभाविक है धन के मद में चूर किसी को कुछ नहीं गिनता जो कि सूचना का अधिकार देखता है हर अभी तक को सूचना का अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा हर आवेदन के जवाब में केवल जानकारी दी जा सकती अत्यधिक है कहकर और लिखकर इति श्री कर ली जाती है बदले में अपील लगाने पर मुख्यालय में बैठा संयुक्त संचालक बीएम त्रिपाठी हर अपील को बहाने बनाकर और मोटा धन वसूल कर पूरे प्रदेश की अपीलो को रद्द कर देता है। भ्रष्टाचार के धन के गुरुर में चूर, आवेदक से तो बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं।

सूचना के अधिकार में अपलोड की जानेवाली धारा 4 की जानकारी जो कि मंत्रालय से डाली गई थी वह भी सन 2011 12 की है उस समय इसके मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी भर दी गई है। तब से अभी तक अनेकों कर्मचारी अधिकारी स्थानांतरित हुए सेवानिवृत्त हुए किसी की भी जानकारी अपडेट नहीं की गई साथ 8-9, 9-10, व 11 12 के आवंटन के पूरे मध्यप्रदेश के नगर निगम पालिकाओं और परिषदों को दिए गए उस आवंटन की की जानकारी लोड की गई है। तब से अभी तक 7 सालों में जो आवंटन नगर निगम पालिका और परिषदों को दिए गए उनकी कोई जानकारी जानबूझकर भ्रष्टाचार छुपाने के लिए अभी तक अपलोड नहीं की गई वैसे विभाग की साइट नहीं खुलती है मंत्रालय में जो अन्य विभाग हैं उनके अंतर्गत इस विभाग की केवल धारा 4 के 17 बिंदु की जानकारीही तब से अपलोड है जबकि यथार्थ में अरबों रुपए जै एन आर यू एमके अंतर्गत व अन्य योजनाओं के अंतर्गत केंद्र से प्राप्त हुए व राज्यों की अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धन के बारे में अभी तक कोई जानकारी इस साइट पर अपलोड नहीं की गई ताकि आमजन यह जानकारी प्राप्त कर संबंधित निगमों पालिकाओं और परिषदों से पूछताछ ना कर सके और यह धन आसानी से निगमायुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी महापौर वह परिषद के अध्यक्ष के साथ पार्षद व वहां बैठा घोर धूर्त स्टाफ आसानी से हजम कर सके। इस साइट पर केवल मुख्यालय की ही थोड़ी सी जानकारी दी गई है जबकि धारा 4 के अंतर्गत हर परिषद पालिका और निगम को अपने यहां की इस विभाग द्वारा विकास के लिए तैयार, स्वीकृत किए गए हर नक्शा जो कि व्यवसायिक भवन, बहुमंजिला भवनों कालोनियों की, आदि सबको साइट पर लोड किया जाना चाहिए। जो कि मुख्यमंत्री शिवराज के बार बार यह घोषणा करने की सारा काम कंप्यूटराइज होने लगा है प्रदेश में की घोषणाओं पर करारा तमाचा है यथार्थ में यही पर भूमाफिया बड़े-बड़े अरबों के घोटाले इन्हीं नगर व ग्राम निवेश के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर करते हैं यदि यह सब जानकारियां तत्काल में विभाग की साइट पर लोड होने लगे तो संबंधित और पीड़ित व्यक्ति जांच करके उसी वक्त शिकायत कर अवैध कार्यों को रोक सकते हैं इसलिए यह जानकारियां कभी लोड नहीं की जाती।

पूर्व के साथ वर्तमान के प्रधान सचिव मलय श्रीवास्तव सचिव विवेक अग्रवाल से लेकर आयुक्त सह संचालक,मुख्य अभियंता और संभागों में बैठे संयुक्त संचालकों, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री जिलों में बैठे हुए सहायक संचालकों से नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों के साथ मिलकर पटवारी, तहसीलदार, सहायक जिलाधीश, उप जिलाधीश, और जिलाधीशों, निगमायुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पार्षदों, महापौरों के संयुक्त माफिया ने अपनी कमाई के लिए पर्यावरण और शहरी विकास के आधारभूत सिद्धांतों को त्याग भूमाफियाओं से मिलकर सरकारी जमीनों के साथ नदी नालों, पड़त, नजूल भूमि, ग्राम भूमि, कृषि भूमि, वन भूमि, मत्स्य पालन व अन्य विभागों की भूमि के नक्शों में हेर फेर कर बड़ी-बड़ी कालोनियां, चिकित्सालय, नर्सिंग होम्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, फैक्ट्रियां व अन्य निर्माणों में अवैध रूप से नगरों, शहरों और महानगरों में खड़ी करवा दी यह इतिहास प्रदेश के हर जिले हर संभाग और पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश का ही है जहां इस विभाग के 99% कर्मचारी, अधिकारी भ्रष्टाचार से मोटी कमाई के चक्कर में नियम-कानूनों और भविष्य की नगरीय व्यवस्थाओं को बलाये ताक पर रखकर तत्काल लाखों से करोड़ों रुपए की कमाई के लिए कानूनों में हेरफेर कर सब कुछ कर गुजरे और गुजरने को तैयार रहते हैं। निसंदेह इंदौर, उज्जैन, भोपाल ग्वालियर, जबलपुर सागर रीवा आदि संभागों में बैठने के लिए हर संयुक्त संचालक मोटी रकम खर्च कर ही बैठने के लिए योग्य हो पाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो कोई मोटी रकम खर्च करेगा तो कहां से खर्च करेगा वह वह धन उसने पूर्व में सहायक संचालक रहते हुए ही कमाया हुआ तभी तो संयुक्त संचालक पद पर बैठने के लिए मोटी रकम खर्च कर मोटी रकम कमाने ही तो आया है।इस विभाग में भ्रष्टाचारों और जालसाजियों का हर कदम पर अंबार लगा ही हुआ है इसके अतिरिक्त भी यहां अय्याशी के दम पर बहुत सारे कर्मकांड होते रहते हैं।

जिसमें अनीता करोठे इसका शादी से पूर्व नाम अनीता विल्सन था, जो हाल ही में लोकायुक्त चंगुल में फंसी थी। के भी मोटे कांड भर्ती से लेकर अभी तक सामने आए हैं यथार्थ में यह महिला मात्र मानचित्रकार थी और सामान्य वर्ग की ईसाई भोपाल निवासी थी। पर बंदी ने अपना फर्जी आदिवासी का प्रमाण पत्र ग्रामीण निवासी बता आदिवासी बन कर अपनी कमनीयता के दम पर, झूठा प्रमाण पत्र बनवा कर पहले नौकरी हथियाई। जबकि उसकी पूरी नियुक्ति ही गैरकानूनी थी, 04.07.1994 को प्रभारी संचालक सह आयुक्त द्वारा उन्हें पत्र सं. 225 / एस्टेब /तीन/94. भोपाल दिनांक 04.7.1994, द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया था। बिना किसी खुले विज्ञापन के, जबकि कोई प्रभारी निदेशक कोई आदेश और नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकता है, जिसकी उन्हें पात्रता ही नहीं थी। दूसरी बात, वह ईसाई, 156 अशोक गार्डन भोपाल की निवासी है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन वकील शौकीन मिजाज बाबूलाल गौर ने सत्यापित कर बनाया था।जबकि गोंड जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र का निर्माण किया, यह जनजाति एसटी श्रेणी केवल छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, शहाडोल, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार झाबुआ इत्यादि जिले में ही भारत शासन द्वारा वहां के उस जाति के निवासियों के लिए ही है । जो कि आत्यधिक उत्साही, भ्रष्ट अधिवक्ता एवं विधायक बीएल गौर द्वारा 19.07 1994 को हस्ताक्षर किए गए जबकि नियुक्ति पत्र 4 जुलाई 94 को ही जारी हो गया था। जो पूर्व मे सांसद व मुख्यमंत्री थे।

अनीता विल्सन या करोठे की कानूनी आय की तुलना में 100 गुना अधिक संपत्तियां हैं।जिसका मूल्यांकन लोकायुक्त द्वारा अत्यधिक कम किया गया है। निश्चित ही जिस कंमनीयता के दम पर सीधी भर्ती फिर सहायक मानचित्रकार से मानचित्रकार और फिर सहायक संचालक के पद पर बैठकर इंदौर खंडवा व अन्य जगह बैठकर जिस गैरकानूनी तरीके से काम कर धन कमाया, संपत्तियां एकत्रित की, अवैध कालोनियों में, हर कालोनियों में 2-4 प्लाट अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम करवाएं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी प्रकार अपनी कमनीयता के दम पर लोकायुक्त को भी तन, मन, धन से सेवा कर लंबे समय तक विभाग में भविष्य में भी जालसाजियां लूटपाट करती रहेंगी और लोकायुक्त इतिहास की तरह महीनों और सालों तक आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएगा।

चपरासी, बाबू, उपयंत्री, सहायक यंत्री, सहायक मानचित्रकार मानचित्रकार, सहायक संचालक उपसंचालक, संयुक्त संचालक, संचालक सचिव से लेकर प्रधान सचिव व मंत्री तक किस तरह से दोनों हाथों से शहरी विकास व आवास के नाम के इस विभाग में कैसा खुला भ्रष्टाचार वह डकैती का तांडव होता है। सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी में जब मुख्यालय से अधिकांश अधिकारियों के संपत्ति के घोषणा पत्र मांगे गए तब सभी अधिकारियों के घोषणा पत्र पूर्णता झूठे थे सब के पास करोड़ों की संपत्तियां है पर घोषणा में मात्र 1-2 मकान और प्लाटों की घोषणा की गई है। यथार्थ में हर शासकीय कर्मचारी अधिकारी की संपत्तियों की जांच गोपनीय रूप से किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए तो इस विभाग के 99% कर्मचारी अधिकारी घोषित संपत्ति से 200 गुना ज्यादा तक के मालिक हो सकते हैं।

फर्जी प्रमाण पत्र के नाम पर धीरज आनंद लिखार जो संयुक्त संचालक जबलपुर है, के भी फर्जी प्रमाण पत्र का मामला आदिवासी व अनुसूचित जनजाति आयोग में जांच के लिए वर्षो से लंबित है, परंतु वहां पर भी मोटा धन बांटकर प्रमाण पत्र की जांच वर्षो से लंबित करवाई जा रही है, इस विभाग में 70% आरक्षित कोटे से भर्ती अधिकारी कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर पिछले कई वर्षों से आराम से नौकरियां कर रहे हैं और शिकायत होने पर वे भी इसी प्रकार धन बांट कर अपनी शिकायतों को आयोग में लंबित करवाते रहते हैं।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारियों अधिकारियों को बचाने के लिए कभी भी जानकारी देने की अपेक्षा यह जानकारी व्यक्तिगत कहकर सारे आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं ।

इंदौर में बैठे संयुक्त संचालक, राजेश नागल जो कि शीघ्र ही भ्रष्टाचार और जालसाजी के चलते अपने कुकर्मो और भ्रष्टाचार का घडा फूट न जाए इसलिए स्थानांतरण ले कर इंदौर से जाने की तैयारी में है। वैसे संयुक्त संचालक संजय मिश्रा नगर एवं ग्राम निवेश उज्जैन के पद पर रहते हुए उन्होंने भी भ्रष्टाचार के काफी मापदंड स्थापित किये हैं उन्होंने मास्टर प्लान के विपरीत जाकर अपने उपयंत्रियों महेश कुमार सलोजे, दिनेश राठौर चौधरी उपसंचालक रजनी वसुनिया मानचित्रकार,आदि के साथ छेड़छाड़ कर काफी अनुमतियां कालोनियों बहुमंजिला इमारतों व्यवसायिक संस्थानों को जारी किया है। यहां बैठे एसएम सांखला जो कि शीघ्र लेखक हैं लगभग 20 वर्ष पहले इनका दुर्घटना में काफी शारीरिक क्षति पहुंची थी जिस कारण यह कार्य करने योग्य नहीं है इसके विपरीत इन्हें यहां प्रतिमाह रुपए 77000/- का वेतन भुगतान किया जा रहा है इनकी अनेकों बार शिकायतें हुई जांच करने वाले जितने भी अधिकारी आए उन सबको रु 50000 का लिफाफा देकरबिदा कर दिया गया और सबने उन्हें कार्य करने में सक्षम बताया। बकायदा इनकी गोपनीय चरित्रावली हर वर्ष संयुक्त संचालक द्वारा लिखकर पिछले 20 वर्षों से भेजी जा रही है क्योंकि ये दलाली करने में काफी सिद्धहस्त माने जाते हैं। इसने भी 3 इ डब्ल्यु एस प्लॉट को फर्जी तरीके से ही आवंटित करवा कर उस पर एक एच आई जी तिमंजिला भवन का निर्माण किया है जो किराए पर मोटी आय दे रहा है। यहां पर भारी भ्रष्टाचार करने के बाद कुछ संयुक्त संचालक दूसरे विभागों में बैठकर विभाग की दलाली के साथ मोटी कमाई कर रहे हैं।

मंगलामूर्ती व्यास जो कि कार्यालय सहायक वर्ग एक है कंप्यूटर व सभी प्रकार की लेखन सामग्री आदि की खरीद करता है जिसमें हजारों रुपए प्रतिमाह के घोटाले किए जाते हैं सारी सामग्री केवल छुट्टी के दिन ही कार्यालय में प्राप्त की जाती है।

इस विभाग के संयुक्त संचालक विष्णु खरे नगर निगम में, आर के सिंह इंदौर विकास प्राधिकरण में, कोचर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में कार्यरत हैं जिन्होंने वहां बैठकर भी अपनी व जहां बैठे हैं, वहां के अधिकारियों की भी मोटी कमाई करवाई और स्वयं भी सभी प्रकार के लाभों का आनंद भोंगते हुएकरोड़ों रुपए के ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं। देश प्रदेश के सभी महानगरों के विकास प्राधिकरणों में नगर ग्राम निवेश का संयुक्त संचालक, संचालक मंडल की कार्यकारिणी का पदेन सचिव होता है इन दोनों विभागों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संयुक्त संचालक मिलकर नगर विकास के नाम अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर नीचे से ऊपर तक सब को बांट कर खुद भी करोडो रूपये हजम कर जाते हैं। संयुक्त संचालक कोचर ने नर्मदा घाटी में बैठकर रानी अवंती बाई सागर बरगी, इंदिरा सागर पुनासा, ओमकारेश्वर बड़वाह, सरदार सरोवर बांध की डूब में हाय लाखों परिवारों के पुनर्वास की नई कॉलोनियां नए नगरों के विकास में इस हरामखोर ने मोटा धन हजम किया और प्लॉट आवंटन के नाम पर भी मोटी वसूली हुई।

यहां के कई संयुक्त संचालक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिसमें जेके विजय, राकेश गांधी जिनकी पत्नी अनीता गांधी को लोकायुक्त ने रु 50000 की घूस लेते पकड़ा था। ये भी व अन्य कई विभागीय कर्मचारी अधिकारी अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए इस विभाग से उल्टे सीधे अवैधानिक कार्यों को अंजाम देते हुए स्वयं भी मोटी कमाई करते हैं और अपने विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की भी मोटी कमाई करवाते हैं यह सिलसिला पूरे मध्यप्रदेश का है।

इस विभाग में, भ्रष्टाचार के अनेक प्रकरणों में अनेकों अधिकारी व कर्मचारी लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए हैं इसके विपरीत यहां रिश्वत का लेनदेन बदस्तूर जारी है। सभी जिलों के सहायक संचालक अपने भ्रष्टाचार के और अवैध नक्शों की स्वीकृति के बदले मोटा धन हजम कर रहे हैं इसकी शिकायतें बराबर प्राप्त हो रही है जो अगले अंकों में प्रकाशित की जाएंगी।

साप्ताहिक समय माया

विश्व पर शासन के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के विनाश व स्वंय के वर्चस्व का मंसूबा

पेज 1 का शेष

वह भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। दूसरी ओर वैसे भी चीनी आबादी 60% 50 साल से ऊपर की है क्योंकि चीन ने एक बच्चे की नीति के चलते जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जिन बच्चों को जिंदा मार डाला गया या जोड़ों को एक बच्चा पैदा करने के लिए विवश किया गया वह दुर्भाग्य पूर्ण निर्णय का परिणाम अब सामने आ रहा है जहां पर 60% जनता 50वर्ष की उम्र से ज्यादा हो चुकी है और नई पौध की संख्या वर्तमान की संख्या में काफी कम है तो उसका यह मंसूबा भी ज्यादा दिन कामयाब नहीं रहेगा।

चीन में भी प्रसार माध्यम पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है और कोई भी खबर बिना सरकार की मर्जी के समाचार पत्र वाले व अन्य माध्यम प्रकाशित-प्रसारित नहीं कर सकते। चीन की हड़प और विस्तारवादी नीति जिसके अंतर्गत उसके आजू बाजू के छोटे राष्ट्रों इसमें पाकिस्तान भारत कोरिया ताइवान वियतनाम आदि को छल, बल, दल और दम से अपने हिसाब से नचाने के लिए विवश करता है. अन्यथा अपनी सेना का उप्योगकर वह धमकाने, चमकाने का खेल करता है जो हाल विश्व के रंगमंच पर करता है वही उसका आंतरिक रूप से अपने देश में भी है। बेशक उसकी खबरें बाहर नहीं आती वहां गूगल, फेस्बूक, व्हाटसएप आदि पर भी प्रतिबंध है। जो चीनी जनता को विश्व से सीधे संपर्क करने में सफल नहीं होने देता ताकि उसकी सच्चाई विश्व की जनता को मालूम ही ना पढ़ सके और वह है अपने शोषण कारी क्रूत्यो को विश्व की जनता के सामने आने से रोक सके रोक रहा है। इसी तरह चीन के प्रधान मंत्री झी जिनपिंग ने चीन में,अपने सहयोगीयों को छल बल दल और धन के दम से खरीद कर संवैधानिक प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया और देश मे जीवन भर शासक बने रहने के लिए खुद को धोखाधड़ी व जालसाजियो से पुन; प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया।

दोनों ही उन पर मजबूत नियम को मारने के लिए प्रकृति का सामना कर रहे हैं, फिर कमजोर कब्जा कर लें, उन्हें हुक या पकाने से निगल लें, हमारे व्यापार का विस्तार करें और हमारे देश की सीमाएं ऐसा करने के लिए, चीन ने 28 देशों में रेलवे लाइनों के विस्तार के द्वारा एक बेल्ट के एक मार्ग का खेल खेला था, जबकि वास्तव में यह एक नियम एक व्यवसाय था। रेलवे लाइन का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय और एशियाई देशों में पैरों का प्रसार करना है। रेलवे लाइन की स्थापना के बाद, चीनी अपने स्टेशनों की स्थापना अपने व्यापार पर कब्जा करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में किए गए विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बस चीनी व्यापारिक कंपनियां शुरू कर दी गईं, फिर ऑस्ट्रेलिया में नौकरशाहों ने सरकार में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वास्तव में चीनी दुनिया के अतीत में उन्होंने जो कुछ किया था, ब्रिटेन के कदमों का पालन कर रहे हैं।दुनिया पर शासन करने के लिए ऐसा ही करना। चीनी सभी प्रकार के अविश्वसनीय सामानों को बहुत अधिक कर कम, उच्च सब्सिडी मुक्त विद्युत प्रदान करने के साथ प्रमुख दरों, श्रम के उच्च जबरन वसूली के साथ पानी के साथ अविश्वसनीय, उनके काम के घंटे 10 से 14 घंटे प्रति दिन का निर्माण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर दीर्घकालिक कुल श्रम में 50 से 60 साल के जीवन में उच्च मृत्यु दर का नुकसान होगा। लेकिन चीनी शासकों ने इसके लिए परेशान नहीं किया उनका मुख्य उद्देश्य चीनी वस्तुओं के साथ दुनिया के कुल बाजार को भरना है, अन्य देशों की कुल अर्थव्यवस्थाओं को क्रैश करना, उन्हें मुख्य चीनी माल पर पूरी तरह भरोसेमंद बनाने के लिए बनाएं। और चीनी शासक इस नीति में सफल रहे हैं ताकि दूसरे देशों को पूरी तरह मेमने बना सकें।

रूसी पुतिन 2000 से रूस पर शासन कर रहे हैं और रूसी जनता की आवाज़ की हत्या कर रहे हैं और रूस के ऊपर शासन कर रहे हैं। चीन में एक्सआई एक्सिन पिंग द्वारा दोहराई जा रही है, वह चीन में तीसरा कार्यकाल भी कर रहा है, वह जनता की आवाज को भी मार रहा है। शासन के लिए जनमत संग्रह और चुनाव प्रणाली दोनों वे उपयोग कर रहे थे और अमेरिका के साथ लड़ने के लिए उत्तर कोरिया का उपयोग करें तो भारत चीन ने भारत के साथ युद्ध के लिए दोकालम में अपनी सड़कों और हेलिपैड की स्थापना की। अब ड फ़र आईपीएम मोदी चीन और पाकिस्तान पर चुप हैं और भारत के खिलाफ उनकी गतिविधियां। ज़ाहिर है कि चीन पाकिस्तान की ओर से आंशिक रूप से समर्थन कर रहा है, भारत के खिलाफ भविष्यवादी युद्ध के लिए पाकिस्तान के पश्चिमी तट पर सड़कों के व्यापारिक गलियारों और बंदरगाहों का विकास करना है।

पूंजीपतियों के लिए लूट की पूरी छूट और आमजन के लिए शोषणकारी बजट

पेज 1 का शेष

फिर भारत की 131 करोड़ जनता को लुभाने के लिए लोकलुभावन बना वोट प्राप्त करने योग्य बनाया जिसकी प्रशंसा भुखेरा जन पार्टी के अतिरिक्त किसी अर्थशास्त्री ने नहीं की। उसने किसानों गरीबों के लिए भारी घोषणा की परंतु इससे किसानों और गरीब जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं यह सारा खेल केवल दिखावा था ।

किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई समर्थन मूल्य में किस आधार पर तैयार किया गया वर्तमान में सरकार में बैठे इन लोगों ने समर्थन मूल्य तैयार किया है यथार्थ में क्या समर्थन मूल्य की परिभाषा में क्या खेत के रखरखाव से लेकर उसने कार्यरत कृषि समन्वयकों श्रमिक, कृषि श्रमिकों, किसान के दैनिक मजदूरी के साथ खाद बीज पानी कीटनाशक बिजली आदि जोड़ा गया और उसकी हर फसल के 3 से 4 महीने मैं कार्यरत उसके परिवार के सदस्यों की दैनिक मजदूरी को शामिल किया गया जो कुल न्यूनतम लागत पर उसके 50% लाभ को जोड़ा गया यदि नहीं तो न्यूनतम लागत के साथ कुल लागत कुल लागत का 50% लाभ को जोड़ने पर ही उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा परंतु इसके विपरीत वातानुकूलित कमरों में बैठकर केवल खाद बीज पानी की कीमत जोड़कर उस पर 50% ज्यादा दे देने से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता।

यही कारण है किसान को पर्याप्त लागत और उसकी मजदूरी न मिल सकने के अभाव में जो लागत में वह कर्ज लेकर बोनी से लेकर फसल काटने तक मेहनत करता है वह भी उसे पूरी नहीं मिलती और अंत में बैंक से लिए हुए कर्ज बैंक को, साहूकारों से लेकरअन्य सरकारी संस्थाओं का कर्ज का भुगतान क समय पर न कर सकने के कारण अंत में आत्महत्या कर लेता है क्या मोदी सरकार ने किसान की इन सब पीड़ाओ को समझा और उस पर उसकी मजदूरी जोड़कर उस पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया दूसरी ओर जो भारत की जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई 5 करोड लोगों के लिए घोषणा की गई उसमें केवल बीमा कंपनियों के लाभ के अतिरिक्त जो कि जनधन से भुगतान किया जाएगा, जिसकी न्यूनतम लागत न्यूनतम न्यूनतम प्रीमियम के रूप में प्रीमियम रूप में मूल्य रुपए गिला करो डेढ़ लाख करोड़ रुपए का भुगतान अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और खास मित्र अंबानी की रिलायंस की बीमा कंपनी को जनधन से किया जाएगा यथार्थ में स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करके जो बीमे के भुगतान की नई प्रणाली अमेरिका की देखा देखी मैं तैयार की गई है उससे भारतीय जनता का कोई भला होने वाला नहीं इसका पूरा फायदा केवल बीमा कंपनियों और निजी चिकित्सालय को होने वाला है जिसने भी आमजन को विभिन्न बीमारियों के नाम विदेशी कंपनियों की महंगी दवाइयांउल्टा सीधा ऑपरेशन के नाम से लूटकर भारी भरकम बिल का भुगतान बीमा कंपनियों से बसुलेगे।

कोई आयकर छूट महानगरों में भी कोई छूट नहीं दी उससे जमकर वसूली करने की व्यवस्था हर कदम पर क जो कि देश की जिसकी 50% जनता है आयकर में छूट न देकर जनता के साथ धोखा किया गया दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल में 32% मैं से 8% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी कम कर 8% सड़क अधिभार जोड़ दिया गया यह भी आंकड़ो की बाजीगरी का एक धोखा ही था देश की सभी राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्ग सड़कें बी ओटी में ठेकेदारों को सौंप दी गई है उस पर भारी टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है जबकि 95% स्तरहीन सड़कों पर कोई भी वाहन 80-90किमी से ज्यादा तेज चलाने पर भारी दचके लगने के साथ ही वाहनों में भारी उछलने कूदने और टूट फुट के साथ दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो सड़कों से क्या केवल जनता को लूटना और वसूली का बहाना ही है।जबकि पेट्रोल में 2% सेस सड़क अधिभार 2% स्वास्थ्य से 2% शिक्षा,1%, सफाई सेस पहले से ही जुड़ा हुआ है।जो कि बढ़ाकर 3%-3% कर दिए गए हैं। अर्थात पेट्रोल और डीजल पर यहां पर भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में से 32 से 8% की कटौती कर वह 8%, सड़क सेस के नाम से वसूल कर लिया। जो कि बढ़कर अब कल 10:00 पर्सेंट हो गया है। जिससे राज्य सरकारों को 32 में से 16% जो धन आवंटित करना पड़ता था उससे बच गई अब 24 में से आधा अर्थात 12% उस राज्य को ही राज्य खर्च के लिए देना पड़ेगा। अर्थात सरकार ने 8% सड़क के नाम से सीधे ही हजम करना शुरू कर दिया जबकि देश के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बी ओ टी के अंतर्गत ठेकेदारों को सौंप कर जनता को लूटवाया जा रहा है

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि अनुदान में कटौती की गई वैसे भी मोदी सरकार पिछले 4 सालों में किसी भी क्षेत्र में जनता को लाभ नहीं दे सकी।चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ी। नए बेरोजगारों को तो रोजगार मिला नहीं इसके विपरीत नोटबंदी और जीएसटी से 10लाख से ज्यादा पुराने लघु व छोटे उद्योग बंद हो गए जिससे 3 करोड लोगों की बेरोजगारी बड़ी। जो असंगठित क्षेत्रों में लघु उद्योग में कार्यरत थे।

जनता को नोच कर वसूली के लिए उसको हर जगह आधार कार्ड, आधार कार्ड को मोबाइल और मोबाइल को बैंक से जोड़ कर हर हर लेनदेन व अन्य कार्य पर जो लूटने की जालसाजियां रची गई। उस से आमजन भारी हैरान परेशान हो रहा है । इसे जनता के हर वर्ग का दम घुटने लगा और भारतीय जनता पार्टी बनाम भुखेरा जानवर पार्टी का यथार्थ सिद्ध होने लगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जो 5.97 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई उसमें से लगभग रुपए दो लाख करोड़ हजम कर लिया जाएगा गांव के नाम से रुपए 14.34 करोड मैं से 3.17 लाख किलोमीटर सड़कों को बनाने का काम का वादा किया गया है उसमें भी अधिकांश काम हो चुका है। 51लाख नए शौचालय बनाने का जो प्रावधान किया गया है। यह दिखाया गया है उसमें से भी मात्र दो या तीन लाख शौचालय बनाए जा सकेंगे शौचालय के नाम से लगातार हजारों करोड़ रुपए जिला पंचायत वाह जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर गांव के सरपंचों ने हजम कर लिया और एक ही घर में सन 2002 के अभी तक 12 से 15 शौचालय का निर्माण कर दिया गया जबकि यथार्थ में सारा पैसा हजम कर दिया गया।

शौचालय निर्माण के नाम सरपंचों को मोटी कमाई करवा कर वोटों का प्रबंधन करना ही है। ताकि आसानी से चुनाव जीता जा सके। यही कारण था की मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास से प्रधान सचिव जुलानिया को हटा दिया क्योंकि उनकी शक्ति ने पंचायतों के सरपंचो से लेकर जनपदों व जिला पंचायतों के के मुख्य मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का भ्रष्टाचार का खेल खत्म कर दिया था जिससे सब बौखला गए थे।

महिलाओं और बुजुर्गों को जो छूट दी गई है वह भी एक छलावा ही है यथार्थ में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर धूर्त मोदी ने कोई कार्य नहीं किया उसके स्टार्टअप और मेक इन इंडिया केवल दिखावा बनकर रह गए।

भुखेरा जन पार्टी की सरकार ने इन 4 सालों में केवल मोटा कमीशन देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों मोदी के मित्र पूंजीपतियों अडानी अंबानी टाटा बिरला मित्तल व अन्य सौ से अधिक की कमाई और उनके लाखों-करोड़ों के लाभ की व्यवस्था पर ही ध्यान दिया है आम आदमी के लिए उसके पास केवल लूटने के ही प्रावधान है। निवेश के नाम पर म्यूचुअल फंडों, बैंकों के बचत खातों तक पर इस गिद्ध ने अपनी गिद्ध निगाहें गड़ा कर रखी हुई है। बैंकों में 5 से ज्यादा बार निकालने और जमा करने पर भी उसने भारी भरकम शुल्क ठोक दिया है। ताकि अपने पूंजीपति बापो को दिया गया दिए गए ऋणों की वसूली की जा सके।वैसे भी विजय माल्या, नितिन मोदी, मेहुल चौकसी तो केवलछोटे से खिलाड़ी हैं जबकि अनिल मुकेश अंबानी ढ़ी बिरला मित्तल अन्य सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी बैंकों से लाखों करोड़ों का ऋण लिया है उनके बारे में सब शांत है आखिर क्यों नहीं सारे बैंक सूचना के अधिकार में जानकारी देते कि उन्होंने जनधन की जमाओ से किसको कितना रण ऋण बांटा है क्योंकि बैंकों के 90 परसेंट अधिकारी कर्मचारी घोर भ्रष्ट और जालसाज हैं इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी देने से सदा ही बचते रहे हैं।

इस बजट में यथार्थ में किसानों को सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो ऋण बांटे जाने की बातें कही गई है वह देश के 90% किसानों को कर्ज में उलझाकर उनकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र ही है ताकि आसानी से उनकी जमीन नीलाम कर बड़े उद्योगपति एवं पूंजीपति बहुराष्ट्रीय कंपनियां खरीद कर उन पर अपनी मैकेनाइज्ड फार्मूला कल के जनता को कृषि उत्पाद भी भारी भरकम कीमतों पर दें वह बेचकर मोटा लाभ कमा सकें जैसा कि अधिकांश देशों में मैकडोनाल्ड वालमार्ट और अन्य कंपनियों ने किया है। गांव के संबंध में भी गुजरात के मोदी ने इसलिए ध्यान दिया की गुजरात में मोदी की विधानसभा में जो बुरी हार हुई उसे मोदी को गांव के वोट बैंक का यथार्थ मालूम चला और अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए आवश्यकता कि बजट में किसानों को लुभाने के लिए आकर्षित प्रावधान किए जाएं यथार्थ में अनपढ़ मोदी जिसने अपनी उम्र के 12 से 32 वर्ष तक केवल मवाली गिरी की हो उसे किसी भी विषय का ज्ञान नहीं। उस अपराधी और नीच व्यक्ति को केवल पूंजीपतियों के इशारे नाचना ही आता है जैसा कि उसके पूंजीपति मित्र कहते हैं वह मोटा कमीशन लेकर उनके हिसाब से बजट बनाने से लेकर सरकार की नीति निर्धारण तक सब कुछ करता है आमजन सही कोई लगाओ तो दूर देखने की भी फुर्सत नहीं बेशक उसके लिए आमजन भ्रमित कर वोट पाने का और सत्ता हथियाने का साधन मात्र हैं।

रुपए 71000 करोड़ जो सड़कों पर किया जाएगा यथार्थ में राष्ट्रीय राजमार्ग जब सारी ब्यूटी ठेकेदारों को सौंप दिए गए हैं और वह सरकार की गारंटी पर 90% का बैंकों से ऋण लेकर राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं तो रुपए कतरा 71000 करोड़ का प्रावधान क्या केवल अपने महान नीच, दुष्ट भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को हजम करने के लिए है क्या जबकि सड़कों के नाम से 8ड का जो अधिभार पेट्रोल व डीजल पर थोपा गया है। उनसे आसानी से जो हर माह लाखों करोड़ की कमाई होगी जनता को सड़कों पर निशुल्क वाहनों को दौड़ाने की आजादी मिलनी चाहिए थी परंतु अद्भुत और महान जालसाज नितिन गडकरी इसके स्वयं के कई टोल टैक्स हैं यह कभी नहीं होने देगा क्योंकि वह ना केवल उसकी मोटी कमाई के साधन है वरन पार्टी फंड के लिए भी आय का स्रोत है । मोदी सरकार को जनता से धन लूट कर या पूंजी पतियों के माध्यम से लुटवा करचुनाव के लिए आगामी चुनाव के लिए मोटा धन चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए यह बजट पूंजी पतियों के लाभ के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज का अंतिम बजट किसानों को छलावा और जनता से लूट की तैयारी

पेज 1 का शेष

परंतु अपनी सीट पर खतरा मंडराता देख शिवराज सिंह ने एक अच्छे वित्त मंत्री को सलाखों के पीछे येन केन प्रकारेण पहुंचा दिया। घोर भ्रष्ट बुंदेलखंडी बनिया वित्त मंत्री जयंत मलैया के आने के बाद वित्तीय संतुलन बिगड़ा और सरकार ने अपनी सरकार में बैठे कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए भी बाजार से हर तरह से भारी ब्याज दर पर भारी भरकम रुपए 1,70,000 करोड से ज्यादा का कर्ज ले लिया जिसके ब्याज में ही 12प्रतिशत धन पूरा हो जाएगा। किस्त लौटाने की बात तो बहुत दूर। इस कड़वे सच से पाठक अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज की भुखेरा जन पार्टी की सरकार जन धन पेट्रोल डीजल व रसोई गैस पर पर 32% वेट वसूलने के अतिरिक्त भी प्रति लीटर पेट्रोल पर रू 4/- और डीजल पर, रु3/- अधिक लिया जा रहा है। और इससे सरकार ने पिछले 5 वर्षों में रुपए 33236 करोड की मोटी कमाई की। इसके विपरीत सरकार चलाने के लिए बाजार से भी खुले ब्याज दरों पर ऋण उठाकर जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर स्वयं ही हजम करती रही मध्य प्रदेश महालेखाकार की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार अपने भ्रष्टाचारों, जालसाजियों कें कांडों को दवाने छुपाने और बदनामी से बचने के लिए कुल वाणिज्य कर के धन प्राप्ति का 80% पैसा प्रसार माध्यम पर रोज दैनिकों को 5-7 पेज विज्ञापन देकर और टीवी न्यूज चैनलों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 15 से 30 मिनट प्रतिदिन के विज्ञापन स्लाट पर प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ खर्च करती रही इसका सीधा उदाहरण उज्जैन के सिंहस्थ 16 में हुए भारी भ्रष्टाचार को छुपाने प्रतिदिन प्रदेश में और देश में छपने वाले सभी भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों के साथ विदेशों मे भी मुख्य रूप से यूरोप में छपने वाले समाचार पत्रों के के विज्ञापनों से जाना जा सकता है। इसके साथ ही नर्मदा यात्रा, एकात्म यात्रा जो कि इसी वर्ष जनता और मीडिया का ध्यान अपने कुकर्मों से जिसमें व्यापम कांड महिला बाल विकास में पोषण आहार की आपूर्ति और रेती कांड, जिसमें पूरा कानून ही बदल कर ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सौंप दिया गया ताकि रेती का आसानी से दोहन कर खुले बाजारों में बैचकर में करोड़ों रुपए कमाएं, आँदि से हटाने के लिए आयोजित की गई थी उस पर भी प्रतिदिन करोडों रुपए का विज्ञापन सारे मीडिया का ध्यान बंटाने और सच्चाई छुपाने के लिए ही किया गया था।

रुपए 204 642करोड़ के बजट में रुपए 155886 करोड कि राजस्व की प्राप्ति संभावित है अर्थात लगभग 25% घाटे का बजट बनाया गया है। घोषणावीर और छपास रोग से पीड़ित हमारे मुख्यमंत्री ने इतिहास की तरह इस बजट में भी बड़ी-बड़ी घोषणा ही तो की है। पर उन्हें पूरा करने के लिए धन नहीं है। जैसे कि इंदौर भोपाल के बीच 5000 करो रुपए का एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा यथार्थ में इंदौर भोपाल के बीच की दूरी मात्र 180 किलोमीटर है अब इस 5000 करोड़अर्थात औसतन रुपए 278 करोड प्रति किलोमीटर में मुख्यमंत्री बताएं कैसा एक्सप्रेस हाई वे बनाया जाएगा। क्या एक्सप्रेस हाईवे पर वाहन के पहुंचते ही वाहन 1 घंटे में इंदौर से भोपाल पहुंच जाएगा। यह मात्र यह सब दिखावा किसी अपने खास कैसे की दिलीप सूर्यवंशी दिलीप बिल्डकॉन को ठेका देने के लिए और उसकी और अपनी मोटी कमाई के लिए तैयारी की जा रही है। जबकि पूर्व से ही फोर लेन बीओटी पर लूट जारी है। जबकि प्रदेश के अधिकांश टोल सड़कें 70 किलोमीटर की गति से चलाने योग्य नहीं है और कई सड़कें टोल वसूली करने के बाद में भी इतनी खराब है कि उन पर 30 किलोमीटर की गति से बिगड़ी नहीं चलाइ जा सकती है।

मेट्रो ट्रेन की घोषणा भी की गई है। जो की पूर्णता जनता को भ्रमित करने का शिगूफा है। हमारी प्रदेश की युवा पीढ़ी, महिलाओं, ग्रामीणों को आकर्षित करने के लिए जो घोषणायें की गई है। शायद इस मुख्यमंत्री के रहते कभी पूरी नहीं होगी। वैसे भी सरकार का राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय 5 गुना ज्यादा है यथार्थ में जैसा कि सरकार ने घोषणा की है इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे पर रुपए 5000 करोड़ खर्च किए जाएंगे 3000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी 150 बड़े पुल 300 अस्पताल खोले जाएंगे यह सब पूंजीगत व्यय आएगा कहां से? जबकि सरकार का 82 परसेंट पैसा केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन और लिए गए रुपए 170000 करोड के ब्याज में ही खर्च हो जाएगा। अर्थात राजस्व प्राप्ति का मात्र 18% ऐसा ही बचेगा जो कि पूंजीगत व्यय के लिए नाकाफी होगा। जबकि सरकार इस बचे हुए 18% का 3गुना केवल प्रचार और प्रसार माध्यम पर अपनी छवि सुधारने और प्रशंसा छपवाने के लिए खर्च करेगी इस खर्च का हिसाब कभी भी वह है बजट में प्रदर्शित नहीं करती। यह धन इस बजट से अलग, अलग-अलग विभागों के आवंटित धन के खर्च के माध्यम से विज्ञापन पर खर्च किया जाता है। सिंचाई बजट के लिए सरकार ने रुपए10928 करोड कि जो व्यवस्था की है उसमें से रुपए 3245 करोड नर्मदा घाटी की सिंचाई उद्वहन परियोजनाओं के लिए है जो कि अधिकांश भविष्य में जाकर विद्युत के अभाव में बंद हो जाने वाली हैं। सभी उद्वहन परियोजनाएं केवल धन हड़पने के उद्देश्य ही बनाई एवं चलाई जा रही हैं । सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में जो रुपए 389 करोड की व्यवस्था की गई है। उसका भी अधिकांश धन हड़पने में ही जाएगा ।सहकारिता मैं रुपए 1627 करोड की जो व्यवस्था की गई है यह

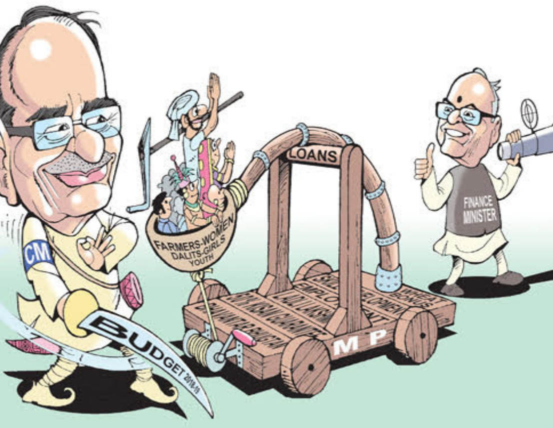

धन भी केवल लूट मार और बंदरबांट मे हीं जाएगा ।सहकारिता का तात्पर्य सहकार मिलकर करो बंटाधार।

इस वर्ष सरकार सरकार ने जो बजट पेश किया है वह केवल अगस्त 18 तक ही काम कर सकेगा उसके बाद चुनावी आचार संहिता लग जाने की कारण बजट का सरकार अक्टूबर से ही और कार्य संपन्न नहीं कर पाएगी। वह अच्छी तरीके से जानती थी। इसके विपरीत उसमें चुनावी वैतरणी पार करने के लिए उसे खास मतदाताओं जो कि किसान, दलित, आदिवासीयों महिला और युवा है। जो आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए बजट पर काफी ध्यान दिया गया बजट वैसे भी केवल एक सरकारी औपचारिकता जनता को दिखाने के लिए वर्ष में एक बार निभा दी जाती है। सरकार करती तो वही है जो उसे अपनी मोटी कमाई, छवि सुधारने और बचाने में आवश्यक लगता है इस वक्त सरकार ने किसानों के लिए जिस रुपए 37498 करोड के धन की व्यवस्था की है। यथार्थ मैं यह धन केंद्र सरकार की योजनाओं में किसानों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दिया जाएगा । वही बजट हर वर्ष की तरह सरकार ने दिखा दिया है किसानों को हर वर्ष इसी तरह से छला जाता है भारी भरकम घोषणाएं होती हैं भावंतर और प्याज की खरीदी जैसे कार्यक्रम में हजारों करोड खर्च करके किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है पर इसके विपरीत किसानों को न मिलकर सत्ता में बैठे हैं धूर्त, हरामखोर, गिद्ध अधिकारी ही बीच में हजम कर जाते हैं। जिस के किस्से कहानियां हर दिन अखबारों में बरसों से छप रहे हैं और इन सारी षड्यंत्रकारी घोषणाओं के बाद भी प्रदेश का किसान हजारों की संख्या में कर्ज के चक्कर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और हमारी सरकार के मुखिया शिवराज केवल और केवल वायदे,घोषणाए, और मीठी बातें करने में मस्त है। इस बजट में रुपए 3650 करो कृषक समृद्धि योजना के लिए, 250 करोड़ भावंतर और प्याज के लिए रुपए 10 928 करोड़ सिंचाई परियोजना के लिए दिया गया है जबकि सच यह है की सिंचाई के लिए केंद्र की पुरानी जल स्त्रोतों, नहरों मैं बांधो आदि के लिए केंद्र सरकार स्वयं पैसा देती है जिसे यह अपने खाते में दिखाएंगे। जबकि यही धन जल संसाधन विभाग की योजनाओं में भी दिखाया जाएगा अर्थात यह भी आंकड़ों की बाजीगरी का ही एक छोटा सा नमूना दिखाया गया है

ग्रामीण विकास के नाम जो नई 3000 किलोमीटर सड़कें बनाने का वादा किया गया है वह ग्रामीण सड़कें पूर्व में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना दी गई हैं जिन्हें यह अगस्त तक नाम बदलकर मुख्यमंत्री सड़क योजना में ले आएंगे

विद्युत के विकास में रुपए 17798 करोड कि मोटी धनराशि बिजली पर खर्च करने का प्रावधान किया है । यहां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जालसाजियां की गई हैं मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में जल, ताप, सौर और पवन विद्युत उत्पादन के माध्यम से प्रदेश में लगभग 30000 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है यह बिजली हमारे देश में सबसे ज्यादा महंगी केवल प्रदेश की जनता को ही बेची जा रही है जब किस्से आधी कीमत में देश के दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान आदि में बेची जा रही है और उसमें भी मोटा कमीशन कमाया जा रहा है मध्य प्रदेश में सरकार दिल्ली में लूटने के कई तरीके अपना रही है जबकि विद्युत उच्च व निम्न दाव लाइनों के समोसे लेकर विद्युत तारों ट्रांसफर करो उप व बड़े विद्युत स्टेशनों पर मेंटेनेंस के नाम सारा पैसा उसके अपने भूत मक्कारों गीत कर्मचारी हजम कर जाने के साथ, विद्युत वितरण में भी भारी 10 से 1000 गुना ज्यादा की बिल जनता को डरा-धमकाकर उसके मकान जमीन जायजाद संपत्तियां ट्रैक्टर मोटरसाइकिल व अन्य सामग्री जप्त कर सरेआम उपभोक्ता की इज्जत नीलाम कर वसूली कर रही है। दूसरी तरफ सौर पवन व ताप विद्युत उत्पादन जो कि निजी क्षेत्र में,टाटा बिरला अंबानी आदि के द्वारा किया जा रहा है और उसे जानबूझकर महंगी दरों पर 50 से 70 पर्सेंट कमीशन पर खरीदी जा रही है और इस प्रकार हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन क्यों बिजली के माध्यम से हजम किए जा रहे हैं.

शिक्षा के नाम पर भी रुपए 21724 का प्रावधान किया गया है उसमें रुपए 3109 करो सब शिक्षा के नाम पर है। सर्व शिक्षा का 80% पैसा हर साल शिक्षा मंत्री से लेकर जिलों पर बैठे उसके अधिकारी हजम कर जाते हैं इसे 30 सालों में सब शिक्षा के नाम पर 80% पैसा शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव सचिव संचालक से लेकर जिलाधीश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,जिला शिक्षा अधिकारी व जिला सर्व शिक्षा केंद्र में बैठे अधिकारी और कर्मचारी झूठ है प्रिंटिंग श्री, शिक्षकों के वेतन आदि के नाम से कागजों पर ही डकार जाते हैं। और रुपए 450 करोड़ से मात्र 16 नई शिक्षा परिषर अर्थात28 करो हर नए परिसर परऔर उपाय 28 करोड़ खर्च किया जाएगा. बजट में 8780 करोड का प्रावधान लोक निर्माण विभाग के लिए सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए किया गया है नई सड़कें मंडी निधि और केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त होने के साथ एशियन विकास बैंक के कर्ज से से भी निर्मित की जा रही है बेशक यहां पर इस कार्य में मोटा पैसा हजम करने के लिए यह कार्य सड़क डकैती निगम के माध्यम से धूर्तो की महाभ्रष्ट इंजीनियरों की फौज से करवाया जाएगा. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए रुपए 3683 करोड़ की व्यवस्था की गई है यह धन अधिकांश बंदरबांट में जाएगा जबकि नल जल योजना ग्रामीण पेयजल योजना आदि के लिए के लिए धन केंद्र सरकार से ही प्राप्त होता है जिससे ग्रामीण विकास स्कूली शिक्षा आदि के नाम प्राप्त किया जाता है।

रुपए21724 करोड़ कब प्रावधान मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया गया है यथार्थ में यह भी एक दिखावा है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के के साथ केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधित 12 योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ का धन केंद्र सरकार से ही प्राप्त होता है यहां पर भी यह धन पूरा केंद्र सरकार का ही होगा जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट मैं दिखाया है। वैसे भी स्वास्थ्य के नाम पर दवाइयों, चिकित्सा सामग्री खरीदी में ही 40 से 60 पर्सेंट का बजट स्वास्थ्य मंत्री घोर भ्रष्ट रुस्तम सिंह से लेकर प्रधान सचिव, सचिव, संचालक से जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ही हजम कर जाते हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर अधिकांश गिद्ध डॉक्टर जानकारी देने की अपेक्षा आवेदक को परेशान करने के अतिरिक्त आतंकित भी करते हैं क्योंकि इस विभाग का भ्रष्टाचार सार्वजनिक है। रुपए 4835 करोड़ महिला बाल विकास के लिए है जबकि यह धन भी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए केंद्र सरकार से ही प्राप्त होता है यह भी यह प्रावधान केवल दिखावा है इसका भी 70 परसेंट पैसा महिला बाल विकास मंत्री से लेकर विकासखंडों में बैठेगी एकीकृत ग्रामीण विकास अधिकारी ही हजम कर जाते हैं और कुपोषण से लगातार बच्चों की मौतों का सिलसिला खंडवा श्योपुर में आज भी अनवरत चल रहा है। रुपए 11932 करोड क बजट नगरी विकास के लिए रखा गया है। इस बजट का 40 परसेंट तो केवल भ्रष्टाचार में नगर निगम पालिकाएं और परिषद भ्रष्टाचार में डकार जाएंगे 30% बजटका हिस्सा मोटे बिल बनाने के लिए जानबूझकर बनी बनाई सीमेंट की सड़कों पर डामर पोता जाएगा। पुराने टाइल्स निकालकर नई टाइल्स लगाए जाने में खर्च किया जाएगा जैसा कि पूरे प्रदेश में 2017 18 में हुआ। इसमें करोड़ों रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान किया गया और पैसा पार्षदों से लेकर महापौर निगमायुक्त और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने डकारा।

बजट की इस नौटंकी में केवल आंकड़ों की बाजीगरी के साथ यथार्थ में जनता को दिखाने और शासकीय औपचारिकता पूरी करने की रस्म ज्यादा होती है और एक अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा सामान्य तौर पर जनता को दिखाने के लिए ही प्रस्तुत किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के आने के बाद बजट का 10से 20% हर वर्ष जनता को भ्रमित करने और प्रसार माध्यमों को सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका मुंह बंद रखने के लिए जन धन से

अनाप-शनाप तरीकों से करो में लूटा गया धन, लुटाया जाता है। बजट कि इस खोखली झूठी आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को और मीडिया को आसानी से भ्रमित कर चुने हुए मंत्री और सरकार के मुख्य व प्रधान सचिवों संचालकों से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक उन्हें स्वयं ही नहीं पता होता कि आखिर इस बजट की प्रस्तुति का उद्देश्य क्या है। यह देखा जाता है कि कितने धन के आवंटन पर कितना पैसा सभी अधिकारियों को मंत्रियों मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा फिर दूसरी तरफ बजट में जिस धन की घोषणा की जाती है वह 90 से 95% तक केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला धन ही ज्यादा होता है उसी के हिसाब से उस धन को बजट में शामिल कर जनता को भ्रमित किया जाता है। जबकि राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री,मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, अपनी सुविधा और लाभ प्राप्ति की दृष्टि से संपन्न करते हैं क्योंकि इस औपचारिकता को पूर्ण करना वैधानिक रूप से आवश्यक है। वैधानिक आवश्यकता की यह नौटंकी जनता को कितनी भारी पड़ती है इसका अंदाजा एक आम नागरिक तो दूर सरकार में बैठे भारतीय प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना सेवा के धूर्त अधिकारियों को भी-कभी समझ में नहीं आया। तो आम नागरिक कि क्या औकात है, कि वह इस बजट की आंकड़ों की जालसाजी और चालबाजी को समझ पाएगा।

यथार्थ में चुनावी वर्ष की इस नोटंकी में केवल शिगूफे छोड़ने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। वैसे भी घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज ने जनता को पिछले 13 वर्षो से घोषणाओं और शिगूफों में ही उलझाए रखा और भविष्य में भी यदि चुनाव जीत गई तो यही करेंगे। अपनी मोटी कमाई के चलते जनता को वादों और घोषणाओं उलझाकर प्रदेश की रेती, बिजली और निर्माण कार्य में में अपनी हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन की कमाई करते रहेंगे।

साप्ताहिक समय माया

दुनिया का सबसे बड़ा ठग गूगल

पेज 1 का शेष

बेशक विदेशों में अनेकों देशों ने गूगल की बदतमीजी पर भारी दंडात्मक करवाई कर सैकड़ों हजारों करोड़ का का आर्थिक दंड वसूल किया है। पर भारत में तो सरकार दंडात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा उल्टे ही गूगल को जनता की जासूसी करने के बदले हजारों करोड़ों का भुगतान करती है और बदले में उसे आधार कार्ड की डाटा से लेकर गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के ठेके भी देती है। साथ कि मोदी ने भी गूगल और फेसबूक के इस डेटा का उपयोग कर न केवल 2014 में सरकार बनाने के लिये देशी- विदेशी कंपनियों का सहारा लेकर जनता के खातों में लगातार अपनी तारीफों, आतंकवाद के खतरों दिखाने के ईमेल भेजने का कार्य किया जाता रहा वरन तब से लगातार राज्य में सरकार बनाने के लिए इस डाटा का उपयोग किया गया निसंदेह वर्तमान की भाजपा सरकार ने सन 2014 का चुनाव जीतने के लिए गूगल की इन जासूसी गतिविधियों को पूरा फायदा उठा कर पूरे देश में अपनी जीत का परचम लहरा दिया था।

वर्तमान में एशिया यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश देशों के लगभग 400 करोड़ कंप्यूटरों में जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। उनमें उनके कंप्यूटर लैपटॉप और 200 करोड मोबाइल नंबरों पर हर बातचीत, संदेश भेजने की प्राप्त करने बैंकों के हर लेनदेन कार्य पर, हर ईमेल, पर हर खोजबीन की जानकारी पर नजरें गड़ा रखी है । जिसके हर डेटा का उपयोग वह दुनिया की बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सरकारों, शत्रु राष्ट्रों, हेकरों, जासूसी एजेंसिओं से लेकर आतंकवादियों तक को उपलब्ध करा देती है । इसके बदले में वह अरबों डॉलर प्रतिदिन की वसूली करके अपनी मोटी कमाई करती है। शायद यह तथ्य आम समान नागरिकों से लेकर सबसे ज्यादा इस कार्य में व्यस्त दुनिया की 200 करोड़ युवा आबादी को उसका ज्ञान नहीं हो परंतु उन डेटा के विश्लेषण से आसानी से भविष्य की नीति तैयार कर पूरी दुनिया अपने चंगुल में जकड़ चुकी है। भले ही गूगल को आमजन और इंटरनेट प्रयोग करने वाला उसे मुफ्त का सर्च इंजन मानता हो। परंतु इसके पीछे का राज यह है कि ना केवल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ ही चीन, पाकिस्तान, रूस, नाइजीरिया के साथ ही दुनिया में बैठे लाखों हैकर्स, जिनमे इस्लामिक स्टेट व अन्य दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन से लेकर दुनिया के बड़े देशों की जानी-मानी जासूस एजेंसियां जिसमें अमेरिका की एफबीआई, ब्रिटेन की एम15, इजराइल की मोसाद, रूस की केजीबी चीन से लेकर पाकिस्तान की आईएसआई तक सब डाटा में सेंध लगाकर अपने अपने तरीके से उसका उपयोग कर दुनिया के अधिकांश लोगों पर नजर रखते हैं जिसमें इसकी भी पूर्ण भूमिका होती है। जबकि यह व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति की गोपनीयता को भंग करने के साथ उसके लिए जान का खतरा भी होता है। इसकी बदतमीजी का आलम यह है, अगर आपने उसके मनपसंद विज्ञापनों और कार्यक्रमों को देखने से मना किया इसे कुकीज कहा जाता है। तो वह आपके जीमेल खाते को खोलने में भी भारी परेशानी खड़ी कर मना भी कर देता है यह उसकी बदतमीजी की पराकाष्ठा होती है।

इस के सर्च इंजन में जाने पर जाने पर बच्चे जो खोज के लिए किसी विषय पर देखरेख करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी अश्लील साइटें भी खुलती हैं इसमें अश्लीलता के साथ में इतनी घिनौनी बदतमीजी पूर्ण सामग्री भी परोसी जाती है जिसमें खुलकर मां बेटे तक की प्रणय लीला दिखाई जाती है । उससे संबंधित घिनौना वार्तालाप विस्तार से प्रसारित किया जाता है । एक बार आपने या खोजकर्ता ने किसी साइट को बटन क्लिक कर दिया उसके बाद में आपके कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल पर उससे संबंधित सामग्री आती रहती है। जिससे बच्चों के मां बाप और संरक्षक भारी परेशान होते हैं। और बाद में यह सब चीजें अल्पअवस्था व अवयस्कता में मैं बच्चों में यौनाचार का कारण बनती है। जिससे बलात्कारों के साथ उच्छृंखलता भी बढ़ रही है। इसके लिए पूर्ण रूप से वास्तविकता में इंटरनेट पर गूगल का सर्च इंजन ही जिम्मेदार है। जो अपने उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने उसकी आदत बनाने और अवस्यकता में बच्चों को अश्लीलता और नग्नता की तरफ धकेलता है जो कि विश्व भर में अपराधों को बढ़ावा दे रहा है इन बदतमीज यों को शीघ्र ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यथार्थ में अश्लील वेबसाइटों का, बहुत बड़ा बाजार इंटरनेट की शुरु हुआ है। एक बार नग्न साइट खोलने के बाद में आपको वह कम उम्र के बच्चों को उलझाती है और थोड़ी सी सामग्री दिखाकर फिर उसे सब्स्क्राइब करने के लिए ऑनलाइन पैसे मांगती है और इस प्रकार से नग्नता के माध्यम से मोटी कमाई की जाती है। यही संचार माध्यमों का यथार्थ में नग्नता परोसने का, कम उम्र में योनाचार और आपराधिकता बढ़ाने जिससे खूब 10 पैसे के कंडोम की बिक्री रु 10 में होती रहे दूसरी तरफ उससे युवा उम्र के लोगों का दिमाग पढ़ाई से भटक कर इन सब में ही उलझा रहे। और वे किसी भी तरह आगे ना बढ़ सके यह एशियाई युवाओं को बर्बाद करने का एक भारी षड्यंत्र भी है जिससे युवा आगे ना बढ़े समाज बर्बाद हो और ये एशियाई देश यूरोपीय देशों से न केवल प्रतिस्पर्धा न कर सके। वरन रोजगार के लिए यूरोपीय देशों की तरफ न जाएं। इससे वे गरीब भी बने रहें और हर तकनीकी के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर रहकर उनकी तरफ मुंह उठाकर ताकने के साथ उनके उत्पादनों को उनकी मुंह मांगी कीमत पर खरीदते रहे।यह उनकी खोज के माध्यम से अनाप-शनाप, अंट शंट विषय वस्तु परोसेने का और उपभोक्ता के समय बर्बाद करने का बहुत भारी षड्यंत्र है।

यह सब जानकर भी हमारे देश की सरकार मुख्य रूप से भाजपा बनाम भुखेरा जन पार्टी के घोर श्याने, जालसाज, झूठे, मक्कार, मूढ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सलाहकारों के इशारे पर आधार कार्ड का सारा डाटा जो कि सबसे पहले अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर पर इकट्ठा होता है इसका प्रबंधन का काम भी गूगल को ही सौंप दिया गया है बदले में उद्दुत को रू4:50 लाख करोड़ का भुगतान भारत के 8000गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है। जबकि यथार्थ यह है की सरकार ने जनता के मोबाइल और कंप्यूटरों से उसकी बातचीत की, संदेशों के संप्रेषण की जासूसी और नजर रखने के लिए ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष भुगतान दिया है।

आज हालत यह है, कि गूगल ने हीं मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप पर किसी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जानकारी एकत्रित करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का होना आवश्यक बना दिया है बिना उद्दुत प्ले स्टोर के मोबाइल पर कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संग्रहित नहीं होती है। जिसमें भुगतान के लिए बैंकों के खाते पेटीएम, भारत सरकार का भीम, डेबिट क्रेडिट कार्ड आदि के, रेलवे के टिकट और आरक्षण के डाउनलोड से लेकर विमान यात्रा के टिकट भुगतान आदि सब में आपको गूगल प्ले स्टोर की आवश्यकता पड़ेगी बिना उसके कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता। यह सब हरकतें यथार्थ में उपभोक्ता की हर जानकारी पर नजर रखने उसकी मानसिकता, दैनंदिनी आदतों, कार्यशैली की गतिविधियों पर नजर रखने ताकि सरकार उसके लेन-देन, आय, कमाई के स्रोत, खर्च की आदतों पर नजर रख और उसका डाटा संग्रहित कर आसानी से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बैंकों को, मोबाइल कंपनियों को, सरकार के गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों जांच एजेंसियों को भारी कीमत के बदले उपलब्ध करवा कर न केवल आसानी से मोटी कमाई करती हैं, वरन हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों सरकार राजनीतिक पार्टियां से लेकर अपराधी तक अपने हित साधन करते हैं और उसका मोबाइल लैपटॉप व कंप्यूटर उसकी हर जानकारी को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक कर देते हैं जिसमें गूगल की बहुत ही नीचता पूर्ण, महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

निसंदेह गूगल, गूगल के संस्थापक से लेकर उसके सारे कर्मचारी अधिकारी अपने आपको भले ही महान समझ मोटी कमाई कर मोटे मोटे करोड़ों अरबों में वेतन भत्ते और लाभ प्राप्त कर रहे हो। परंतु कब तक वर्तमान की युवा पीढ़ी जो आधुनिक संचार माध्यमों की तकनीक को जहां एक तरफ अपने आप को उपयोग करने में धन्य समझती है ।वहीं दूसरी और वह मन ही मन अपनी गोपनीयता को भंग होते हुए देख और परेशानी में पड़ने के कारण, सभी आधुनिक संचार साधनों को भी दिल से कोसती भी है। हालात इतने बुरे हैं कि घर के बच्चों के बारे में स्वयं जो बात माता पिता स्वयं नहीं जानते। उससे ज्यादा उनके बच्चे के बारे में शिक्षण, कोचिंग, संस्थान, राजनीतिक पार्टियां, देशी- विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मोबाइल, बैंक, बीमा, वाहन, पिज्जा बर्गर विक्रेता, सेक्स रैकेट चलाने वाले, आदि के पास ज्यादा जानकारी होती है। जिसका सदुपयोग सरकार से लेकर बैंक, बीमा कंपनियां, निजी और शासकीय उधार बांटने वाली कंपनियां, बहुराष्ट्रीय, कॉस्मेटिक दवा, वस्त्र, कंपनियां, नशीले पदार्थ बेचने वाले, हैकर्स, जालसाज, ठग, ड्रग माफिया, सटोरिये, सेक्स रैकेट, वैध अवैध हथियार बेचने वाले आदि अपने उपयोग में ला कर अपने धंधे को चमकाने और धन कमाने में लगे हुए हैं।

इसके साथ ही गूगल पर किसी भी सर्च में जाने पर,गूगल काम की बातें कम व्यर्थ समय बर्बाद करने के दूसरे हर पेज पर 4-4,6-6विज्ञापन पहले दिखाता है। इस चक्कर हर उपयोगकर्ता के हर दिन 2 से 5 घंटे में बर्बाद करता है इस प्रकार पूरे विश्व में यदि 200 करोड़ लोग हर दिन उल्टी-सीधी खोजबीन के चक्कर में 400 करोड़ घंटे बर्बाद करते हैं। फिर भी उसमें समझ में नहीं आता कि सच और वास्तविकता में हम जिसकी खोज कर रहे हैं उस से संबंधित तथ्य वही है या अन्य जिसमें उपभोक्ता को भारी समय की हानि होती है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अपना एकाधिकार बनाकर चारों तरफ हर कंप्यूटर और मोबाइल की कार्यपद्धती या एप्लीकेशन को मात्र गूगल प्ले से लेने की या डाउनलोड करने की धूर्तता पूर्ण षड्यंत्र की रचना की है, उसके खिलाफ इंग्लैंड व अन्य देशों में उपभोक्ताओं ने के खिलाफ न्यायालय की शरण ली और क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की है इसमें न्यायालयों ने इस कार्य और एकाधिकार के विरुद्ध खुलकर टिप्पणियां की हैं और शासकों व सरकारों से इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहकर भारी जुर्माना भी ठोका है जो मेरे द्वारा लिखे गए तत्वों की पुष्टि करता है यथार्थ में इसके माध्यम से पूरी दुनिया की हर उपभोक्ता के ऊपर बड़ी बारीकी से नजर रख उसकी हर गतिविधि के दस्तावेज संचित करता रहता है यह सरकारें भी जानती हैं पर हमारे देश की सरकार इस धूर्त के सामने नतमस्तक होकर उसे देश के अंदर शासकीय डाटा से लेकर जनता के आधार कार्ड के डाटा तक को प्रबंधित करने का अवसर प्रदान कर अरबों रुपए का भुगतान कर रही है मात्र इसलिये की वह उसे आसानी से चुनाव जीतने के लिए जनता को फेस्बूक, ट्विटर,व्हाटसएप, इंस्टाग्राम व अन्य सोशल साइटों पर जनता को भ्रमित करने के लिए अपने संदेश, अपनी तारीफें, दहशत व अन्य हथकंडों के समाचार जनता को उसके मोबाइल नंबर पर ईमेल पर फेसबुक खातो पर, आसानी से भेजने के साथ ही अपने विरुद्ध चलने वाली हर खबर का खंडन करने, उड़ाने, गायब करने से लेकर उसके शब्दों में हेर फेर कर अर्थ का अनर्थ कर, लिखने वाले उपभोक्ता का मजाक उडा सकें, कानूनी कार्रवाई मैं उलझाकर उसे गिरफ्तार कर परेशान करने से लेकर मरवाने तक सारी कृत्यों को आसानी से अंजाम दे। सन 2014 की तरह सन 2019 का चुनाव भी जीत सके। इसके साथ ही सामान्य दिनों में मोदी के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए नोटबंदी, माल एवं सेवा कर, फुटकर व्यवसाय में शत प्रतिशत विदेशी निवेश, 70 से ज्यादा विदेश यात्राओं में रुपए 50 लाख करोड़ से ज्यादा की बर्बादी, कश्मीर में आतंकवाद को न रोक पाना, चीन की धमकियों के सामने झुक जाना,पाकिस्तानी आतंकवाद को न रोक पाना, सत्ता हथियाने के लिए राज्यों में छल कपट और कूटनीति के माध्यम से अपनी ही पार्टी के नेताओं का कद छोटा करना भाजपा के संस्थापकों यथा अटल बिहारी वाजपेई, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी आदि को नीचा दिखाना, विरोधी पक्ष की सरकारों को परेशान करना जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अच्छे कार्यों के समाचारों को सोशल साइट पर चलने से रोकना. जीमेल पर भेजे गए समाचारों वह पत्रों की जासूसी करना उसके बारे में सरकार को सूचित करना आदि काम में भी ये धूर्त अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं बेशक उसकी बदतमीजी से दुनिया का जीमेल और इसके सर्च इंजिन का उपयोग करने वाले 90% उपभोक्ता भारी हैरान परेशान है। निसंदेह इसीलिए चीन अपने यहां इसके विकल्प के रूप में नया सर्च इंजन बना रखा है उसी के माध्यम से खोजबीन और ईमेल का आदान प्रदान किया जाता है पर हमारे भारत में तो हमारी निकम्मी मुढों की भुखेरा जन पार्टी की सरकार को इन सब से कोई सरोकार नहीं। मामला केवल भारत और भारत की जनता का ही नहीं है। वैसे भी यह कोई भारतीय कंपनी तो नहीं है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता की भारत के डाटा जो कि शासकीय तंत्र का है या निजी संस्थानों के साथ किसी का व्यक्तिगत डाटा है उसे केवल अपनी प्रतिदिन अरबों डॉलर की कमाई से मतलब है। उसके लिए क्या भारत पाकिस्तान और चीन व अन्य मित्र व शत्रु राष्ट्र जिसको जिसका डाटा चाहिए हो वह भुगतान करें और व्यक्तिगत संस्थानिक शासकीय रक्षा वैज्ञानिक शोध आदि का जो भी डाटा चाहिए हो ले जाए क्योंकि सारा डाटा उसी के पास संग्रहित होता है । यही कारण है कि भारत की शासकीय संस्थानों की जानकारियों से लेकर सेना पुलिस बालों की अत्यधिक गोपनीय जानकारी भी पाकिस्तानी घुसपैठियों से लेकर आतंकवादियों चीनियों आदि को भी आसानी से मिल जाती है जिससे वे हमारे देश में ही हमारी हर गतिविधि पर नजर रखकर हमारी सुरक्षा से लेकर हमारी व्यवसाय गतिविधियों तक पर ना केवल सेंध लगाते हैं हमारी सेना के जवानों को मारते हैं हमारे देश के व्यवसाय को चौपट करने पर तुले रहकर हमारे देश में करोड़ों की बेरोजगारी, लाखों उद्योगों का बंद होना आदि के कार्यों को भी पिछले 15-17 वर्षों से अंजाम दे रहे हैं यह सरकार को कभी समझ में नहीं आया कि इस जेसे सपोले को पाल कर, उसे अरबों रुपए का धन इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के नाम भुगतान कर रहे हैं वह हमारे देश की सरकारों सेना और जनता की जड़ें काटकर कैसे हमारे देश के साथ ही दुनिया के अन्य पूरे देशों की बर्बादी का करण बना हुआ है। यही कारण है की दुनिया के आतंकवादी संगठनों को आसानी से भर्ती करने के लिए उनके संगठन में पूरी दुनिया के मुसलमानों को आसानी से बरगलाकर वे संगठन अपने लिए दुर्दांत लड़कों की भर्ती अपने संगठन में आसानी से कर लेते हैं साथ ही इस्लामिक स्टेट विचारधारा को पूरी दुनिया में फैला कर युवाओं को भ्रमित कर आसानी से अन्य सामान्य जन को आतंकित एवं प्रताड़ित करते रहते हैं यह गूगल का ही कारनामा है उसे पूरी दुनिया हैरान परेशान है

यही हाल फेसबुक का भी है फेसबुक के माध्यम से भी इस्लामिक स्टेट ने न केवल युवा लड़ाकों को भर्ती किया वरन उन्होंने विश्व के हर कोने से युवा लड़कियों को भी आसानी से भ्रमित कर उन्हें भी भर्ती कर लिया गया और आतंकवाद के लिए उकसाया गया जिसमें भारत के हैदराबाद व अन्य स्थानों से लड़कियां इन आतंकवादियों के साथ शामिल हो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गई।इसमें भी Google और Facebook ने अपनी अहम भूमिका अदा की इसको देखते हुए आवश्यक हो गया है सबसे पहले Google Facebook आदि पर भाजपा सरकार को अपने क्षुद्र चुनाव जीतने की षड्यंत्रकारी नीति त्यागकर सबसे पहले इन पर नियंत्रण किया जाए अन्यथा भविष्य में यह ना केवल व्यक्तिगत रूप से देश की जनता वरनदेश की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक घातक होगा।

आपस में लड़-लड़ कर ही हिंदुओं, कर लेना अपना अस्तित्व समाप्त

पेज 16 का शेष

इसी प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी अपनी श्रेष्ठता का अहंकार त्याग आने वाले भविष्य में अपने परिवार की समाज की सुरक्षा के लिए एकत्रित होकर उपाय करने ही होंगे अन्यथा सरकारी राजनीतिक पार्टियां सभी वोटों के लालच में बिखराव के कारण इनकी समाप्ति में गुरेज नहीं करेंगे और वर्तमान में भी नहीं कर रही हैं निसंदेह सभी राजनीतिक पार्टियां और सरकार सवर्णों के धन के दम पर ही इतना उचकती कूदती है। यहीं भाजपा जब अपनी शैशव अवस्था में थी तब हिंदुओं को हिंदुओं की पार्टी कहकर सबसे ज्यादा चंदा सवर्णों से ही लूटा गया। उस के दम पर ही यह भूखेरा जन पार्टी आज जब केंद्र सत्ता में है सबसे ज्यादा सवर्णों को ही लूटकर सवर्णों का ही संहार कर रही है। इस अवस्था में ब्राह्मणोंो को वेदों का, शास्त्रों का और तप का सहारा लेकर, अपनी प्राचीन विद्याओं की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए उन्हें चाहिए कि वे उन शक्तियों को जागृत करें और उन शक्तियों के आधार पर समाज की समृद्धि जनसंख्या विस्तार और सुरक्षा को सुनिश्चित करें अन्यथा भारत में शीघ्र सवर्णों का भी अंत हो जाएगा और यह श्रेष्ठता का अहंकार मृत्यु के साथ खत्म होने और हिंदुओं का अस्तित्व पृथ्वी से नष्ट होने का कारण बन जाएगा। किसी ब्राह्मण को अपने ज्ञान धर्म और शक्तियों का जो उन्हें उनके पूर्वजों ने दी है यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो निरर्थक है उनके ज्ञान और श्रेष्ठता का हंकार हमको चाहिए कि वे अपनी शक्तियों को जागृत कर सबसे पहले शक्तियों का प्रदर्शन कर विश्व को यह दिखाएं कि वे अभी भी पूर्व की तरफ नहीं सक्षम और संपन्न है जो उनके आक्रमणों और षड्यंत्रों से रक्षा करने में सक्षम है अन्यथा पौराणिक शक्तियां जो अभी भी विद्यमान है यदि उपयोग नहीं किया गया तो ब्राह्मणों आपका ब्राह्मण होना ही निरर्थक है आवश्यक यह है कि उन पर पुनः ध्यान केंद्रित कर तंत्र मंत्र के साथ मस्तिष्क की तरंगों को संघनित कर प्रक्षेपित करें और शत्रुओं को नष्ट कर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करें। वर्तमान युग ही नहीं अनादि काल से शक्ति का प्रदर्शन किया जाना श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता था और वर्तमान में भी है। तो आखिर ब्राह्मण क्यों इन शक्तियों को उपयोग कर प्रदर्शन नहीं करते जो होना होगा वह होगा परंतु अपने पास रखे ज्ञान धन का उपयोग समय पर ना किए जाने का दुष्परिणाम ही है जो आज ब्राह्मण समाज निर्धन और हेय की श्रेणी में आ गया है। वही हाल क्षत्रियों का भी है, जो अपने बल का दुरुपयोग सुरा सुंदरी के भोग में लगाकर नष्ट होते रहे अभी भी वक्त है जागे और शक्तियों को पुनर्जीवित कर श्रेष्ठता का परिचय दें अन्यथा आप का अहंकार आपको नष्ट होने की कगार पर ले आया है।

पुलिस का वर्तमान देख कर भविष्य निर्धारित किया जाना चाहिये... बना दो इंदौर को अपराधों की महा राजधानी

पुलिस कमिश्नर सिस्टम से बढ़ेगी पुलिस की वसूली-लूटपाट, और संगठित अपराध

> **पहले से ही पुलिस संगठित अपराधियों को संरक्षण देकर स्वयं करवाती है, अपराध और करती है, वसूली**

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में पुलिस कमीशनरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की है जिसमें पुलिस को और ज्यादा अधिकार मिल जाने पर पुलिसकी वसूली और लूटपाट का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा।

यथार्थ में यह पुलिस को नियंत्रण के साथ ही कानून को अपनी मर्जी से मोटे धन का लेनदेन करके अपराधियों को संरक्षण देकर बिना न्यायालय भेजें ही अपराधियों को अपराध करने के लिए खुला छोड़ देंगे, दूसरी ओर बड़े से बड़े अपराध में भी छोटी धाराएं लगाकर उसे आसानी से थाने से ही से विदा कर दिया जाएगा। जो कि और ज्यादा घातक होगा। वर्तमान की तरह अभी भी पुलिस ९९३ अपराधों में फरियादियो को पहले तो अधिकांश थानों में गहन-गंभीर अपराध में भी भगा देती है। फिर दबाव पड़ने पर उससे आवेदन लेकर चलता कर देती है।

यदि फरियादी भारी होता है, तो भी बिना पैसे लिए उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती यह सिलसिला भारत के सभी प्रदेशों की पुलिस का है। स्वाभाविक है इससे मध्यप्रदेश और उसका इंदौर महानगर भी इससे अछूता नहीं है। हर दिन ही इस प्रकार की खबरें अखबारों में छपती रहती हैं।पर घोर बेशर्म, हरामखोर और मक्कार पुलिस, पुलिस के सहायक, उप और थाना निरीक्षको को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जो स्वयं को नकारा और निकम्मा मानते हैं, और यह भी मानते हैं कि उन्हें अफसरशाही जैसा नचाती है वैसा वह नाचते हैं। बेशक इस फैसले के अचानक आ जाने से यह तो सिद्ध होता है। कि भविष्य में आने वाले चुनावों के लिए, यह व्यवस्था अपने प्रतिद्वंदियों को, विपक्षी पार्टियों, कांग्रेसी नेताओं के साथ, अपने ही भाजपाई खेमे में बागी हुए लोगों को निपटाने में काम आएगा। दूसरी तरफ अपने चुनाव जीतने के लिए अपने पार्टी के लोगों जो अपराधों से जुड़े हुए हैं और स्वयं अपराधी हैं, को बचाकर जनता को डराने धमकाने के लिए गुंडों को संरक्षित करने के काम आएगा क्योंकि फिर मामला न्यायाालय तक जाएगा ही नहीं। थानेदार, नगर अधीक्षक, उप अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्वयं ही अपने आकाओं की सेवा व जी हजूरी करने के लिए अपराधियों को छुटटा छोड़ देंगे। ताकि आसानी से सत्तारूढ़ दल अपने विरोधियों को निपटाता हुआ चुनाव जीत सके।

वर्तमान में भी पुलिस स्वयं ही नशीली दवाओं, मादक पदार्थों और अवैध शराब को बेचने वाले माफियाओं को, जबकि इंदौर में ही नारकोटिक्स का थानेसे लेकर अधीक्षक तक का ऑफिस पलासिया में ह पर कार्रवाई के नाम पर यहां का सारा स्टाफ केवल कागजी खानापूर्ति करअपनी महीना वसूली में व्यस्त रहता है । ज़बकि इंदौर प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र होने के साथ, शिक्षा और चिकित्सा का भी देश और प्रदेश का बड़ा केंद्र है।

(शेष पढे अगले अंक में)

महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण के नाम ...

पेज 16 का शेष

इसमें 13 योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश जन धन कागजों पर ही खर्च किया जा रहा है जिसको देख रेख करने वाला और हिसाब किताब रखने वाले लोग भी गैर अनुभवी मनचाहे तरीके से अपने अपनों को मोटी वसूली कर अपनी मर्जी से भर्ती किए गए हैं कि तेरा योजनाओं में समेकित बाल संरक्षण योजना जिसंमे 'विधि विवादित, निराश्रित, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले, सड़क पर निवास करने वाले, सड़क पर कचरा बीनने वाले तथा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की देखरेख का शासकीय स्तर पर कार्य किया जाता है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनॉक 01.04.2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई वन स्टॉप सेंटर सखी के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित वन स्टॉप सेंटर (सखी)/ उषा किरण योजना (राज्य मद) अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेन्टर/उषा किरण केन्द्रों में उपलब्ध करायी जायेगी परंतु यहां पर भी केंद्र को विकसित करने के नाम केंद्र अधिकारी अधिकांश महिलाएं होती है ऐसी पीड़ित महिलाओं को ना सहायता उपलब्ध करवाती हैं एवं राशन की व्यवस्था करती है और यह सब कागजों पर दिखाकर हजम कर लिया जाता है।

लाडो अभियान के अंतर्गत सूचना मिलने पर, मूल कार्य बाल विवाह को रोकना ही है। वर्तमान में इस अभियान की यथार्थ में आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि केंद्र और राज्य स्तर पर महिला बाल विकास के व समाज कल्याण के सभी सभी अनुभवियों को सोचना चाहिए जब प्रचार माध्यमों में ही जिनमें ऊन्न, इंटरनेट, फिल्म आदि में 24 घंटे विज्ञापनों, लघु नाटिका के माध्यम योनाचार परोसा जा रहा है। स्कूलों-कॉलेजों आदि के शिक्षा केंद्रों में स्वच्छंद वातावरण की स्थितियां बन चुकी है और शासन स्वयं ही निरोधक वेंडिंग मशीन लगा रहा है तो बेहतर यह होता शादी की उम्र को हटाकर 18 से 16 का दी जाती ताकि सुरक्षित वातावरण भी पारिवारिक माहौल तैयार किया जा सकता था। शौर्य कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को स्वमेव विपरीत परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिये शिक्षित किया जाता है ।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गतविपत्तिग्रस्त, पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/ सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा जिन संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री/ प्रमाण पत्र शासकीय/अशासकीय सेवाओं मे मान्य हो। प्रशिक्षण पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय का वहन विभाग के द्वारा किया जावेगा, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन आदि शामिल रहेगा। महिलाओं का चयन जिला स्तर पर गठित समिति व्दारा किया जायेगा। परंतु यह सब भी केवल कागजों की शोभा बढ़ाते हुए शासकीय धन को हजम करने का माध्यम ही बन गए हैं यथार्थ में इस दिमाग में पर्याप्त स्टाफ का अभाव है इसलिए कार्यरत स्टाफ केवल आंकडों की बाजीगरी कर धन हजम कर जाता है।

यह भ्रष्टाचार का आलम यह है सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर पहले तो आवेदन लेने में ही काफी ना नुकुर की जाती है और यहां से टरकाया जाता है। फिर यदि आवेदन ले भी लिया गया तो 90% मामले में पत्रों के जवाब ही उचित तरीके नहीं दिए जाते, पत्र जवाब मिल भी जाते हैं। तो या तो समय उपरांत होते हैं, या उसमें आवेदकों के अनुसार चाही गई जानकारी के अपेक्षा उल्टे सीधे होने पर अपील की सुनवाई जिलाधीश और संभागायुक्त करते हैं स्वभाविक है कि इन्हें भी महीना मिलने के कारण हरामखोर उसे लंबे समय तक लटकाने के बाद उन तीनों अपीलों को रद्द कर देते हैं। इसीलिए जिलाधीश और आयुक्त के रूप में बैठे घोर जालसाज, हरामखोर भारतीय प्रताडना सेवा के अधिकारी जिनका दायित्व है, कि वे सभी जिलों और संभाग के सभी कार्यालयों पर निगरानी रखें परंतु उनकी निगरानी का तात्पर्य वसूली से होता है और वे सब महिना डकार कर सभी भ्रष्टों को लूटने की पूरी छूट देते हैं। वे अपने अंतर्गत कार्य करने वाले सभी जिलाधिकारियों को तभी पूछताछ और जांच पड़ताल करते हैं जब इन शूकरों की फौज को महीना मिलना बंद हो जाता है।

विश्व में प्रदूषण के लिए यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार

पेज 16 का शेष

पर इसके विपरीत कार कंपनियों, बाइक्स, ट्रक बसें जलपोत और वायुयान कंपनियों ने अपने उत्पादन बंद कर दिए जो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से सबसे ज्यादा वायुमंडल को नष्ट करने को तुले हुए हैं। दुनिया के अधिकांश देश अमेरिका और यूरोप के साथ एशिया महाद्वीप के चीन भारत जापान सबसे ज्यादा कार, बसों, ट्रकों का आवागमन के लिए उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से जो धुआं निकलता है वह वायुमंडल को दूषित करने के साथ ही उसने अधिकांश देशों में मौसम का चक्कर भी बिगाड़ दिया है जिससे अल्प वर्षा अधिक तेज गर्मी, शीत पढ़ने के साथ ही भारी बर्फबारी, हिमालय के ग्लेशियरों का खत्म होना, सूख जाना,नदियों के बहाव का कम होना, या अत्यधिक बाढ़ आना, छोटी नदियों, नालों जो कि इन बड़ी नदियों के जल के स्त्रोत हुआ करते थे गायब या सूख जाना।यह सब मानव की लालची प्रवृत्ति का ही परिणाम है। दुनिया और विशेष तौर से अमेरिका और यूरोप की सरकारें प्रदूषण को लेकर हल्ला तो भारी मचाती हैं । बड़े-बड़े कार्यक्रम, सभाएं और सम्मेलन करती हैं। जिन्हें उन देशो में बैठी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं।इन नेताओं और सरकारों को वित्तीय सहायता देकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित भी स्वयं ही करती हैं ताकि मानव वह पृथ्वी के वायुमंडल के हितैषी होने कापाखंड कर सकें। निसंदेह बढ़ते प्रदूषण के कारण हर देश की सरकारों में अपने यहां प्रदूषण नियंत्रण मंडल का सरकारी कार्यालय खोल रखा है परंतु यह सभी प्रदूषण मंडल या विभाग इस प्रदूषण नियंत्रण की आड़ में मोटी वसूली कर प्रदूषण फैलाने का कार्यक्रम चलाते हैं बेशक यह सच भारत चीन अमेरिका और जापान व अन्य देशों में तो सच है परंतु स्विट्ज़रलैंड व अन्य अनेकों राष्ट्र प्रदूषण के प्रति काफी गंभीर भी है। हर वर्ष पूरी दुनिया में पॉलिथीन, प्लास्टिक, एलुमिनियम जिलेटिन, आदि के पेकिंग सामग्री के कचरे से लगभग 30लाख टन कचरे से धरती के साथ यह पॉलिथीन, प्लास्टिक, एल्युमीनियम फाइल का यह कचरा नदी नालों से बहता व होता हुआ समुद्रों के गर्भ में एकत्रित हो रहा है जिससे हर वर्ष करोड़ों जलीय जीवो और वनस्पतियों की प्रजातियां नष्ट होने के साथ ही बची हुई प्रजातियों की प्रजनन क्षमता भी कम होती जा रही है। जिससे समुद्र का जल अत्यधिक प्रदूषित होने के साथ ही विषैला भी होता जा रहा है। यही हाल धरा पर जीवित प्राणियों यथा मानव के साथ ही वन्य प्राणी पशु पक्षियों कीटो के साथ वनस्पतियों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि ना केवल वायुमंडल में ऑक्सीजन व जल की कमी के साथ आद्रता की भी कमी होती जा रही है।पिछले 50 वर्षों में हजारों पशु पक्षियों और वनस्पतियों की प्रजातियां धरती से लुप्त हो गई है। भारत के वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन लगभग 20 पशु पक्षियों व अन्य प्राणियों की, वनस्पतियों की प्रजातियां भी नष्ट हो रही है जो केवल मानव रूपी गिद्ध के भारी लोभ-लालच और मौत का परिणाम ही है। भारत में ही हमारे देश के महा धूर्त, और सरकार को पिछाड़ू जेब मैं रखकर चलने वाले अंबानी बंधुओं न हीं मोदी सरकार को दबाव डाल कर प्लास्टिक को जो कि उसकी रिलायंस रिफाइनरी का सह उत्पाद है और हर दिन हजारों टन क्रूडपेट्रो के डीजल पेट्रोल शुद्धिकरण से प्राप्त होता है। की विपणन व्यवस्था भारी खपत के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक को पुनः पिघलाकर दूसरे शब्दों में प्रयोग लाने की के कार्य को बंद करवा दिया ताकि उसके रिलायंस रिफाइनरी से निकले हजारों टर्न प्लास्टिक दाने का उपयोग लगातार होता रहे और उसकी बिक्री लगातार बनी रहे जो उसके लाभ का एक बड़ा हिस्सा है। यथार्थ में पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारे बड़े पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही चलाई जाती है यह सच पूरी दुनिया में एक समान लागू होता है यह पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जनता की जेब पर डाका डालने, लूटने,शोषण करने, मोटे लाभ के लिए सरकार में बैठे मंत्रियों अधिकारियों को मोटी रिश्वत बांटकर,खरीदकर सरकारों पर दबाव डालकर अपनी मनमर्जी से कानून बनवाती हैं। फिर सरकार को नचा कुदा कर अपने प्रतिद्वंदियों, छोटे व्यापारियों को नष्ट करने के लिए मनमर्जी से शासकीय तंत्र का उपयोग करती है हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश और देश में छोटे व्यवसाइयों, ठेले वह सड़क पर माल बेचने वालों को व्यवसाय बंद करने, उनका रोजगार छुड़ाने, प्रतिद्वंदिता खत्म करने देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, सचिव, क्षेत्रीय स्तर के मंत्रियों, महापौरों, पार्षदों व नगर निगमों, पालिकाओ,परिषदों के निगम आयुक्त, व अन्य अधिकारी कर्मचारियों, जिले के जिलाधीशों, उप जिलाधीशों से लेकर थानेदार पुलिस अधीक्षक, आदि को खरीदकर. नगर की स्वच्छता के नाम, स्मार्ट सिटी के नाम व अन्य कई तरीकों से सड़क पर फुटपाथ पर छोटे व्यापारियों पर पतली पॉलीथिन के नाम पर ठेले वालों सड़क पर माल बेचने वालों छोटे दुकानदारों आदि के ठेले व सामान जप्त कर, सामान में लूटपाट हुई, बाद में उनके ठेले तोड़ दिए गए उन्हेंउसकी बिक्री लगातार बनी रहे जो उसके लाभ का एक बड़ा हिस्सा है ।

साप्ताहिक समय माया

श्रेष्ठता के छद्म अहंकार में चूर, बामन, बाणिया, ठाकुरा, जाति देख गुर्राये, इसीलिए समाप्ति की कगार पर आए

आपस में लड़-लड़ कर ही हिंदुओं, कर लेना अपना अस्तित्व समाप्त

सहस्त्रों वर्ष के इतिहास से भी सीखने को तैयार नहीं, मात्र श्रेष्ठता के घमंड मे नष्ट होने को तैयार अवश्य है। यह है दुनिया की श्रेष्ठ कोम, जिसने पूरे विश्व को भाषा, ज्ञान, धर्म, विज्ञान सिखाया, वह शीघ्र नष्ट होने की तैयारी में है मात्र अपने अहंकार और बिखराव के कारण।

वर्तमान काल से 2020 वर्ष पूर्व जब न मुस्लिम थे, न ईसाई, तब मात्र हिंदू ही थे और पूरे विश्व में हिंदू धर्म का साम्राज्य था। आखिर क्या कारण था कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म सिमटते-सिमटते भारत में और भारत में भी वर्तमान में 12 राज्यों में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आ चुके हैं। उसके पीछे मात्र एक कारण था वह था ब्राह्मणों को ज्ञान का, वैश्यों को धन का, और क्षत्रियों को बल का छद्म श्रेष्ठता का अहंकार। इसी अहंकार में इस देश पर सहस्त्र वर्षों से विदेशी आक्रांताओं के अनेकों आक्रमणों में, अधिकांश बार पराजय का स्वाद चखते रहना बदले में ही उन आक्रांताओं द्वारा हमारी धर्म, संस्कृति, मंदिरों, नगरों को बार-बार लूटा जाना बदले में हमारे देश के नागरिकों द्वारा उनकी गुलामी किया जाने का अच्छा खासा इतिहास रहा है। इसके विपरीत इस इतिहास से वर्तमान में भी सारी हिंदू जातियां जो कि नष्ट होने की कगार पर आ चुकी हैं। सुधरने को और एकत्रित होकर अपने अतीत को बचाने का प्रयास करना नहीं चाहती उसके विपरीत जातिवाद के चक्कर में आपस में ही लड़ लड़ कर नष्ट होने को तैयार बैठे हुए हैं जबकि इतिहास हर बार सबक सिखाता रहा पर यह अहंकार खत्म होने का नाम नहीं लेता। निसंदेह इस देश की महिलाओं ने अपने पति, पिता और पुत्र रूपी पुरुष को स्वाभिमान का और एकत्रित होकर विस्तार करने और जँग लड़ने का पाठ कभी नहीं पढ़ाया। यही कारण था हमारे देश की महिलाओं ने सदा ही पति, पिता और पुत्र को बहुत स्वार्थी, डब्बू और धर्म के अनुकूल हिंसा से बचने की सलाह दी। यही सलाह हिंदुओं के लिए अभिशाप बन गई। जबकि हर आक्रमण और पराजय के बाद सबसे ज्यादा अपमान बलात्कार और हत्याएं महिलाओं की ही की जाती थी। यही अभिशाप शताब्दियों से हिंदुओं को, हिंदुओं की संस्कृति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान को न केवल नष्ट करने वरन् आक्रांताओं विदेशियों द्वारा हर हिंदू साम्राज्य पर हमला करने के बाद हुई पराजय में सबसे पहले उसने पुरुषों को नष्ट करने के साथ,हिंदू महिलाओं के बलात्कार और अपनी रखेल बनाकर रखने के बाद, मंदिरों, गुरुकुलों के साथ अध्ययन शालाओं को ही नष्ट किया। दूसरी ओर अंतिम आक्रांताओं, डच,पुर्तगीज के बाद अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से व्यापार के बहाने भारत में आकर पहले व्यापार किया फिर मौका पढ़ते ही छोटी-छोटी हिंदू रियासतों से

युद्ध कर या छल कपट से हथियाकर, फिर बड़े-बड़े मुस्लिम शासकों से युद्ध किया इस बीच उन्होंने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए सबसे पहले यहां की भाषा संस्कृति को नष्ट करने आपस में ही हिंदुओं को हिंदुओं से, मुस्लिमों से लड़वाकर आसानी से अपनी अब सत्ता स्थापित की। इस बीच उस हिंदू संस्कृति के श्रेष्ठ ज्ञान को ब्राह्मणों से, व्यापार के लिए वेश्यों का और युद्ध के लिए क्षत्रियों का भरपूर उपयोग कर अपने देश को समृद्ध बनाया।

भारत में जातियों के बिखराव ने हीं भारत की समृद्ध संस्कृति के अंतर्गत सभी धर्मों में कर्म को प्रधान बना गया वैष्णव से संबंधित जैन धर्म में भगवान महावीर ने 2557 वर्ष पहले भी यही कहा था कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है और कर्म की प्रधानता भारत में अनादि काल से ही वर्तमान तक जारी है जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा। वह वैसा ही पहचाना जाएगा। महर्षि बाल्मीकि जिनका जन्म शूद्रों में हुआ था परंतु उनके ज्ञान शिक्षा ने उन्हें महर्षि की उपाधि से विभूषित किया।

यही हाल महर्षि वेदव्यास काा था कि वह भी शुद्र में पैदा हुए थे परंतु उनकी ज्ञान और शिक्षा नहीं उन्हें भी महर्षि की उपाधि से विभूषित कर गीता और महाभारत लिखाा जिन्होंने रामायण लिखी थी और वह रामायण राम के जन्म से लेकर जो उन्होंने द्वापर में लिखी थी सहस्त्रों वर्ष बाद भी ना केवल भारत को वरन विश्व के सभी देशों को सामाजिकता और नैतिकता का पाठ पढ़ाती रही है। पर वर्तमान में अपने आप को दलित कहने वाले या वोटों की राजनीति ने उन्हें इस श्रेणी में रखा है और वह भी सामाजिक परिवेश में बदलकर अपने आपका स्वयं उत्थान करना नहीं चाहते मात्र शासन के धन का और आरक्षण का लाभ लेने के लिए वह उसी श्रेणी में रहने के इच्छुक रहते हैं। इस प्रकार वह अपनी जाति के आधार पर शासकीय नौकरियों में अपनाा प्रभुत्व चाहते हैं। जबकि सामान्य श्रेणी में आने वाले ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों जिनके करों में लूटे गए, धन से वास्तविकता में आदिवासियों और नीचे तबके के लोगों को शिक्षा देकर उनका विकास करना था परंतु इसे उन्होंने अपना अधिकार समझ लिया जिसके चलते अब भारत में एक नए वर्ग संघर्ष का जन्म हो चुका है। जिसके चलते हाल ही में पूरे देश में 2 अप्रेल जो आंदोलन किया गया, जिसे राजनीतिज्ञों ने काफी हवा दी। यह भी यथार्थ में सवर्णों के लिए एकत्रित होने का सबक था। जिसे देख कर भी सवर्ण एकत्रित नहीं हुए। बेशक इस संघर्ष को हवा देने में पाकिस्तानी आईएसआई ने धन की व्यवस्था की अनावश्यक रुप से दलित संघों को आंदोलन में तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया। यह सब घटनाएं यथार्थ में हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र था परंतु इन सब से सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर अपने अधिकारों के साथ जनसंख्या विस्तार के लिए भी कार्य करना चाहिए। श्रवण जो करोड़ों अरबों रुपए का टेक्स्ट सरकार को देते हैं स्वयं समाज की भलाई में उपयोग नहीं कर सकते जब कि नहीं चाहिए कि सभी अपने गरीब समाज जनों को उनके बच्चों को निशुल्क शिक्षा निवास आदि की व्यवस्था अपने सरकार को दिये जाने वाले टैक्स में से करना चाहिए। सभी स्वरोजगारी हिंदुओं को जो कि किसी शासकीय सेवा में नहीं है और ना ही वह शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं उन्हें ना केवल रोजगार देने के लिए सभी सवर्णों को अपने उद्योगों कार्यालयों दुकान वादी में रोजगार देकर उन्हें अधिकतम बच्चे पैदा करने और बच्चों की देखरेख करने के लिए समाज की ओर से निशुल्क छात्रावास और शिक्षा की व्यवस्था समाज की तरफ से की जानी चाहिए ताकि सवर्णों की घटती जनसंख्या को रोका जा सके और आने वाले समय में हिंदुओं की घटती आावादी को बढ़ाया जा सके। आखिर धनाढ्य सवर्ण वर्ग अपनी श्रेष्ठता और धन के अहंकार को कब जागेगा। जब उसकी आंखों के सामने ही सरकारी, राजनीतिक गुंडे, छल बल से उसकी संपत्तियां व परिवारजनों को धन की खातिर नष्ट करते रहेंगे और वह अपने ही कमाए हुए धन को अभिशाप के रूप में भोगता रहेगा।

इससे ज्यादा बेहतर होगा की सभी सव ्और हिंदू एकत्रित होकर अपने कमाए हुए धन का उपयोग अपने समाज के विकास और जनसंख्या विस्तार के लिए दान करते रहें जैनी जो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में है उनको चाहिए कि जो निर्धन या गरीब कम आय वाले जैन परिवार के याा जो भी जोड़ा 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है उसे सामाजिक रूप से सम्मानित करें उसके बच्चे की निशुल्क शिक्षा छात्रावास निर्धन या गरीब कम आय वाले जैन परिवार सामाजिक सहायता उस गरीब परिवार की लड़कियों की समाज की ओर से शादी करवाई जानी चाहिए अन्यथा जैनियों का या पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। **(शेष पेज 15 पर)**

महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण के नाम हो रहा अधिकारी-कर्मचारियों का विकास सशक्तिकरण

13 योजनाओं में करोड़ों की बर्बादी जिसको जहां मिले लूटो खाओ उचित देखरेख का अभाव

अपने खास लोगों को मोटी रिश्वत लेकर भर्ती कर, नव सिखुवे अधिकारी कर्मचारी, सब को मौके की तलाश महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टचार से लूट्ने, खाने का सिलसिला बहुत पुराना है।

हाल ही में उच्च न्यायालय ने महिला बाल विकास के आंगनबाड़ियों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पर निजी आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा कर उसे शासकीय निगमों से आपूर्ति करने के लिए कहा गया है, यह सिद्ध करता है कि आंगनवाड़ियों में आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य में काफी भ्रष्टाचार किया जा रहा था। यथार्थ में आंगनवाड़ियों में बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार वितरण के मामले में भ्रष्टाचार का सिलसिला महिला बाल विकास विभाग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था यह हाल केवल प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का था। जिसका 70से 90% प्रतिशत पैसा आंगनवाड़ियों के कार्यकर्ताओं से लेकर उनके विकास खंड अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त संचालक महिला बाल विकास से लेकर आयुक्त, सचिव प्रधान सचिव मंत्री औरमुख्यमंत्री तक पहुंचता था इसलिए वास्तविकता में गरीब गर्भवती, या स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के साथ नवजात शिशु से लेकर 10 वर्ष के बच्चों का पोषण आहार पहुंचता ही नहीं था। सारा खेल उपस्थिति दिखाने, पोषण आहार खरीदकर या शासन से प्राप्त कर तैयार करने तैयार करने और वितरण करने का केवल कागजों में ही चला करता था। और वह पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक बंदरबांट में ही पूरा हो जाता था यही कारण है कि सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी देने के नाम पर यह तो बताओ जवाब नहीं दिए जाते या भारी भरकम खर्च बताकर आवेदकों को डरा धमका कर भगा दिया जाता है। जबकि यह सारी जानकारी जिसमें आंगनबाड़ी के बच्चों के रजिस्टर नहीं बच्चों के नाम के साथ, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के नाम व पते बकायदा विभाग की साइट पर उपलब्ध होनी चाहिए थे ताकि कोई भी उनका निरीक्षण कर सकता था। पर मध्यप्रदेश में चलने वाली 97135 आंगनवाड़ियों मैसेज किसी के भी रजिस्टरों की जानकारी ऑनलाइन इसीलिए नहीं की गई की साधारण आदमी भी उनकी सच्चाई का पता लगा सकताथा इससे 90 परसेंट भ्रष्टाचार में धन बर्बाद होने का रास्ता बंद हो जाता। इसीविभाग की एक नई शाखा महिला सशक्तिकरण के नाम से अलग से तैयार की गई क्योंकि इस शाखा में कोई शासकीय वरिष्ठ अनुभव युक्त अधिकारी नहीं थे इसलिए वहां बैठे प्रधान सचिव, सचिव, ने कुछ इसी महिला बाल विकास के अधिकारियों को लेकर इसको प्रारंभ कर दिया।

(शेष पेज 15 पर)

विश्व में प्रदूषण के लिए यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार

जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, हल्ला भी वही मचाते हैं, अपने कुकर्मों को छुपाने

मानवीय संयुक्त घोर गिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लालच ने हीं पूरी दुनिया को भारी प्रदूषण की आग में झोंक, न केवल बर्बाद किया बरन आने वाली मानव पीढ़ियों के साथ, ही जल थल और नभ मैं निवास व विचरण करने वाले वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से नष्ट करने का खतरा खड़ा कर दिया है। अधिकांश कंपनियां यूरोप और अमेरिका की है। जिन्होंने जीवाश्म ईंधन या पेट्रोल डीजल किसका प्रयोग स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है। इस पेट्रोल डीजल के उपयोग से निकलने वाला धुआं और उसके अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के साथ इस जीवाश्म ईंधन के शुद्धिकरण से प्राप्त कार्बन के सह उत्पाद के रूप में जो प्लास्टिक दाना प्राप्त होता है वह खाद्य वस्तुओं के साथ ही सभी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए पैकिंग का जो पॉलिथीन प्लास्टिक बोतल एलुमिनियम जिलेटिन आदि के उपयोग से पूरी दुनिया के जल थल नभ को को दूषित कर दिया। प्लास्टिक और पॉलिथीन यथार्थ में पेट्रो का सह उत्पाद ही है।जो की अधिकांश खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के साथ ही अन्य उपभोक्ता सामग्री को को पैक करने के काम आता है ने हीं, जल और थल को अपने पुनः प्रयोग ना हो पाने के कारण ढक दिया है । निसंदेह सारे पेट्रो प्रोडक्ट न हीं वर्तमान में सबसे ज्यादा दुनिया को परेशान कर रखा है जिसके कारण समुद्र से लेकर धरती तक, राम सामान्य जीव जंतुओं को वनस्पतियों को अपने जीवन निर्वाह में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर यह सब मानव की ही आधुनिकता, शीघ्रता का हीं तो परिणाम है जिसने पृथ्वी पर और उसके वायुमंडल को प्रदूषित कर पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग की जाने वाली पेट्रोल डीजल और गैस जो कि धरती से प्राप्त जी जीवाश्म ईंधन का ही अंश है इसके उपयोग से निकलने वाले धुये जिसमें अनेकों प्रकार की अन्य गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, गैसों की प्रचुरता ने पृथ्वी के वायुमंडल का ऑक्सीजन और उसकी ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचाया और पहुंचा रही है। साथ ही ठोस प्लास्टिक की बोतलें पैकिंग पॉलीथिन की थैलियां, नालियों से लेकर सभी जलस्त्रोतों के साथ धरती पर फैल कर कर वनस्पतियों, जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया को अब इसकी चिंता सताने लगी है पर यह चिंता खोखली और दिखाऊं है क्योंकि जो कंपनियां इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वे ही ज्यादा हल्ला मचाती है जबकि स्वयं अपने उत्पादन कभी बंद नहीं करती जो की अधिकांश अमेरिका और यूरोप की है इनकी देखादेखी एशिया महाद्वीप के देशों में भी इस जीवाश्म इंधन के उपयोग की गति अधिक तेज गति से बढ़ रही है जिसमें बाइक्स कारें ट्रक बसें, वायुयान, जलपोतों जिस जीवाश्म इंधन जो की पेट्रोल डीजल के रूप में उपयोग करते हैं यह सभी यथार्थ में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। **(शेष पेज 15 पर)**

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर। मोबा. 9425125569, 9479535569